2017

विदेश नीति की समीक्षा

विदेशी मामलों के क्षेत्र में हुए विकास पर वार्षिक रिपोर्ट

विश्व मामलों की भारतीय परिषद

सप्रू हाउस, बाराखंभा रोड

नई दिल्ली -110070

www.icwa.in

विदेश नीति की समीक्षा 2017

विदेशी मामलों के क्षेत्र में हुए विकास पर वार्षिक रिपोर्ट

अनुसंधान संकाय, विश्व मामलों की भारतीय परिषद,
नई दिल्ली
द्वारा तैयार किया गया

विश्व मामलों की भारतीय परिषद (आई.सी.डब्ल्यू.ए.) भारत की सबसे प्राचीन विदेश नीति थिंक टैंक है, जो विदेश तथा सुरक्षा नीति के मुद्दों में विशेषज्ञता रखती है। यह भारत के स्वतंत्रता से पहले 1943 में भारत के पहले प्रधानमंत्री, जवाहरलाल नेहरू की प्रेरणा के तहत प्रख्यात बुद्धिजीवियों के एक समूह द्वारा स्थापित किया गया था। 2001 में संसद के अधिनियम द्वारा विश्व मामलों की भारतीय परिषद को "राष्ट्रीय महत्व का संस्थान" घोषित किया गया है।

परिषद अपने आंतरिक संकाय के साथ-साथ बाहरी विशेषज्ञों के माध्यम से नीति अनुसंधान का संचालन करती है। यह नियमित रूप से सम्मेलनों, सेमिनारों, गोलमेज चर्चाओं, व्याख्यान तथा प्रकाशन सहित बौद्धिक गतिविधियों की श्रृंखला का आयोजन करती है। यह एक ऐतिहासिक तथा अच्छी तरह से स्थापित लाइब्रेरी, वेबसाइट और 'इंडिया क्वार्टरली' नामक पत्रिका का अनुरक्षण करती है। यह अंतर्राष्ट्रीय मामलों में भारत की भूमिका और सरकार तथा नागरिक समाज नीति मॉडल व रणनीतियों के लिए सार्वजनिक जागरूकता बढ़ाने के कार्य में संलग्न है, और अन्य विदेशी थिंक टैंक के साथ कई दौर के संवाद तथा बातचीत हेतु एक मंच के रूप में कार्य करती है।

विषय-सूची

अध्यायपृष्ठ सं.

1. दक्षिण एशिया 5

2. दक्षिण पूर्व / पूर्व एशिया / सुदूर पूर्व 19

3. मध्य एशिया 30

4. पश्चिम एशिया 35

5. अफ्रीका (उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम और उप-सहारा अफ्रीका)47

6. हिंद महासागर द्वीप राज्यो 61

7. लैटिन अमेरिका और कैरेबियन 65

8. उत्तरी अमेरिका 68

9. प्रमुख शक्तियाँ 72

10. बहुपक्षीय और अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक विकास 82

योगदानकर्ताओं की सूची 87

स्रोत

विदेश नीति की समीक्षा 2017 में दी गई जानकारी निम्नलिखित वेबसाइटों से ली गई है:

1. विदेश मंत्रालय
2. वाणिज्य मंत्रालय
3. वित्त मंत्रालय
4. राष्ट्रपति कार्यालय
5. उपराष्ट्रपति कार्यालय
6. प्रधानमंत्री कार्यालय
7. औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग (डीआईपीपी)
8. प्रेस सूचना ब्यूरो
9. विभिन्न समाचार और मीडिया घरानों की वेबसाइट

दक्षिण एशिया

1. दक्षिण एशिया

वर्ष 2017 में दक्षिण एशिया के देशों में कई राजनीतिक, रणनीतिक, सुरक्षा और आर्थिक विकास हुए। सामरिक मोर्चे परभूटान को चीनी सैनिकों द्वारा अपने क्षेत्र में जबरदस्त आक्रमण की वजह सेरणनीतिक संकट की स्थिति का सामना करना पड़ाथा। चीनी पोस्ट की घुसपैठडोकलाम पठार पर अवैध रूप से सड़क बनाने हेतु शुरू की गई। भूटानी सरकार के अनुरोध परभारतीय सैनिकों ने विवादित क्षेत्र में प्रवेश किया, जिसकी वजह से 74 दिनों तक गतिरोध बना रहा। हालांकि, दोनों देशों के पीछे हटने के बाद यह गतिरोध खत्म हो गया। राजनीतिक और सुरक्षा के मोर्चे परदेश में चुनाव करते हुए नेपाल ने अपने घरेलू राजनीतिक अवस्था के भीतर नए राजनीतिक समरूपता की लड़ाई लड़ी। अफगानिस्तान को काबुल में और उसके आसपास कई आतंकवादी हमलों का समाना करना पड़ा। काबुल में 31 मई को हुए आतंकवादी हमले में 150 से अधिक लोग मारे गए थे तथा 500 से अधिक घायल हुए थे। हालांकि देश मास्को, काबुल और कई अन्य मंचों से मिला, लेकिन फिर भी शांति की प्रक्रिया धीमी थी। तालिबान ने इस लाभ उठाया और शांति प्रक्रिया में एक प्रमुख रणनीतिक खिलाड़ी के रूप में उभरा। मालदीव राजनीतिक उदासी के दौर से गुज़रा। पाकिस्तान ने निर्वाचित प्रधानमंत्री को हटाने, न्यायिक सक्रियता बढ़ाने और लोकतांत्रिक परंपराओं तथा संस्कृति को दुर्बल होने जैसे समस्याओं का सामना किया। बांग्लादेश को रोहिंग्या शरणार्थियों की आमद के साथ मानवीय तथा सुरक्षा चुनौतियों का सामना करना पड़ा, जो म्यांमार में हिंसा की वजह से छोड़कर भाग आए थे। भारत और पाकिस्तान के बीच राजनीतिक तनाव के कारण सार्क निष्क्रिय बना रहा। बांग्लादेश भूटान भारत नेपाल मोटर व्हीकल एग्रीमेंट (बीबीआईएन-एमवीए) की उप-क्षेत्रीय पहल भी अवरोध हो गई दिया, क्योंकि भूटान 2018 में अपने होने वाले राष्ट्रीय चुनावों के बाद ही इस समझौते पर निर्णय ले पायेगा। अन्य तीन देशों ने समझौते की पुष्टि की है। आर्थिक विकास के संबंध में भारत, बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका ने 7.0 [भारत], 7.2 [बांग्लादेश], 6.9] [नेपाल] और 4.5 [श्रीलंका] की सतत विकास दर हासिल करने की दिशा पर लगातार काम किया है।[1]

1.1अफ़ग़ानिस्तान

वर्ष 2017 अफगानिस्तान के लिए चुनौती भरासाल रहा। शांति बहाल करने हेतु प्रयास किएगए, जहां रूस, चीन और पाकिस्तान सहित कई देशों ने इसमें अग्रणी भूमिका निभाई। उन्होंने कहा कि शांति प्रक्रिया में तालिबान एक महत्वपूर्ण कारक बना रहा और यहां स्थायी शांति स्थापित करने हेतुभागीदार बनाया जाना चाहिए। इस तरह की टिप्पणी की अफगान संसद के निचले सदन ने आलोचना की थी।[2] बातचीत के दूसरे दौर मेंभारत और ईरान के साथ अफगानिस्तान ने काबुल में हुई वार्ता में भाग लिया।[3]

1The other growth rates are Afghanistan - 2.5, Bhutan - 6.9 and Maldives - 4.2, as per the Asian Development Bank, https://www.adb.org/countriesas accessed on March 28, 2018

2"Taliban Welcomes Moscow Talks", Tolonews, 01 January 2017. URL: http://www.tolonews.com/afghanistan/taliban-welcomes-moscow-talksaccessed on 02 January 2017.

3"Six Nations To Meet In Moscow Over Afghanistan", Tolonews, 11 February 2017. URL: http://www.tolonews.com/afghanistan/six-nations-meet-moscow-over-afghanistanaccessed on 13 February 2017.

एक अन्य प्रमुख राजनीतिक विकास हिज्ब-ए-इस्लामी नेता गुलबुद्दीन हिकमतयार की अफगानिस्तान में वापसी थी, जिन्होंने 2016 में अफगान सरकार के साथ शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए थे।[4] आगे यह भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने अगस्त 2017 में अपनी अफगान रणनीति घोषित की थी, जिसमें उन्होंने अफगान सरकार के एक प्रमुख भागीदार के रूप में अपनी स्थायी प्रतिबद्धता दिखाई थी। उन्होंने अफगान शांति प्रक्रिया में भारत को एक बड़ी भूमिका निभाने के लिए भी कहा था।[5] अमेरिकी कांग्रेस ने हक्कानी आतंकवादी नेटवर्क पर अंकुश लगाने में विफल रहने के कारण पाकिस्तान को गठबंधन सहायता कोष से मिलने वाले पैसे पर अंकुश लगाने हेतु एक बिल पास करके पाकिस्तान पर कड़ा रुख अपनाया।[6]

अफगानिस्तान को अक्टूबर 2017 में एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक (एआईआईबी) की स्थायी सदस्यता मिल गई, जिससे ढांचागत विकास हेतु सहायता प्राप्त करने का एक बड़ा अवसर खुल गया।[7] काबुल में नाटो के नेतृत्व वाले संकल्प मिशन द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार, 2017 अगस्त में अफगानिस्तान वायु सेना ने कार्बनिक खुफिया टोही क्षमता हासिल की, और अफगान रक्षा मशीनरी के अन्य खंडों की क्षमताओं का विस्तार करने के प्रयास जारी थे।[8] अगस्त 2017 कोअमेरिकी सेना ने अफगानिस्तान में लगभग 3,000 अधिक सैनिकों को भेजा, जो अफगानिस्तान में पहले से ही तैनात 11,000 सैनिकों में शामिल हो जाएंगे।[9]

भारत के साथ द्विपक्षीय संबंध

काबुल से दिल्ली हवाई अड्डे तक उड़ान भरने के साथ जून 2017 कोहवाई माल ढुलाई गलियारे (एयर कार्गो कॉरीडोर) की उद्घाटन किया गया था,जिससे व्यापार योग्य वस्तुओं को ले जायाजाएगा। इस समर्पित हवाई माल ढुलाई गलियारे (एयर कार्गो कॉरीडोर)की योजना प्रधानमंत्री मोदी की सितंबर 2016 की काबुल यात्रा के दौरान बनाई गई थी।[10]11 सितंबर, 2017 को नई दिल्ली में भारत और अफगानिस्तान के बीच दूसरी रणनीतिक भागीदारी परिषद की बैठक में एक संयुक्त वक्तव्य जारी किया गया था।रणनीतिक भागीदारी परिषद ने पारस्परिक हितों के द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचारों साझा किए और उन पर विचारों का अभिसरण किया। राजनीतिक तथा सुरक्षा मुद्दों के क्षेत्रों में चार संयुक्त कार्य समूहों के परिणामों; व्यापार, वाणिज्य तथा निवेश; विकास सहयोग; और मानव संसाधन विकास, शिक्षा और संस्कृति की समीक्षा की गई और इनका सकारात्मक रूप से मूल्यांकन किया गया।

4Tamim Hamid, "Hekmatyar's Return Met With Mixed Reaction", Tolonews, 29 April 2017. http://www.tolonews.com/afghanistan/hekmatvar%E2%80%99s-retum-met-mixed-reactionaccessed on 01 May 2017.

5"Trump Unveils Long-Awaited Afghan Strategy", Tolonews, 22 August 2017. https://www.tolonews.com/index.php/afghanistan/trump-unveils-long-awaited-afghan-strategyaccessed on 22 August 2017.

6"US congress passes new bill regarding Pakistan and Haqqani network", Khaama Press, 19 November 2017. http://www.khaama.com/us-congress-passes-new-bill-regarding-pakistan-and-haaaani-network-03877accessed on 20 November 2017.

7 "Afghanistan Gets Permanent Membership of AIIB", Tolonews, 15 October 2017. https://www.tolonews.com/index.php/business/afghanistan-gets-permanent-membership-aiibaccessed on 15 October2017.

8"Afghan Air Force to get organic intelligence reconnaissance capability for the first time", Khaama Press, 20 August 2017.http://www.khaama.com/afghan-air-force-to-get-organic-intelligence-reconnaissance-capability-for-the-first-time-03395accessed on 21 August 2017.
9 "US Defense Secretary Orders New Troop Deployment to Afghanistan", Outlook Afghanistan, 04 September 2017. http://www.outlookafghanistan.net/nationaldetail.php?post id=18931accessed on 04 September 2017.
10KallolBhattacheijee, "India, Afghanistan open air freight route", The Hindu, 19 June 2017. http://www.thehindu.com/news/national/india-afghanistan-open-air-freight-route/article19104598ece accessed on 19 June 2017.

एक बहुपक्षीय मंच पर श्री एम.जे. अकबर, विदेश राज्य मंत्री 1 दिसंबर, 2017 को हार्ट ऑफ एशिया - इस्तांबुल प्रक्रिया के मंत्रिस्तरीय सम्मेलन में भाग लेने के लिए बाकू, अजरबैजान गए थे। अफगानिस्तान, भारत और ईरान के बीच अंतर्राष्ट्रीय परिवहन तथा पारगमन गलियारे की स्थापना पर त्रिपक्षीय समझौते के कार्यान्वयन पर चर्चा करने हेतुदूसरी मंत्री स्तरीय स्तरीय त्रिपक्षीय बैठक 3 दिसंबर, 2017 को चाबहार, ईरान में आयोजित की गई थी, जहां चाबहार पोर्ट के पहले चरण का उद्घाटन किया गया था।

आतंकवाद और आतंकवाद का मुकाबला

अफगानिस्तान में सुरक्षा की स्थिति

वर्ष 2017 में तालिबान द्वारा जमीन हासिल करने और इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासान प्रांत (आईएसकेपी), इस्लामिक स्टेट (जिसे आईएसआईएस के नाम से भी जाना जाता है) के अफगान ठिकाने, अपने ऑपरेशन के मुख्य क्षेत्र में खुद को मजबूत करने और पड़ोसी क्षेत्रों में और विस्तार करने की वजह से अफगानिस्तान में सुरक्षा की स्थिति खराब हो गई। 2017 के दौरान तालिबान द्वारा आतंकवादी हमले तेज हो गए।नंगरहार प्रांत में आईएसकेपी की बढ़ती उपस्थिति और कुनार तथा अन्य प्रांतों में विस्तार करना देश में बढ़ती असुरक्षा का एक अन्य संकेत था। संघर्ष में वृद्धि, अफीम उत्पादन और मादक पदार्थों की तस्करी जैसे संगठित अपराधों के साथ, संघर्ष-प्रेरित विस्थापन के उच्च स्तर का कारण बना। अपनी 31 दिसंबर, 2017 की रिपोर्ट में, संयुक्त राष्ट्र के मानवीय मामलों के समन्वय कार्यालय (यूएनओसीएचए) ने बताया कि पिछले 18 महीनों में 2017 में प्रति दिन 1,100 की औसत दर से लगभग एक लाख अफगान आंतरिक रूप से विस्थापित हो गए थे - उनमें से दो तिहाई महिलाएं और बच्चे थे। विस्थापन का मुद्दा पड़ोसी देशों - पाकिस्तान और ईरान से लौटने वाले शरणार्थियों के कारण और अधिक जटिल हो गया है।

2017 में अफगानिस्तान की सुरक्षा स्थिति का जायजा हेतु हुए वार्षिक रिपोर्ट का यह खंड अफगानिस्तान में आतंक और संगठित अपराध पर युद्ध के विषय पर प्रमुख अंतरराष्ट्रीय रिपोर्टों को संकलित करके इस मुद्दे पर एक अवलोकन प्रदान करेगा।

यूएनएएमए - त्रैमासिक रिपोर्ट, अक्टूबर 2017

अफगानिस्तान में संयुक्त राष्ट्र सहायता मिशन (यूएनएएमए) ने सशस्त्र संघर्ष में नागरिकों की सुरक्षा पर अपनी अंतिम जारी त्रैमासिक रिपोर्ट (जनवरी - सितंबर 2017) में नागरिकों की नुकसान से रक्षा

के प्रयासों को तेज करने हेतु संघर्ष का आग्रह किया, जैसा कि रिपोर्ट में डेटा में जारी किया गया है कि8,019 नागरिक हताहत हुए, 2,640 मौतें हुई और 5,379 घायल हुए।

ह्यूमन राइट्स वॉच (एचआरडब्ल्यू), कंट्री चैप्टर - अफगानिस्तान, 2017 का कार्यक्रम

यूएनएएमएद्वारा उपलब्ध कराए गए नागरिक हताहतों के आंकड़ों पर भरोसा करते हुए, एचआरडब्ल्यू की रिपोर्ट, 2017 के दौरान अफगान सरकार और तालिबान बलों के बीच लड़ाई तेज हो गई। जमीनी लड़ाई के दौरान सरकारी बलों की वजह से नागरिक हताहतों की संख्या में कमी आई; हालांकि, अमेरिकी सेनाओं ने सैन्य अभियानों में ड्रोन सहित हवाई जहाजों के अपने उपयोग को बढ़ाया। एचआरडब्ल्यूकीरिपोर्टकेअनुसार, आंतरिक रूप से विस्थापित व्यक्तियों (आईडीपी) की संख्या, जो संघर्ष के कारण अपने घरों से भाग गए थे, तेज हो गए थे। 2017 के पहले 10 महीनों में 250,000 से अधिक लोग विस्थापित हुए, जिसमें राष्ट्रव्यापी स्तर पर कुल लगभग 1.7 मिलियन लोग आए।

रक्षा विभाग (डीओडी), अफगानिस्तान में सुरक्षा और स्थिरता में वृद्धि, दिसंबर 2017

सुरक्षा स्थिति परकांग्रेस को सौंपी गई अपनी अर्ध-वार्षिक रिपोर्ट में डीओडीने कहा कि अफगानिस्तान को बाहरी रूप से सक्षम और लचीले विद्रोह का सामना करना पड़ा। इसमें बताया गया है कि अफगान सरकार ने लगभग 60 प्रतिशत आबादी पर नियंत्रण या प्रभाव बनाए रखा, जबकिशेष बचे हुए लोगों के साथ विद्रोहियों का लगभग 10 प्रतिशत आबादी पर नियंत्रण या प्रभाव था। 20 से अधिक आतंकवादी संगठनों की उपस्थिति दुनिया में आतंकवादी और चरमपंथी संगठनों की सबसे बड़ी एकजुटता है।

यूएनजीएसुरक्षा परिषद, 15 दिसंबर, 2017

15 नवंबर तक, संयुक्त राष्ट्र ने 2017 के पहले 11 महीनों में 21,105 से अधिक सुरक्षा संबंधी घटनाएं दर्ज की गई थी, जिसमें 2016 के बाद से 1 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। निरंतर बढ़ती घटनाओं का मुख्य कारण सशस्त्र संघर्ष को ठहराया जाता है। पूर्वी क्षेत्र में सबसे अधिक ऐसी घटनाएंहुई, इसके बाद दक्षिणी क्षेत्र में,जिनमें दो क्षेत्रों में 56 प्रतिशत घटनाएंहुई थी।

तालिबान ने जिला प्रशासन केंद्रों पर कब्जा करने हेतु बड़े पैमाने पर कईअभियान चलाए, जिसमें अस्थायी रूप से कंधार प्रांत के मारूफ़, ग़ज़नी प्रांत के अंडार, फराह प्रांत के शिब कोह और उरोज़ प्रांत के शाहिद-ए-हसस पर कब्जा कर लिया गया। हालांकि, अफगान सुरक्षा बलों ने अंतरराष्ट्रीय सैन्य हवाई समर्थन के साथ तालिबान और ओसमे मामलों में पीछे धकेल दिया। साथ ही, तालिबान ने देश में कई जटिल हमले किए।

आईएस लचीले बना रहा और नागरिकों तथा सैन्य लक्ष्यों दोनों के खिलाफ कई हमलों की जिम्मेदारी ली।

भारत के साथ सुरक्षा संबंधी द्विपक्षीय संबंध

अफगानिस्तान और भारत के बीच द्विपक्षीय संबंध सुरक्षा से संबंधित मुद्दों पर जोर देने के साथ तेज हुए। 12 सितंबर, 2017 को "नई विकास साझेदारी" की शुरुआत, और 28 सितंबर, 2017 को

पुलिस प्रशिक्षण तथा विकास पर तकनीकी सहयोग के समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर के साथ अफगानिस्तान और भारत ने अपने द्विपक्षीय संबंधों का विस्तार किया।

1.2 बांग्लादेश

वर्ष 2017 में शेख हसीना के नेतृत्व वाली अवामी लीग और खालिदा जिया के नेतृत्व वाली बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) के बीच देश में बढ़ती राजनीतिक खींचतान देखी गई। वर्ष की शुरुआत से, बीएनपी ने सरकार को पार्टी की कुछ चुनाव संबंधी मांगों को स्वीकार करने हेतु प्रेरित किया ताकि वह आगामी आम चुनावों में अपनी भागीदारी की घोषणा कर सके। इस तरह की एक मांग स्वतंत्र, निष्पक्ष और समावेशी आम चुनाव सुनिश्चित करने हेतु निष्पक्ष चुनाव-समय की कार्यवाहक सरकार की स्थापना की रही। पार्टी ने कहा कि बीएनपी की भागीदारी के बिना देश में कोई विश्वसनीय चुनाव नहीं होगा। सत्तारूढ़ प्रणाली ने इन मांगों को स्वीकार नहीं किया और यह स्पष्ट कर दिया कि वो एक समावेशी चुनाव चाहते हैं और समावेशी चुनाव सुनिश्चित करने हेतु सब कुछ निर्धारित संवैधानिक सीमाओं तथादेश के कानूनों के तहत करता है।

चीन के साथ बांग्लादेश के संबंध अच्छे हुए हैं। जारी आर्थिक सहयोग के अलावा, दोनों देशों ने रक्षा सहित अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सहयोग का विस्तार किया है। देश की नौसेना की क्षमताओं और रक्षा प्रणाली को उन्नत करने हेतु चीन से दो पनडुब्बियों- बीएनएस नबजात्रा और बीएनएस अग्रोजात्रा की खरीद की गई। अक्टूबर 2017 मेंदोनों देशों ने चीनी सहायता की मदद से 220 किलोमीटर तेल पाइपलाइन बनाने हेतु एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। समझौते के अनुसार, चीनी एक्जिम बैंक अगले 20 वर्षों में 2 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर के साथ चुकाए जाने वाले ऋण के रूप में धन प्रदान करेगा।

बढ़ते रोहिंग्या संकट के मद्देनजर म्यांमार के साथ बांग्लादेश के संबंध बिगड़ते और ऐतिहासिक रुप से कमजोर होते गए। यह ध्यान देने योग्य है कि म्यांमार बीजीपी के पोस्टों और सेना के आधार पर अराकान रोहिंग्या सैल्वेशन आर्मी (एआरएसए) के हमले के बाद, राखाइन प्रांत में स्थिति खराब हो गई जिसमें रोहिंग्याओं की सबसे बड़ी संख्या रहती थी। हिंसा से बचने के लिएबड़ी संख्या में लोग राखीन में अपने घरों से भाग गए और पड़ोसी बांग्लादेश में शरण लेने हेतु सीमा पार कर गए। बांग्लादेश ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से म्यांमार पर मानवाधिकारों के उल्लंघन को रोकने और अपने नागरिकों को वापस लेने हेतु दबाव बनाने का आहवानकिया। मानवीयता दिखाते हुएबांग्लादेश ने म्यांमार के लोगों को अस्थायी रूप से मेक-शिफ्ट शिविरों में रहने की अनुमति दी और यह स्पष्ट कर दिया कि एक बार स्थिति स्थिर हो जाने के बाद उन्हें अपने देश वापस जाना होगा। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने म्यांमार में रोहिंग्या के प्रोशोधन के प्रति अपनी नाराजगी व्यक्त की और संयुक्त राष्ट्र, यूरोपीय संघ और ओआईसी जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने हिंसा के फैलने की निंदा की। यूएनएचसीआर ने इसे जातीय सफाई का एक उदाहरण करार दिया। संकट और बड़े पैमाने पर बांग्लादेश में जबरन प्रवास पर

म्यांमार की प्रतिक्रिया पर गंभीर अंतर्राष्ट्रीय आलोचना के तहत, दोनों देशों ने संवाद शुरु किया, जिसके परिणामस्वरूप नवंबर 2017 में समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए।[11]

भारत-बांग्लादेश द्विपक्षीय संबंध

दोनों पक्षों के कई उच्च स्तरीय दौरे हुए, जिसने दोनों देशों के बीच मित्रता के बंधन को मजबूत किया। फरवरी में, भारत के तत्कालीन विदेश सचिव डॉ. एस. जयशंकर ने ढाका का दौरा किया और भारत तथा बंग्लादेश के बीच द्विपक्षीय सहयोग के क्षेत्र की समीक्षा की। दोनों पक्षों ने हाल ही में सुरक्षा तथा सीमा प्रबंधन, व्यापार एवं वाणिज्य, बिजली, ऊर्जा, शिपिंग, रेलवे आदि क्षेत्रों में विभिन्न द्विपक्षीय तंत्रों की बैठकों के दौरान लिए गए निर्णयों का जायजा लिया।[12]

[11] "Bangladesh and Myanmar conclude 'Arrangement' on Return of displaced persons from Rakhine state," November 23, 2017, available at http://www.mofa.gov.bd/media/bangladesh-and-myanmarconclude-'arrangement'-return-displaced-persons-rakhine-state-11

अप्रैल में, बांग्लादेशी प्रधानमंत्री शेख हसीना ने भारत की चार दिवसीय राज्य यात्रा की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों की व्यापक समीक्षा की। हसीना ने उन भारतीय शहीदों को सार्वजनिक रूप से सम्मानित किया, जिन्होंने 1971 में बांग्लादेश मुक्ति के लिए मुक्तिबाहिनी के साथ संघर्ष किया था। भारत ने इस अच्छे कदम पर प्रतिक्रिया दी और बांग्लादेश के संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान की याद में दिल्ली में एक सड़क का नाम रखा।

दोनों देशों ने 11 समझौतों, 24 समझौता ज्ञापनों और दो एसओपी पर हस्ताक्षर किए। ग्यारह अनुबंधित समझौतों में से चार बिजली क्षेत्र से संबंधित हैं, तीन परमाणु क्षेत्र में सहयोग की श्रेणी में आते हैं, जो शांतिपूर्ण उद्देश्यों हेतु कड़ाई से प्रतिबंधित है, और एक-एक मोटर वाहन यात्री यातायात, बांग्लादेश में छत्तीस सामुदायिक क्लीनिकों का निर्माण, और दृश्य-श्रव्य सह-उत्पादन, पेट्रो-रिफाइनरी सहयोग के नियमन से संबंधित है। दोनों देशों ने रक्षा सहयोग ढांचे पर भी सहमतिदर्शाई। रक्षा क्षेत्र में चार समझौता ज्ञापनों में से एक, विशेष रूप से रक्षा क्षेत्र में सहयोग पर है। इन समझौता ज्ञापनों के तहत, भारत ने बांग्लादेश को 500 मिलियन डॉलर की रक्षा लाइन का विस्तार किया, जिसका उपयोग भारत से रक्षा उपकरणों की खरीद हेतु किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, भारत ने बुनियादी ढांचा विकास कनेक्टिविटी परियोजनाओंके लिए बंगलेश को 4.5 बिलियन डॉलर का ऋण भी दिया।[13]

मानवीय संकट के मद्देनजर, भारत बांग्लादेश को सहायता पहुंचने वाले पहले देशों में से था। कुछ ही समय के भीतर, सरकार ने संकट से निपटने हेतु राहत सामग्री से बांग्लादेश की मदद के लिए ऑपरेशन इन्सानियत शुरू करने का फैसला किया।[14] भारत-बांग्लादेश संयुक्त सलाहकार आयोग की चौथी बैठक की अध्यक्षता करने के लिए भारतीय विदेश मंत्री सुश्री सुषमा स्वराज ने अक्टूबर 2017 में बांग्लादेश का दौरा किया।[15] नवंबर, 2017 में दोनों देशों ने कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स की औपचारिक

शुरुआत की, जिसमें दूसरा भैरब और टिटास रेलवे ब्रिज, और कोलकाता के चितपुर में इंटरनेशनल रेल पैसेंजर टर्मिनस शामिल हैं। भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, बांग्लादेशी प्रधानमंत्री शेख हसीना और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इस शुभारंभ समारोह में उपस्थित थे। गणमान्य लोगों ने कोलकाता और खुलना के बीच बंधन एक्सप्रेस का उद्घाटन किया।[16]

12 MEA Press Release on Visit of Foreign Secretary of India Dr. S Jaishankar to Bangladesh, February 23, 2017, available at http://mea.gov.in/pressreleases.htm?dtl/28096/Visit+of+Foreign+Secretary+of+India+Dr+S+Jaishankar+to+Bangladesh+February+2324+2017

13 India-Bangladesh joint statement during the state visit of Prime Minister of Bangladesh to India, April 8, 2017, available at http://www.mea.gov.in/bilateraldocuments.htm?dtl/28362/India++Bangladesh+Joint+Statement+during+the+State+Visit+of+Prime+Minister+o f+Bangladesh+to+India+April+8+2017

14 MEA press release on "Operation Insaniyat—Humanitarian assistance to Bangladesh on account of influx of refugees," available at http://mea.gov.in/pressreleases.htm?dtl/28944/Operation_Insaniyat__Humanitarian_assistance_to_Bangladesh_on_account_of_influx_of_refugees

15 MEA Press Release on Visit of External Affairs Minister of India to Bangladesh, available at http://www.mea.gov.in/pressreleases.htm?dtl/29038/Visit_of_External_Affairs_Minister_of_India_to_Bangladesh_October_2223_2017

1.3 नेपाल

वर्ष 2017 नेपाल के लिए चुनावी वर्ष के रूप में याद किया जाएगा क्योंकि तीन महत्वपूर्ण स्थानीय, प्रांतीय और संघीय चुनाव सफलतापूर्वक संपन्न हुए थे। जून 2017 में, नेपाली कांग्रेस के अध्यक्ष शेर बहादुर देउबा को रिकॉर्ड चौथे कार्यकाल के लिए नेपाल के प्रधानमंत्री के रूप में निर्वाचित होने के बाद, नेपाल में राजनीतिक परिवर्तन देखा गया, जब प्रचंड ने जून 2017 में सत्ता साझाकरण समझौते के तहत इस दिग्गज नेता को शासन सौंपा। नवंबर-दिसंबर 2017 में प्रांतीय और संघीय चुनाव, माओवादी केंद्र और सीपीएन- यूएमएल ने विलय के बाद भविष्य में एकल कम्युनिस्ट पार्टी के जन्म की घोषणा करते हुए प्रांतीय तथा संघीय चुनावों के लिए गठबंधन की घोषणा की। हालांकि यहां यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि माओवादी केंद्र पहले से ही संघीय सरकार में सत्तारूढ़ पार्टी नेपाली कांग्रेस के साथ गठबंधन में था। सीपीएन-यूएमएल नेपाली कांग्रेस के विपक्ष में था और माओवादी केंद्र नोसीपीएन-यूएमएल (चुनाव उद्देश्यों के लिए) के साथ गठबंधन लिया, जिसका पहले से ही नेपाली कांग्रेस (संघीय सरकार का हिस्सा होने के साथ) के साथ गठबंधन था।

नेपाल ने मई, जुलाई और सितंबर में तीन चरणों में 6 महानगरीय शहरों, 11 उप-महानगरीय शहरों, 276 नगर पालिकाओं और 460 ग्रामीण नगरपालिकाओं में स्थानीय निकाय चुनाव आयोजित किए।

सीपीएन (यूएमएल) इन चुनावों के दौरान सबसे बड़े राजनीतिक दल के रूप में उभरा। नेपाली कांग्रेस दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बन गई। सीपीएन (माओवादी केन्द्र) इन चुनावों के दौरान से तीसरे स्थान पर रहा।[17] 2017 में, भारत की सीमा से लगे नेपाल के तराई मैदानों का प्रतिनिधित्व करने वाली मधेश-आधारित क्षेत्रीय पार्टियों ने चुनावों में भाग लिया।

भारत नेपाल द्विपक्षीय संबंध

अप्रैल 2017 में राष्ट्रपति बिध्या देवी भंडारी ने नई दिल्ली की अपनी पहली यात्रा की। यात्रा के दौरान, भंडारी ने राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से मुलाकात की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं पर चर्चा की।

भारतीय विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज ने जुलाई 2017 में बिम्सटेक (बंगाल की खाड़ी बहु-क्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग उपक्रम) की बैठक में भाग लेने के लिए नेपाल का दौरा किया।[18]प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा की अगस्त 2017 की भारत यात्रा के दौरान भारत और नेपाल ने आठ समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए।[19]इनमें से ज्यादातर विकास, भूकंप पुनर्वास, कनेक्टिविटी और ऊर्जा के क्षेत्रों में हस्ताक्षर किए गए।यात्रा के दौरान, पीएम देउबा ने भारतीय अधिकारियों के साथ पंचेश्वर बहुउद्देशीय परियोजना की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट को पूरा करने के बारे में भी चर्चा की। उन्होंने भारत से नेपाल में अधिक आर्थिक विकासात्मक सहायता और निवेश का भी आह्वान किया।

16 Press release on “Joint launch of connectivity projects between India and Bangladesh,” available at http://mea.gov.in/pressreleases.htm?dtl/29101/Joint+Launch+of+Connectivity+Projects+Between+India+and+Bangladesh+November +09+2017

17 "Federal Parliament and Provincial Assembly Election 2017", My Republica, 20 December 2017, http://election.nagariknews.com/federal-election-2074-nepal/candidates?lang=ENG

18 "Sushmaswaraj to attend Bimestec meeting in Nepal", Business Standard, 4 August 2017, http://www.business-standard.com/article/news-ians/sushma-swaraj-to-attend-bimstec-meeting-in-nepal117080401237_1.html

19 "PM Deuba returns home after 5 days India visit", The Kathmandu Post, 27 August 2017, http://kathmandupost.ekantipur.com/news/2017-08-27/pm-deuba-returning-home-tonight.html

1.4 पाकिस्तान

पाकिस्तान में राजनैतिक, सामाजिक और आर्थिक रूप से 2017 में उतार-चढ़ाव का अनुभव किया गया।देश को एक बेहद चुनौतीपूर्ण विदेश नीति परिदृश्य से भी गुजरना पड़ा। राजनीतिक रूप सेइस वर्ष में नागरिक और सैन्य नेतृत्व के बीच दरार बढ़ती हुई देखी गई। जांच पर नियंत्रण रखने हेतु सेना के सदस्यों को संयुक्त जांच दल में शामिल किया गया था।पाकिस्तान के संविधान में अनुच्छेद 62 के अनुसार सादिक (सत्यवादी) और अमीन (ईमानदार) नहीं होने की वजह से यह 28 जुलाई, 2017 को न्यायपालिका द्वारा प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की बर्खास्तगी के रूप में खत्म हुआ।[20]

नवाज शरीफ की बर्खास्तगी को लेकरचुने गए राजनीतिक नेता, प्रधानमंत्री शाहिद खाकान अब्बासी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग (नवाज़) (पीएमएल (एन)) के सदस्यों के बीच दरार देखी गई।

अहमदीस[21], ईसाई, जातीय बलूचियों और पख्तूनों, हिंदुओं और साथ ही शियाओं के उत्पीड़न सहित2017 के दौरान पाकिस्तान मेंधार्मिक अल्पसंख्यकों के उत्पीड़न की घटनाएं होती रही।

आर्थिक रूप से, विश्व बैंक के एक वर्ष में दो बार पाकिस्तान विकास अद्यतन में रेखांकित किया गया कि 2017 के वित्तीय वर्ष में देश की आर्थिक विकास दर 5.3 प्रतिशत हो गई है।[22] स्कूल की भागीदारी दर और स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच जैसे मानव विकास संकेतकों में कुछ सुधार हुआ।[23]

चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे (सीपीईसी) ने कुछ परियोजनाओं में प्रगति की और साथ ही कईयों को विभिन्न कानूनी, तार्किक और वित्तीय बाधाओं का सामना करना पड़ा। न तो चीन और न ही पाकिस्तानी सरकार ने सीपीईसीदीर्घकालिक योजना को सार्वजनिक किया। सीपीईसीमें शामिल होने के लिए ईरान ने अपनी रुचि दिखाई।[24] पूरे साल पाकिस्तानी न्यायपालिका द्वारा न्यायिक सक्रियता दिखाई गई। जून 2017 में दो चीनी नागरिकों के अपहरण और बाद में हत्या ने चीन तथा पाकिस्तानी प्रशासन के बीच कुछ तनाव भी पैदा कर दिए।

तत्कालीन सेना प्रमुख राहील शरीफ को अप्रैल 2017 में सऊदी नेतृत्व वाले सैन्य गठबंधन का नेतृत्व करने हेतु अनापत्ति प्रमाणपत्र प्रदान किया गया था। पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल बाजवा ने 2017 में पाकिस्तानी संसद में गवाही दी कि यह एक ऐसी संस्था है जिसे निर्वाचित प्रतिनिधि द्वारा निर्देशित किया जाना चाहिए, और संसद से अनुरोध किया कि वह राजनीतिक शून्यता पैदा न करे।[25]

20Mohsin Raza Malik, "On 'Sadiq' and 'Ameen", The Nation, June 29, 2017, https://nation.com.pk/29-Jun-2017/on-sadiq -and-ameenaccessed on February 20, 2018
21Kalbe Ali, "Senate body to approach FO for complaint against Canadian citizen", Dawn, January 3, 2017, http://www.dawn.com/news/1306105accessed on January 9, 2017
22Pakistan Development Update, World Bank, November 2017, http://documents.wor1dbank.org/curated/en/386771510146349984/pdf/121027-WP-P164910-PUBLIC-11-9-17- 12am-PDU-Fall-2017-Online.pdfaccessed on February 20, 2018
23Pakistan Development Update, World Bank, November 2017, http://documents.worldbank.org/curated/en/386771510146349984/pdf/121027-WP-P164910-PUBLIC-11-9-17- 12am-PDU-Fall-2017-Online.pdfaccessed on February 20, 2018
24"Iran keen to join CPEC, says envoy", Dawn, January 27, 2017, http://www.dawn.com/news/1311031as accessed on January 30, 2017

ट्रम्प ने 22 अगस्त, 2017 को अपनी दक्षिण एशिया नीति की घोषणा की और स्पष्ट कियाकि पाकिस्तान अभी भी "अराजकता, हिंसा और आतंक के एजेंटों को पनाह" दे रहा है, और उसे इन आतंकवादी समूहों का मुकाबला करने हेतु कदम उठाने चाहिए। इस तरह की घोषणा के तुरंत बाद पाकिस्तानी प्रशासनइस तरह के आरोपों से बचाव के लिए सऊदी अरब, रूस, तुर्की, चीन, साथ ही ईरान पहुंच गया, जिसके तहत प्रयास समान विचारधारा वाले देशों का एक समूह बनाने की थी, जो

पाकिस्तान का समर्थन करता हो। अमेरिका और पाकिस्तान तथा अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच संबंध पूरे साल के दौरान खराब रहे।

सितंबर 2017 में पाकिस्तान, शंघाई सहयोग संगठन का पूर्ण सदस्य बन गया।[26] सितंबर 2017 में चीन के शियामेन में हुए ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में सीमा पार आतंकवाद का मुकाबला करने में सहकारिता को प्रत्यक्ष रूप से संबोधित किए बिना पाकिस्तान का विरोध किया गया था।[27]

भारत पाकिस्तान द्विपक्षीय संबंध

भारत और पाकिस्तान के बीच स्वतंत्र तथा खुला संवाद फिर से शुरू नहीं हो सका। कुलभूषण यादव का मामला, और उन्हें सैन्य अदालत द्वारा मौत की सजा सुनाया जाना, भारत पाकिस्तान संबंधों में एक बड़ी अड़चन बना रहा। 18 मई, 2017 को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ़ जस्टिस ने पाकिस्तान से कहा कि वह मौत की सज़ा को लागू न करे, जब तक कि आईसीजेइस मुकदमे के बारे में अंतिम फ़ैसला नहीं कर देता, जिसे अंतरराष्ट्रीय अदालत के सामने लाया गया है।[28]भारत और पाकिस्तान ने जनवरी 2017 में विश्व बैंक की मध्यस्थता के साथ सिंधु जल संधि पर कुछ समाधान तलाशने की कोशिश की, जो बिना किसी भी समाधान के खत्म हो गया।[29]पाकिस्तान और भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों ने दिसंबर 2017 में बैंकॉक में मुलाकात की। पाकिस्तानी प्रशासन ने भी कुलभूषण यादव की मां और पत्नी को मानवीयतादर्शातेहुए 25 दिसंबर को इस्लामाबाद आने की अनुमति दी।

पिछले प्रोटोकॉल का सम्मान करते हुए और दोनों पक्षों के कैदियों तथा मछुआरों की रिहाई सहितभारत और पाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय बातचीत लगभग बंद है।

1.5 श्रीलंका

राजनीतिक मोर्चे पर श्रीलंका के डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट रिपब्लिक ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद (यूएनएचआरसी) के प्रस्ताव 30/1 को श्रीलंका पर लागू करने की कोशिश की और इसकी संविधान निर्माण प्रक्रिया मेंप्रगति की। विभिन्न राजनीतिक दलों का प्रतिनिधित्व करने वाले 21 सदस्यों वाली संचालन समिति (एससी) एससी ने 21 सितंबर 2017 को संविधान सभा को एक अंतरिम रिपोर्ट पेश की।

25Irfan Ghauri, “You make policy, we follow it, Gen Qamar tells parliament”, The Express Tribune, December 19, 2017, https://tribune.com.pk/storv/1587001/1-armv-chief-arrives-parliament-brief-lawmakers-securitv-situation/accessed on February 21, 2018

26'It is a historic day': Pakistan becomes full member of SCO at Astana summit”, Dawn, June 9, 2017, https ://www. dawn.com/news/1338471accessed on February 21, 2018

27“Spotlight: BRICS summit in Xiamen brings China, India closer”, Xinhua, September 4, 2017, http://www.xinhuanet.com/english/2017-09/04/c 136583342.htmaccessed on February 21, 2018

28"UN court stays KulbhushanJadhav hanging; Modi govt says will do everything to save him", Hindustan Times, May 18, 2017, https://www.hindustantimes.com/india-news/kulbhushan-iadhav-case-live-ici-verdict-expected-at-3-30pm-todav/storv-v6LJOlnS4Raapv5i7H9P3I.htmlaccessed on February 21, 2018

29Anwar Iqbal, "US initiates process for resolving Pakistan-India water dispute", Dawn, January 4, 2017, http://www.dawn.com/news/1306011

हालांकि, राष्ट्र की प्रकृति, शक्तियों के विचलन, उत्तरी तथा पूर्वी प्रांतों के विलय और आधिकारिक भाषा व धर्म की स्थिति के बारे में मुख्य विवादास्पद मुद्दों पर आम सहमति नहीं बन पाई थी। तमिल नेशनल एलायंस टीएनए ने एक नए संविधान को पेश करने हेतु राष्ट्रव्यापी जनमत संग्रह की मांग की थी।

संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषदने 3 मार्च को श्रीलंका केयुद्धकालीन अतीत को संबोधित करते हुए "धीमी" प्रगति की आलोचना की और अधिकारों के उल्लंघन के आरोपों की जांच हेतु अंतरराष्ट्रीय तथा स्थानीय न्यायाधीशों के मिश्रितअदालत के लिए अपने पहले के आह्वान को दोहराया। प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे ने इस मांग को खारिज कर दिया। संयुक्त राष्ट्र ने श्रीलंका को प्रस्ताव को लागू करने के लिए दो और साल दिए थे। श्रीलंकाई सरकार ने सैनिकों को मुकदमा न चलाने की कसम खाकर लिट्टे के साथ संघर्ष के दौरान किए गए कथित युद्ध अपराधों की जांच हेतु अंतर्राष्ट्रीय जजों को अनुमति देने की संयुक्त राष्ट्र की अपील को खारिज कर दिया।

2 मई 2017 को मंत्रिपरिषद ने राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेना द्वारा राष्ट्रीय एकता तथा पुनर्गठन (ओएनयूआर) के कार्यालय द्वारा गठित पहली राष्ट्रीय पुनर्गठन नीति को लागू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। जून 2017 में, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारों की संयुक्त राष्ट्र समिति ने श्रीलंका से एक व्यापक विधेयक अधिकार को अपनाने का आग्रह किया जो आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों को पूरी तरह से शामिल करता है। राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेना ने 20 जुलाई को ऑफिस ऑफ़ मिसिंग पर्सन्स (ओएमपी) पर राजपत्र पर हस्ताक्षर किए।

श्रीलंका ने जनवरी 2017 में 2006 के समुद्री श्रम सम्मेलन की पुष्टि की और 8 मार्च 2017 को इंडोनेशिया में इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन लीडर्स समिट में भाग लिया। अप्रैल 2017 में, कोलंबो ने पहली बार क्षेत्रीय जर्मन राजदूत सम्मेलन श्रीलंका की मेजबानी की और जर्मनी के साथ हिंद महासागर क्षेत्र में एक आर्थिक और राजनीतिक केंद्र बनने कीअपनी महत्वाकांक्षा पर चर्चा की। अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा पर 6वें मॉस्को सम्मेलन के मौके पर 27 अप्रैल, 2017 को श्रीलंका तथा ईरान ने दोनों देशों के बीच सर्वांगीण रक्षा सहयोग के विस्तार का आह्वान किया।

अमेरिका ने आर्थिक, राजनीतिक और सुरक्षा क्षेत्रों में श्रीलंका के साथ अपना सहयोग बढ़ाया। पैसिफिक पार्टनरशिप 2017 ने 07 मार्च को यूएस नेवल शिप फॉल रिवर के आगमन के साथ, हंबनटोटा में अपना प्रारंभिक मिशन रोक दिया। यूएस और एसएल नेवी मरीन के सहयोग से 6 अक्टूबर, 2017 को संपन्न हुई, अफलोत रेडीनेस एंड ट्रेनिंग (सीएआरटी) अभ्यास - 2017 का आयोजन किया गया। श्रीलंकाई सरकार द्वारा सुलह के प्रयासों को चिन्हित करते हुए यूरोपीय संघ ने प्रगति के बारे में

अपनी संतुष्टि व्यक्त करने के बाद मई 2017 में श्रीलंका ने जीएसपी + का दर्जा हासिल किया। हंबनटोटा बंदरगाह को औपचारिक रूप से 9 दिसंबर को चीन के नेतृत्व वाली कंपनी को सौंप दिया गया था और श्रीलंका को पट्टे हेतु प्रारंभिक भुगतान प्राप्त हुआ।

भारत श्रीलंका द्विपक्षीय संबंध

श्रीलंका के प्रधानमंत्री श्री रानिल विक्रमसिंघे 25 से 29 अप्रैल 2017 तक भारत की यात्रा पर थे। भारतीय प्रधानमंत्री ने मई 2017 में द्विपक्षीय यात्रा की और श्रीलंका के प्रधानमंत्री ने 22 से 24 नवंबर तक भारत की यात्रा की। वर्ष 2017 में दोनों देशों के विदेश सचिव स्तर के दौरे भी हुए।

श्रीलंका के प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान भारत तथा श्रीलंका के बीच "आर्थिक परियोजनाओं में सहयोग हेतु समझौता ज्ञापन" (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए, जिसने भविष्य में द्विपक्षीय आर्थिक सहयोग के एजेंडे को संरेकित किया। भारतीय प्रधानमंत्री ने संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय वेसाक दिवस समारोह में भाग लेने हेतु श्रीलंका का दौरा किया और साथ ही साथ भारतीय मूल के तमिलों को संबोधित किया।

विकास सहयोग के हिस्से के रूप मेंभारत मध्य प्रांत में 4000 घरों के निर्माण तथाऊंचे क्षेत्रों में अतिरिक्त 10,000 घरों के निर्माण कार्य में लगा हुआ था। भारत तथा श्रीलंका सिद्धांतिक रूप में, अप्रैल 2017 में ट्रिनकॉमीले में विश्व वारेरा तेल भंडारण सुविधा को संयुक्त रूप से संचालित करने हेतु सहमत हुए। सूखा राहत सहायता के रूप मेंभारत ने अप्रैल 2017 में श्रीलंका को 8 जल बॉउसर और 100 मीट्रिक टन चावल प्रदान किए। भारत द्वारा प्रदान की गई वितीय सहायता सेजाफना विश्वविद्यालय के कृषि संकाय के एक छात्र विकास केंद्र और इंजीनियरिंग संकाय हेतु दो मंजिला इमारत की स्थापन का उद्घाटन जून 2017 में किया गया था।

अप्रैल 2017 मेंश्रीलंका की राज्य-संचालित पेट्रोलियम कंपनी के कर्मचारियों ने भारत के साथ प्रस्तावित सौदे के खिलाफ अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू किया, जो कि रणनीतिक पूर्वी बंदरगाह शहर त्रिनकोमाली में तेल भंडारण सुविधा का संचालन करती है।

विपक्षी दलों ने प्रस्तावित आर्थिक एवं तकनीकी सहयोग समझौते (ईटीसीए) के खिलाफ जनता को भी लामबंद किया।दोनों सरकारों ने दोनों पक्षों के मछुआरा समुदायों के लिए स्वीकार्य समाधान खोजने की कोशिश की। जनवरी और अक्टूबर 2017 में मछुआरों के मुद्दे पर भारत तथा श्रीलंका की मंत्रिस्तरीय स्तर की वार्ता आयोजित की गई थी। भारत सरकार द्वारा पल्क खाड़ी क्षेत्र में निचले इलाकों में जाल से मछली पकड़ने का कार्यको समाप्त करने हेतु की गई पहल को श्रीलंका के साथ साझा किया गया था। इनमें नीली क्रांति योजना के तहत टूना लॉन्ग लाइनिंग के लिए डीप सी फिशिंग वेसल्स में निचले ट्रैवर्स के विविधीकरण पर कार्यक्रम शुरू करना, मूकायुर तथा पूमपुहर मछुवारा बंदरगाह का निर्माण, गहरे समुद्र में ट्यूना लॉन्ग लाइनिंग में पल्क खाड़ी क्षेत्र के मछुआरों के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम शामिल हैं। इसके अलावा, तमिलनाडु सरकार द्वारा पल्क बे क्षेत्र में निचले ट्रैवर्स के लिए नए पंजीकरण पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसके अलावा, पल्क खाड़ी क्षेत्र में

मछली पकड़ने वाले समुदायों के लिए वैकल्पिक आजीविका के अवसर ओपन सी केज़ फार्मिंक, समुद्री शैवाल की खेती और अन्य संबद्ध तटीय मत्स्य पालन गतिविधियों के माध्यम से पेश किए गए थे।

1.6 मालदीव

वर्ष 2017 मालदीव के लोकतांत्रिक एकीकरण हेतु एक अशांति भरासाल रहा। सरकार ने विभिन्न आरोपों में कई विपक्षी नेताओं को गिरफ्तार किया। जनवरी 2017 में, संयुक्त राष्ट्र के पैनल ने फैसला किया कि मालदीव के एक पूर्व रक्षा मंत्री को अवैध रूप से हिरासत में रखा गया है और घोषणा की कि उन्हें तुरंत मुक्त किया जाना चाहिए। मालदीव ने हिरासत में लिए गए पूर्व रक्षा मंत्री पर संयुक्त राष्ट्र के इस फैसले को खारिज कर दिया। तत्कालीन मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद नशीद ने फरवरी 2018 में घोषणा की कि वह मालदीव डेमोक्रेटिक पार्टी (एमडीपी) का प्रतिनिधित्व करने वाले उम्मीदवार के रूप में 2018 में मालदीव राष्ट्रपति का चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि मालदीव में निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित कराना भारत का नैतिक दायित्व है। श्री नशीद को मानवाधिकार तथा लोकतंत्र पर नौवें वार्षिक जिनेवा शिखर सम्मेलन में 25 अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार समूहों के गठबंधन द्वारा प्रतिष्ठित '2017 का साहस पुरस्कार' दिया गया। श्री नशीद ने विपक्षी गठबंधन को जुटाने हेतु श्रीलंका की यात्रा की। जुमोरे पार्टी के नेता गासिम इब्राहिम को गिरफ्तार कर लिया गया और बाद में चिकित्सा हेतु जर्मनी जाने की अनुमति दी गई।

अप्रैल 2017 मेंसोशल मीडिया एक्टिविस्ट और ब्लॉगर यामीन रशीद की निर्मम हत्या कर दी गई। जून 2017 मेंमालदीव ने ब्रिटेन के कारण उत्पन्न मानवाधिकारों की स्थिति की आलोचना की। मालदीव ने 30 से अधिक देशों द्वारा संवैधानिक स्वतंत्रता को बहाल करने, राजनीतिक विरोध हेतुरास्ता बनाने और मानवाधिकार रक्षकों को डराने से रोकने के आह्वान को खारिज कर दिया। "मालदीव में बिगड़ती राजनीतिक और मानवाधिकारों की स्थिति" पर व्यक्तिगत लक्षित प्रतिबंध लगाने के बाद मालदीव ने यूरोपीय संसद की भी आलोचना की।

मालदीव और सऊदी अरब संबंधों के बारे में, मुख्य विपक्षी दल मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी ने सऊदी शाही परिवार को फाफू एटोल को बेचने की कथित योजनाओं के बारे में चिंता व्यक्त की और चेतावनी दी कि यह सौदा "विदेशी सरकार के लिए पूरे प्रवालद्वीप का प्रभावी नियंत्रण" करेगा। मार्च 2017 में, सऊदी अरब सरकार ने कहा कि उसका मेगा प्रोजेक्ट में निवेश करने या मालदीव में द्वीप या प्रवालद्वीप खरीदने का कोई इरादा नहीं है। राजा सलमान की आधिकारिक यात्रा से पहले 24 मार्च को बड़े पैमाने पर विरोध की घोषणा के बाद, राजा की यात्रा रद्द कर दी गई।

मई 2017 मेंराष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने कांग्रेस को दक्षिण एशिया को मिलने वाली विदेशी सहायता में कमी करने का सुझाव प्रस्तुत किया जिसमें अमेरिका द्वारा मालदीव को प्रदान की गई सहायता राशि में भारी कटौती शामिल थी। इस संबंध में तत्कालीन राष्ट्रपति बराक ओबामा ने अमेरिकी विदेश सहायता नीति के तहत मालदीव को 3.3 मिलियन अमरीकी डालर दिए थे, जबकि ट्रम्प सरकार ने केवल 444,000 अमरीकी डालर कीराशि प्रदान कीथी।

मालदीव सरकार ने 5 जून 2017 से कतर के साथ प्रभावी राजनयिक संबंधों को खत्म करने का फैसला किया।मालदीव के राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन ने संयुक्त अरब अमीरात की अपनी आधिकारिक यात्रा के दौरान वेलाना इंटरनेशनल एयरपोर्ट (वीआईए) को विकसित करने हेतु अबू धाबी फंड फॉर डेवलपमेंट (एडीएफडी) के साथ एक ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए।मालदीवके राष्ट्रपति की चीन की यात्रा के दौरान दिसंबर 2017 में मालदीव और चीन ने एक मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) पर हस्ताक्षर किए।

भारत मालदीव द्विपक्षीय संबंध

भारत के विदेश मंत्रालय के तत्कालीन विदेश सचिव डॉ. एस. जयशंकर ने 13 अप्रैल को राष्ट्रपति कार्यालय में राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन अब्दुल गयूम से शिष्टता भेंट की। राष्ट्रपति ने भारत सरकार द्वारा प्रदान की गई निरंतर सहायता हेतु सराहना की। विदेश राज्य मंत्री श्री एम. जे. अकबर ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के विशेष दूत के रूप में 21-22 फरवरी, 2017 में मालदीव का दौरा किया। मंत्री ने नागरिकों की आकांक्षाओं को पूरा करने वाले स्थिर, लोकतांत्रिक, शांतिपूर्ण और समृद्ध मालदीव के निर्माण के लिए भारत के समर्थन को दोहराया।

24 अक्टूबर को नई दिल्ली में पहली भारत मालदीव वाणिज्यिदूतीय संवाद आयोजित किया गया था। भारत ने 14 दिसंबर कचीन और मालदीव के बीच हस्ताक्षरित मुक्त व्यापार समझौते पर एक संरक्षित प्रतिक्रिया दी, जिसमें कहा गया था कि उसे अभी तक पूरा दस्तावेज नहीं देखा है और इसलिएइसपर कोई टिप्पणी नहीं कर सकता है। मालदीव नेशनल डिफेंस फोर्स (एमएनडीएफ) और भारतीय सेना के बीच "एकुवेरिन" नाम का संयुक्त सैन्य अभ्यास कर्नाटक राज्य के बेलगाम में आयोजित किया गया था। भारत ने आंतरिक अशांति के घटनाक्रम के बावजूद मालदीव को अपनी विकास सहायता जारी रखी।

दक्षिण पूर्व / पूर्व एशिया / सुदूर पूर्व

2.दक्षिण पूर्व / पूर्व एशिया / सुदूर पूर्व

क्षेत्र में हुए प्रमुख विकास कार्य: दक्षिण चीन सागर पर पहला मसौदा आचार संहिता (सीओसी) मार्च 2017 में पूरा हो गया था, और चीन तथा आसियान दोनों देश इससे संतुष्ट थे। 6 अगस्त, 2017 को मनीला में 50वें आसियान विदेश मंत्रियों की बैठक मेंदक्षिण चीन सागर पर आचार संहिता के दो पृष्ठ के फ्रेम वर्क को दक्षिण पूर्व एशिया के विदेश मंत्रियों तथा चीन द्वारा अपनाया गया था।

अमेरिकी रक्षा सचिव जिम मैटिस ने आसियान देशों के रक्षा मंत्रियों के साथ शांगरी- ला डायलॉग (1-4 जून, 2017) के मौके पर बैठकें कीं। अमेरिकी रक्षा सचिव ने क्षेत्र में अमेरिकी उपस्थिति को जारी रखने की पुष्टि की।

50वें आसियान वर्षगांठ समारोह मेंआसियान के विदेश मंत्रियों की बैठक में, क्षेत्र मेंकुछ आसियान सदस्यों द्वारा भूमि पुनर्ग्रहण और गतिविधियों के बारे में व्यापक चर्चा और चिंताओं के बाददक्षिण चीन सागर में गैर-सैन्यीकरण तथा आत्म-संयम के महत्व पर जोर दिया गया।

5 अगस्त, 2017 को मनीला में आयोजित 24वें आसियान क्षेत्रीय मंच (एआरएफ) की बैठक मेंसदस्यों ने शांतिपूर्ण तरीके से कोरियाई प्रायद्वीप के पूर्ण, सत्यापन योग्य तथा अपरिवर्तनीय परमाणु मुक्तिकरणहेतु अपना समर्थन दिया। एआरएफ ने उत्तर कोरिया को आसियान क्षेत्रीय मंच का भागीदार बनने के लिए भी कहा, ताकि क्षेत्र की स्थायी शांति, स्थिरता, दोस्ती और समृद्धि की प्राप्ति में सकारात्मक योगदान दिया जा सके।

11वें आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक (एडीएमएम) का आयोजन 23 अक्टूबर, 2017 को मनीला, फिलीपींस के उत्तर में क्लार्क फ्रीपोर्ट में किया गया था। सिंगापुर ने एडीएमएमकी अध्यक्षता की। तीन 'प्रमुख चुनौतियों'; क्षेत्रीय आतंकवाद-रोधी सहयोग को बढ़ावा देना, रासायनिक, जैविक तथा रेडियोलॉजिकल खतरों के प्रति सामूहिक क्षमता बढ़ाना, और विमानन तथा समुद्री क्षेत्र में व्यावहारिक विश्वास निर्माण उपायों का उपयोग करने पर चर्चाएँ हुईं। एडीएमएममें इंडोनेशिया ने एक "मिनी-इंटरपोल" के निर्माण का प्रस्ताव रखा, जिसमें "अवर आइज़" पहल के माध्यम से खुफिया जानकारी साझा करने वाले क्षेत्र के छह देशों को शामिल किया जाएगा।

9 नवंबर, 2017 को वियतनाम के डा नांग में आयोजित 29वीं एशिया-पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन (एपीईसी) मंत्रिस्तरीय बैठक में एपीईसी मंत्रियों और आसियान के प्रतिनिधियों, प्रशांत आर्थिक सहयोग परिषद (पीईसीसी), पेसिफिक आइलैंड्स फोरम (पीआईएफ), और एपीईसी व्यापार सलाहकार परिषद (एबीएसी) के बीच भागीदारी देखी गई।

2.1 ब्रुनेई

5 अक्टूबर, 2017 को, ब्रुनेई के सुल्तान हसनल बोल्कियाह ने सत्ता संभालने और पूर्ण शक्ति के साथ सबसे लंबे समय तक शासन करने वाले सम्राट के रूप में अपनी 50वीं वर्षगांठ मनाई। वैश्विक ऊर्जा की कीमतों में गिरावट ने तेल पर निर्भर राज्यों को प्रभावित किया, कच्चे तेल की कीमतों में 2012 की कीमतों की तुलना में आधे से अधिक की कमी आई। ब्रुनेई के लोगों के बीच प्यार और सम्मान के बावजूद वैश्विक ऊर्जा की कीमतों के कारण गिरते राजस्व ने शासक सम्राट के समक्ष एक बड़ी चुनौती खड़ी की।

2.2कंबोडिया

मानवाधिकार कार्यकर्ता केम सोखा को सैम रेन्सी की जगहकंबोडिया नेशनल रेस्क्यू पार्टी (सीएनआरपी) के नए नेता के रूप में नियुक्त किया गया। सैम रेन्सी ने कंबोडिया नेशनल रेस्क्यू पार्टी (सीएनआरपी) के प्रमुख के पद से इस्तीफा दे दिया था। संसद द्वारा अपराध हेतु कानून में संशोधन के बाद उनकी प्रतिरक्षा को छीन लिए जाने के बाद 2005 के बाद से वह स्व-निर्वासित निर्वासन में थे, ताकि किसी अपराधी को पद पर बनेरहने से रोका जा सके। कंबोडिया के सुप्रीम कोर्ट ने 16 नवंबर, 2017 को फैसला सुनाया कि देश की विपक्षी कंबोडिया नेशनल रेस्क्यू पार्टी (सीएनआरपी) को सरकार के खिलाफ "तख्तापलट" की साजिश रचने के आरोप में भंग करदिया जाए, आमतौर पर जुलाई 2018 में आयोजित आम चुनाव से पहले प्रधानमंत्री हुन सेन की किसी भी प्रतिभागिता को समाप्त कर दिया जाए।

2.3इंडोनेशिया

इंडोनेशिया ने 14 जुलाई, 2017 कोदक्षिण चीन सागर के उत्तरी हिस्सों में पड़ने वाले अपने विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र नाम बदलकर 'उत्तर नतुना सागर'कर दिया।इंडोनेशिया ने जोर देकर कहा कि यह दक्षिण चीन सागर विवाद में एक गैर-दावेदार राज्य है लेकिन नतुना के आसपास मछली पकड़ने के अधिकार, द्वीप समूह में चीनी मछुआरों को हिरासत में लेने और क्षेत्र में अपनी सैन्य उपस्थिति का विस्तार करने पर चीन के साथ टकराव है।बीजिंग में आरआई-पीआरसी पॉलिटिक्स एंड सिक्योरिटी डायलॉग मैकेनिज्म पर 6वीं बैठक मेंचीन और इंडोनेशिया दोनों ने 21वीं सदी के समुद्री सिल्क रोड के साथ इंडोनेशिया द्वारा शुरू किए गए वर्ल्ड मैरीटाइम एक्सिस विजन के बीच संरेखण को मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की।

लाओ पीडीआर

अप्रैल 2017 में, लगभग तीस लाओटियन सैनिकों ने कम्बोडियन क्षेत्र पर अतिक्रमण किया। कंबोडियाई प्रधानमंत्री हुन सेन ने लाओ सैनिकों के लिए वापस लौटने के लिए 17 अगस्त की समय सीमा तय की थी, इसके बाद अपने सैनिकों को भी विवादास्पद क्षेत्र में भेज दिया था। कंबोडियाई पीएम और

उनके लाओ समकक्ष थॉन्गलौन सिसोलिथ के बीच एक समझौते को बाद15 अगस्त तक, उत्तरी कंबोडिया में विवादित सीमा क्षेत्रों से लाओस के सैनिकों ने वापस आना शुरू कर दियाथा। कंबोडियाई पीएम हुन सेन ने सितंबर 2017 में नोम पेन्ह के 'पीस पैलेस' में तनाव को करने के लिएअपने लाओस समकक्ष पीएम थॉन्गलौन सिसोलिथ से मुलाकात की। चूंकि दोनों राष्ट्र फ्रांस द्वारा उपनिवेश बनाए गए थे, दोनों राष्ट्रों ने फ्रांसीसी राष्ट्रपति को एक संयुक्त पत्र लिखने पर सहमति व्यक्त की थी जिसमें सीमा के नक्शे का अनुरोध किया गया है जो ऐतिहासिक सीमा सीमांकन को दर्शाता हो। इसके अलावा, उन्होंने फ्रांस को कंबोडियन और लाओस सीमा पर कोई अन्य प्रासंगिक दस्तावेज प्रदान करने के लिए भी कहा।

थाई-लाओ जनरल बॉर्डर कमेटी (जीबीसी) की 24वीं बैठक में क्षेत्र में सुरक्षा को खतरा पैदा करने वाले लोगों के खिलाफ द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने के लिए थाईलैंड के उप प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री प्रवीत वंसुवोन और लाओ के रक्षा मंत्री चान्समोनचैनियल के बीच समझौता किया गया।

2.4 वियतनाम

वियतनाम दक्षिण चीन सागर में चीन के दावों के सबसे मुखर विरोधी के रूप में उभरा। वियतनाम ने मनीला में आसियान की 50वीं वर्षगांठ का जश्न मनाने हेतु आयोजित आसियान विदेश मंत्रिस्तरीय बैठक में दक्षिण चीन सागर में द्वीप-निर्माण के बारे में चिंता व्यक्त की और इसकी आलोचना की।

12 नवंबर, 2017 को वियतनाम की अपनी राज्य यात्रा के दौरान, राष्ट्रपति ट्रम्प ने अपने समकक्ष राष्ट्रपति त्रान दाई क्वांग, प्रधानमंत्री गुयेन जुआन फुच और वियतनाम की कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव गुयेन फातरंग से मुलाकात की। वियतनाम में राष्ट्रपति ट्रम्प की यात्रा का प्रमुख एजेंडाव्यापार था।राष्ट्रपति ट्रम्प ने चीन के साथ पूर्वी वियतनाम सागर के मुद्दे में मध्यस्थता करने की भी पेशकश की।

2.5 म्यांमार

मई 2017 में 21वीं सदी के पंगलोंग शांति सम्मेलन का दूसरा सत्र आयोजित किया गया, जो विभिन्न जातीय सशस्त्र समूहों, सरकार के प्रतिनिधियों, सेना तथा नागरिक समाज समूहों को एक साथ एक ही छतरी के नीचे लाया। हितधारकों द्वार विभिन्न राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक सिद्धांतों पर सहमति बनने की वजह सेशांति सम्मेलन का परिणाम महत्वपूर्ण था। हालांकि, शांति प्रक्रिया की निरंतरता राखीन राज्य और साथ ही सेना तथा जातीय सशस्त्र समूहों के बीच सीमावर्ती क्षेत्रों में धार्मिक हिंसा के कारण तनावपूर्ण रही। राखीन में हुई हिंसा की अंतरराष्ट्रीय स्तर पर निंदा हुई थी। इस बीच, म्यांमार ने आसियान और बिम्सटेक प्रक्रियाओं में सक्रिय रूप से भाग लिया।

2.6फिलीपींस

मई में राष्ट्रपति डुटर्टे ने म्यूट समूह और इस्नीलोन हैपिलोन के इस्लामिक स्टेट से जुड़े सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच लड़ाई के बाद मिंडानाओ द्वीप पर मार्शल लॉ घोषित किया।अक्टूबर में दक्षिणी शहर मरावी में जो एक क्रूर घेराबंदी की निगरानी करता था उसे जिहादी लड़ाकों से मुक्त घोषित किया गया था, जिन्होंने इसपर लगभग पांच महीने तक कब्जा किया हुआ था।

अमेरिका और फिलीपींस के सैनिकों ने 2 अक्टूबर को एक नया संयुक्त आतंकवाद-रोधी अभ्यास शुरू किया।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने अपने पांच देशों के एशिया दौरे के तहत 13 नवंबर को फिलीपींस का दौरा किया। राष्ट्रपति ट्रम्प ने राष्ट्रपति रोड्रिगो डुटर्टे के साथ आसियान शिखर सम्मेलन के मौके पर मुलाकात की, जहां दोनों नेताओं ने अपनी 70 साल की साझेदारी को स्वीकार करते हुए, अपने द्विपक्षीय गठबंधन को मजबूत करने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया।

6 दिसंबर, 2017 को, राष्ट्रपति डुटर्टे ने शांति वार्ता को रद्द करने के बाद फिलीपींस की कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीपी) और उसके सशस्त्र विंग न्यू पीपुल्स आर्मी (एनपीए) को आतंकवादी समूहों के रूप में वर्गीकृत करते हुए घोषणा पर हस्ताक्षर किए। राष्ट्रपति का आदेश राज्य को उन समूहों या व्यक्तियों को पकड़ने की अनुमति देता है जो सीपीपी-एनपीए का समर्थन कर रहे हैं।

2.7सिंगापुर

सिंगापुर के प्रधानमंत्री ली हिसयन लूंग ने चीन की अपनी आधिकारिक यात्रा के दौरान राष्ट्रपति शी जिंगपिंग और प्रधानमंत्री ली केकियांग के साथ चीन की सर्वोच्च पोलित ब्यूरो स्थायी समिति के सदस्यों के साथ मुलाकात की। प्रधानमंत्री ली ने कहा कि चीन के साथ सिंगापुर का संबंध अच्छा है।सिंगापुर के रक्षा मंत्री एनजी इंग हेन ने चीनी राज्य पार्षद तथा राष्ट्रीय रक्षा मंत्री चांग वानक्वान से भी मुलाकात की। दोनों मंत्रियों ने 2014 में सहमति जताते हुए चार-सूत्रीय सहमति के आधार पर रक्षा संबंधों को गहरा करने हेतु ठोस और व्यावहारिक तरीके की खोज करके, दोनों देशों के बीच रक्षा संबंधों को गहरा करने तथा आपसी विश्वास व व्यावहारिक सहयोग का निर्माण करने की प्रतिबद्धता की पुष्टि की।

थाईलैंड

राजा वाजीरलॉन्गकोर्न ने नए, सैन्य-प्रारूपित संविधान पर हस्ताक्षर किए, जो कि 2014 में जूनता शासन के बाद से थाईलैंड में लोकतंत्र की वापसी का मार्ग प्रशस्त करता है।

10 अक्टूबर, 2017 को कैबिनेट और राष्ट्रीय शांति एवं व्यवस्था परिषद की संयुक्त बैठक के बाद थाईलैंड के प्रधानमंत्रीप्रयुत चान ओ चा ने कहा कि उनका शासन राजनीतिक प्रतिबंधों को कम करने पर विचार करेगा ताकि दलनया कानून के अनुपालन में अपनी राजनीतिक गतिविधियों को पुनः शुरू कर सकें। 11 जुलाई, 2017 कोथाईलैंड की सैन्य सरकार ने उच्च गति के रेलवे के पहले खंड के

निर्माण हेतु 179 बिलियन बात को मंजूरी दी, जो अंततः बैंकॉक को दक्षिणी चीन से जोड़ देगा। परियोजना चीन के विशाल क्षेत्रीय बुनियादी ढांचे की योजना का हिस्सा है, जो दक्षिणी शहर कुनमिंग को लाओस, थाईलैंड, मलेशिया और सिंगापुर से जोड़ता है। राष्ट्रपति ट्रम्प ने 2 अक्टूबर, 2017 को व्हाइट हाउस में प्रधानमंत्रीप्रयाुत चान-ओ-चा का स्वागत किया और कहा कि अमेरिका तथा थाईलैंड के वर्तमान संबंध बहुत मजबूत हैं और पिछले नौ महीनों में और मजबूत हुए हैं।

2.10 आसियान-भारत द्विपक्षीय संबंध

2017 में आसियान-भारत वार्ता साझेदारी की 25वीं वर्षगांठ मनाया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने माना कि "एक्ट ईस्ट पॉलिसी" उस महत्व कोदर्शाता है जिसके तहत भारत आसियान के साथ अपनी रणनीतिक साझेदारी से जुड़ा हुआ है।14 नवंबर, 2017 को मनीला, फिलीपींस में 15वें भारत-आसियान शिखर सम्मेलन में अपने संबोधन के दौरान, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत अपनी 15वीं"एक्ट ईस्ट पॉलिसी"के मूल में आसियान को रखता है और इंडो-पैसिफिकक्षेत्रीय सुरक्षा वास्तुकला में केंद्रीय है।

1 अप्रैल, 2017 को मलेशिया के प्रधानमंत्री मोहम्मद नजीब बिन तुन अब्दुल रजाक ने भारत का दौरा किया। दोनों देशों ने हमारी रणनीतिक साझेदारी को बढ़ाने हेतु एक साझा दृष्टिकोण पर सहमति व्यक्त की।

विदेश राज्य मंत्री जनरल वी के सिंह (सेवानिवृत्त) ने 6 अगस्त, 2017 को मनीला में 15वें आसियान-भारत के विदेश मंत्रियों की बैठक को संबोधित किया। 26 अगस्त, 2017 कोभारत ने म्यांमार के उत्तरी राखीन राज्य में आतंकवादियों द्वारा नए सिरे से हिंसा तथा हमलों का खुलासा करने वाली रिपोर्टों पर अपनी चिंता व्यक्त की और इस तरह की हिंसा की निंदा की।

इसके अलावा, इसने म्यांमार गणराज्य की सरकार को अपना मजबूत समर्थन दिया। म्यांमार गणराज्य के राष्ट्रपतिमहामहिमयू. हतिन क्याव के निमंत्रण परभारत के प्रधानमंत्रीने 5 से 7 सितंबर 2017 तक म्यांमार गणराज्य की अपनी पहली द्विपक्षीय राज्यकीय यात्रा की। इस यात्रा के दौरानस्वास्थ्य, संस्कृति, क्षमता निर्माण, समुद्री सुरक्षा और प्रमुख संस्थानों के बीच सहयोग के क्षेत्रों मेंविभिन्न दस्तावेजों पर हस्ताक्षर और आदान-प्रदान किए गए। दोनों पक्षों ने इस विचार को साझा किया कि राखिन राज्य की स्थिति में विकास के साथ-साथ सुरक्षा आयाम भी महत्वपूर्ण था। म्यांमार ने राखीन राज्य विकास कार्यक्रम के तहत भारत की सहायता की पेशकश का स्वागत किया और दोनों पक्षों ने अगले कुछ महीनों के भीतर कार्यान्वयन के तौर-तरीकों को अंतिम रूप देने पर सहमति व्यक्त की। दोनों पक्षों ने दोनों देशों के बीच पहले से ही सीमांकित सीमा हेतु अपने पारस्परिक सम्मान को दोहराया और मौजूदा द्विपक्षीय तंत्र तथा परामर्शों के माध्यम से बकाया सीमा सीमांकन मुद्दों को जल्द से जल्द हल करने की आवश्यकता पर जोर दिया।भारत के तत्कालीन विदेश सचिव डॉ. एस. जयशंकर 20 दिसंबर, 2017 को म्यांमार की आधिकारिक यात्रा पर गए थे।यात्रा के दौरान,

उन्होंने राज्य काउंसलर दाऊ आंग सान सू की, राज्य के काउंसलर कार्यालय में केंद्रीय मंत्री यू क्यॉ टिंट स्वे और केंद्रीय समाज कल्याण, राहत और पुनर्वास मंत्री डॉ. विन मय ऐ से मुलाकात की।

सिंगापुर और भारत ने 24 अक्टूबर, 2017 को आसियान के रक्षा मंत्रियों की बैठक के दौरान द्विपक्षीय वार्ता में अपने मजबूत तथा दीर्घकालिक रक्षा संबंधों की पुष्टि की। नवंबर 2015 में हस्ताक्षरित रक्षा सहयोग समझौते (डीसीए) के तहत, दोनों राष्ट्रएक नियमित रक्षा मंत्रियों के संवाद की स्थापना, समुद्री सुरक्षा में सहयोग को गहरा करने, और अपने रक्षा उद्योगों के बीच सहयोग को प्रोत्साहित करने पर सहमत हुए। भारत और सिंगापुर ने 29 नवंबर, 2017 को समुद्री सुरक्षा में सहयोग को गहरा करने हेतु एक समझौते पर हस्ताक्षर किए तथा महत्वपूर्ण समुद्री रास्तों में नेविगेशन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने का आह्वान किया।

"पॉवरिंग डिजिटल एंड फिजिकल लिंकेज फॉर एशिया इन द 21 सेचुरी" विषय पर पहली बार आसियान-भारत कनेक्टिविटी शिखर सम्मेलन (एआईसीएस), नई दिल्ली में 11-12 दिसंबर, 2017 को आयोजित किया गया था। एआईसीएस विदेश मंत्रालय द्वारा आसियान- इंडिया सेंटर (एआईसी), आरआईएसतथा भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) के सहयोग से विदेश मंत्रालय द्वारा आयोजित किया गया था। दो दिवसीय शिखर सम्मेलन में भारत और आसियान के सदस्य राज्यों के वरिष्ठ सरकारी अधिकारी, विशेषज्ञ, व्यापारिक नेता और उद्यमी एक साथ आए।

2.11 डेमोक्रेटिक पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया (उत्तर कोरिया)

डेमोक्रेटिक पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया (उत्तर कोरिया) ने 2017 में अपने परमाणु तथा मिसाइल कार्यक्रम में महत्वपूर्ण विकास किया। उत्तर कोरिया ने 2017 में 24 मिसाइल परीक्षण और परमाणु परीक्षण किया।[30] परीक्षणों में दो अंतर महाद्वीपीय बैलेस्टिक मिसाइलों (आईसीबीएम); ह्वासोंग-14 और ह्वासोंग-15 और एक मध्यवर्ती श्रेणी की बैलिस्टिक मिसाइल (आईआरबीएम) जिसे ह्वासोंग-12 कहा जाता है, का सफल प्रक्षेपण किया। 3 सितंबर, 2017 कोउत्तर कोरिया ने अपना छठा परमाणु परीक्षण किया, जिसकी अनुमानित उपज 250केटीथी।उत्तर कोरिया ने दावा किया कि परीक्षण किया गया बम हाइड्रोजन बम था जो कि आईसीबीएम पर लगाए जानेजाने में सक्षम था।28 नवंबर, 2017 को ह्वासॉन्ग-15 के परीक्षण के बाद, उत्तर कोरिया ने अपने "राज्य परमाणु बल" के पूरा होने का दावा किया। ह्वासॉन्ग-15 की अनुमानित सीमा 13,000 किमी (8,100 मील) से अधिक है - जो वाशिंगटन डीसी तक पहुंचने मेंसक्षम है।[31]

उत्तर कोरिया के परमाणु मिसाइल के उकसावे के जवाब में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने पाँच यूएनएससी प्रस्तावों को अपनाते हुए प्रतिबंध: 2345, 2356, 2371, 2375, और 2397 लगाएं।[32] नए प्रतिबंधों के तहत कोयला, लोहा, सीसा और समुद्री भोजन, कपड़ा निर्यात आदि के सभी निर्यातों और औद्योगिक उपकरणों, मशीनरी, परिवहन वाहनों और औद्योगिक धातुओं के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया गया। इसके तहत पेट्रोल, डीजल और अन्य परिष्कृत तेल उत्पादों के निर्यात में कुल 89% की कटौती भी

की गई है। यह उत्तर कोरियाई मजदूरों का उपयोग करने वाले देशों को भी 24 महीने के भीतर घर वापस भेजने की मांग करता है।

2017 में, अमेरिका और उत्तर कोरिया के बीच सैन्य खतरे के आदान-प्रदान के बाद कोरियाई प्रायद्वीप में सुरक्षा तनाव अधिक स्तर तक बढ़ गया। 19 सितंबर, 2017 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के अपने संबोधन में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने उत्तर कोरिया को चेतावनी देते हुए कहा कि वह परमाणु और बैलिस्टिक मिसाइल खतरों के कारण उत्तर कोरिया को "पूरी तरह से नष्ट" कर सकते हैं। जवाब में उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग-उन ने "उच्चतम-स्तरीय" कार्रवाई करने हेतु एक बयान जारी किया।

30"North Korean Missile Launches & Nuclear Tests: 1984-Present", CSIS, https://missilethreat.csis.org/north-korea-missile-launches-1984-present/
31David Wright, "North Korea's Longest Missile Test Yet", November 28, 2017, www.allthingsnuclear.org/dwright/nk-longest-missile-test-yet
32"Security Council Resolutions", United Nations, www.un.org/en/sc/documents/resolutions/2017.shtml

20 नवंबर, 2017 को संयुक्त राज्य अमेरिका ने उत्तर कोरिया के परमाणु हथियार कार्यक्रम व्यवस्था पर दबाव बढ़ाने के उद्देश्य से उत्तर कोरिया को प्रतीकात्मक कदम में आतंकवाद प्रायोजक राष्ट्रकरार दिया।

7 अक्टूबर, 2017 को,वर्कर्स पार्टी ऑफ कोरिया की 7वीं केंद्रीय समिति की दूसरीविस्तृत बैठक में किम जोंग उन की बहन, किम यो-जोंगको शीर्ष निर्णय लेने वाली संस्था पोलित ब्यूरो का वैकल्पिक सदस्य बनाया गया। फेरबदल में, पार्टी के उपाध्यक्ष और किम जोंग-उन के सबसे करीबी सहयोगियों में से एकचोएरॉन्ग-हे को पार्टी के केंद्रीय सैन्य आयोग का सदस्य चुना गया था। वो सरकार और पार्टी में आठ हाई-प्रोफाइल पदों पर कार्यरत हैं। उत्तर कोरिया के विदेश मंत्री री योंग हो को पोलित ब्यूरो के पूर्ण वोट वाले सदस्य के रूप में भी पदोन्नत किया गया था।[33]

भारत-उत्तर कोरिया द्विपक्षीय संबंध

द्विपक्षीय स्तर पर भारत और उत्तर कोरिया के बीच कोई दौरा नहीं हुआ। 21 अप्रैल, 2017 कोभारत ने किसी भी भारतीय नागरिक या फर्म को प्योंगयांग को उत्तर कोरिया की बैलिस्टिक-मिसाइल क्षमताओं को बढ़ावादेने वाले हथियारों, किसी भी परमाणु संबंधित सामग्री या प्रौद्योगिकी, या किसी भी अन्य सामग्री की आपूर्ति करने से प्रतिबंधित कर दियाऔर उत्तर कोरियाई अधिकारी को भारत में मिलने वाले सभी सैन्य और पुलिस प्रशिक्षण पर रोक लगा दी। हालांकि, भारत नेभोजन और दवा की आपूर्ति जारी रखने का फैसला किया।[34] 3 सितंबर, 2017 को उत्तर कोरिया के परमाणु परीक्षण के जवाब में, भारत ने अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धता के उल्लंघन तथा भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव के संबंधमें गहरी चिंता का विषय मानते हुए परीक्षण को समाप्त कर दिया।[35]

2.12 जापान

2017 में जापान में राजनीतिक परिदृश्य प्रधानमंत्री शिंजो आबे के खिलाफ भ्रष्टाचार, विपक्षी पार्टी के विघटन और नए राजनीतिक दलों के गठन के खिलाफ भ्रष्टाचार के सभी मामलों कागवाह बना और अस्थिर रहा। प्रधानमंत्री आबे के साथ भ्रष्टाचार के आरोपों में दो स्कूल संचालकों कापक्षपात करने और कैबिनेट मंत्रियों से जुड़े घोटालों के आरोपों में शामिल होने से, आबे प्रशासन की राजनीतिक प्रतिष्ठा धूमिल हो गई। 29 जुलाई, 2017 को, दक्षिण सूडान में अमेरिकी शांति सैनिकों के रूप में सेवारत जापानी सैनिकों की गतिविधियों का विवरण देने वाले लॉग विवर के कवर-अप के आरोपों के बाद, रक्षा मंत्री टोमोमी इनाडा ने इस्तीफा दे दिया।[36]

28 सितंबर, 2017 को, प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने सभा के निचले सदन को भंग कर दिया और अनियोजित चुनाव कराने का आह्वान किया। चुनाव की घोषणा के बादटोक्यो के गवर्नर युरिको कैके के नेतृत्व में एक नई राजनीतिक पार्टी किबो नो टू (पार्टी ऑफ होप) का गठन किया गया। अनियोजितचुनाव में मुख्य विपक्षी दल, डेमोक्रेटिक पार्टी ने युकियो एडानो के तहत एक नई राजनीतिक पार्टी, संवैधानिक डेमोक्रेटिक पार्टी (सीडीपी) बनाने हेतु विघटित किया। डेमोक्रेटिक पार्टी के कुछ सदस्य पार्टी ऑफ होप में शामिल हो गए। 22 अक्टूबर, 2017 को हुए चुनाव मेंप्रधानमंत्री शिंजो आबे की लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी और उसके साथी कोमिटो के सत्तारूढ़ गठबंधन ने अक्टूबर 22 के चुनाव में 465 सीटों में से 312 सीटें जीतकर निचले सदन में जापानी सभा के दो-तिहाई बहुमत को बरकरार रखा। एलडीपी ने 284 सीटें हासिल की और चुनाव से पूर्व की स्थिति बरकरार रखी। पार्टी ऑफ होप को 50 सीटें मिलीं, संवैधानिक डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ जापान -54, एलडीपी की गठबंधन सहयोगी कोमितो -29, जापान कम्युनिटी पार्टी -12 और होप पार्टी की गठबंधन सहयोगी निप्पन इशिन -10 सीटें जीती।[37]

33 "Second Plenum of Seventh WPK Central Committee", KCNA, October 8, 2017, https://kcnawatch. co/newstream/1507453321-366833140/second-plenum-of-seventh-wpk-central-committee/ (Accessed on October 9, 2017)

34"Democratic People's Republic of Korea- Non-Proliferation order, April 21, 2017 Democratic People's Republic of Korea- Non-Proliferation order", MEA, India, April 21, 2017 (2.79MB)mea.gov.in/press-releases.htm?51/Press_Releases

35"Press Statement on Nuclear Test conducted by DPRK", The Ministry of Foreign Affairs, India, September 3, 2017,mea.gov.in/press-releases.htm?dtl/28911/press+statement+on+nuclear+test+conducted+by+dprk

36Reiji Yoshida, "Struggling in polls, Abe puts premium on stability in Cabinet shake-up", The Japan Times, August 3, 2017,http://www.iapantimes.co.ip/news/2017/08/03/national/pohtics-diplomacv/struggling-polls-abe- puts-premium-stability-cabinet-shake/#.WYgB9oh96M9(Accessed on August 7, 2017)

एक दिसंबर 8, 2017 को, जापानी सरकार ने मंजूरी दी कि 30 अप्रैल 2019को सम्राट अकिहितो गुलदाउदी सिंहासन का त्याग कर देंगे। अगले दिन, 1 मई कोक्राउन प्रिंस नरहिटो सम्राट बन जाएंगे, और 30 साल तथा चार महीने काहेसी युग समाप्त हो जाएगा और अभी तक नामित नहीं हुए एक नए युग की शुरुआत होगी। यह जापान की संवैधानिक राजनीति के इतिहास में पहला संकेत होगा।[38]

उत्तर कोरिया की ओर से जारी मिसाइल और परमाणु उकसावे के बाद 2017 में जापान में सुरक्षा की स्थिति अस्थिर रही। दो बार उत्तर कोरियाई मिसाइल जापानी क्षेत्र के ऊपर से गुजरी। जवाब में, "अधिकतम दबाव" के वैश्विक अभियान में अमेरिका तथा दक्षिण कोरिया के साथ जापान सबसे आगे आया था। 10 फरवरी, 2018 कोजापानी प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने नए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के साथ शिखर सम्मेलन में भाग लिया। शिखर सम्मेलन के दौरान राष्ट्रपति ट्रम्प ने अमेरिकी सैन्य क्षमताओं के माध्यम से जापान की रक्षा करने की अमेरिका की प्रतिबद्धता की पुष्टि की, जिसमें सेनकाकू द्वीप समूह सहित परमाणु तथा पारंपरिक दोनों प्रकार की रक्षा शामिल थे। बीजिंग में 14-15 मई, 2017 को आयोजित पहले बेल्ट एंड रोड फोरम में जापान ने भाग लिया। जापानी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व एलडीपीमहासचिव- तोशीहिरो निकाई ने किया। 11 नवंबर, 2017 को जापानी प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से वियतनाम के दनांग में एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन (एपीईसी) शिखर सम्मेलन के मौके पर मुलाकात की और अपनी बैठक को जापान-चीन संबंधों में एक "नई शुरुआत" बताया। 8 दिसंबर, 2017 को, जुलाई 2017 जापान में हुए एक सिद्धांतिक समझौते के बाद जापान ने यूरोपीय संघ के साथ एक मुक्त व्यापार समझौते को अंतिम रूप दिया।[39] जापान - यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौता अब तक का सबसे बड़ा मुक्त व्यापार समझौता है।

37 "VOTE 2017: Coalition retains two-thirds majority as all seats finalized", Asahi Shimbun, October 23, 2017, http://www.asahi.com/ajw/articles/AJ201710230012.html (Accessed on October 30, 2017)

38 “Cabinet sets abdication date; talks move to ceremony plans”, The Asahi Shimbun, December 8, 2017, http://www.asahi.com/ajw/articles/AJ201712080054.html

39 “Japan-EU Economic Partnership Agreement”, Ministry of Foreign Affairs, Japan, February 15, 2017, http://www.mofa.go.jp/policy/economy/page6e_000013.html

भारत-जापान द्विपक्षीय संबंध

8 जुलाई, 2017 को विभिन्न द्विपक्षीय शिखर सम्मेलनों के बीच, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापानी प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने जर्मनी के हैम्बर्ग में जी20 शिखर सम्मेलन के अवसर पर एक शिखर बैठक की।[40] 13-17 सितंबर, 2017 को जापानी प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने भारत का दौरा किया। "एक मुक्त, खुले और समृद्ध इंडो-पैसिफिक की ओर" पर एक संयुक्त वक्तव्य मेंभारत और जापान ने इंडो-

पैसिफिक क्षेत्र में नियम-आधारित व्यवस्था को "सुरक्षित तथा मजबूत" करने में दोनों देशों की "केंद्रीय भूमिका" को स्पष्ट किया। यात्रा के दौरान, भारत और जापान ने 15 समझौतों पर हस्ताक्षर किए।[41] इनमें शामिल हैं, आपदा प्रबंधन पर एमओसी, भारत में जापानी भाषा की शिक्षा पर समझौता, भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में संपर्क बढ़ाने और विकास परियोजनाओं को बढ़ावा देने हेतु भारत-जापान एक्ट ईस्ट फोरम की स्थापना की पहल, भारत में जापानी निवेश को बढ़ावा देने हेतु दो समझौते, विज्ञान और प्रौद्योगिकी सहयोग को बढ़ावा देने हेतु तीन समझौते, खेल के क्षेत्र में चार समझौते, और नागरिक उड्डयन पर एक समझौता।[42] त्रिपक्षीय और चतुर्भुज स्तरों पर भी जुड़ाव देखने को मिला।13 दिसंबर, 2017 को विदेश सचिव डॉ. एस. जयशंकर ने ऑस्ट्रेलिया में विदेश मंत्रालय तथा विदेश व्यापार विभाग के सचिव सुश्री फ्रांसिस एडम्सन और जापान के विदेश मंत्री श्री शिंसुके सुगियामा के साथदिल्ली मेंचौथे-भारत-ऑस्ट्रेलिया-जापान त्रिपक्षीय वार्ता की मेजबानी की।[43]

12 नवंबर, 2017 को भारत के विदेश मंत्रालय, ऑस्ट्रेलिया के विदेश मामलों के विभाग, जापान के विदेश मंत्रालय और संयुक्त राज्य के राज्य विभाग के अधिकारियों ने इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में आम हित के मुद्दों पर परामर्श हेतु मनीला में मुलाकात की।[44]

18 सितंबर, 2017 को भारतीय विदेश मंत्री, सुषमा स्वराज ने न्यूयॉर्क में अमेरिकी विदेश मंत्री टिलरसन और जापानी वित्त मंत्री कोनो के साथ मंत्रीीय त्रिपक्षीय बैठक की। समुद्री सुरक्षा, कनेक्टिविटी और प्रसार मुद्दों पर विचारों का आदान-प्रदान किया गया।[45]

10 जुलाई कोजापानी समुद्री आत्मरक्षा बल (एसडीएफ) अपने समुद्री सुरक्षा सहयोग को बढ़ाने के प्रयास में वार्षिक मालाबार अभ्यास में भारतीय तथा अमेरिकी नौसेना में शामिल हो गया। जापान 2014 में मालाबार अभ्यास में शामिल हुआ।

40 "Meeting between Prime Minister and Shinzo Abe, Prime Minister of Japan", MEA, India, July 8, 2017, www.mea.gov.in/press-releases.htm?dtl/28604/Meeting_between_Prime_Minister_and_Shinzo_Abe_Prime_Minister_of_Japan

41 “List of MoUs/Agreements signed during the visit of Prime Minister of Japan to India”, Ministry of External Affairs, Republic of India, September 14, 2017, http://www. mea. gov.in/bilateral-documents.htm?dtl/28949/List of MoUsAgreements signed during the visit of Prime Minister of Japan to India September 14 2017 (Accessed on September 15, 2017)

42 "India-Japan Joint Statement during visit of Prime Minister of Japan to India", Ministry of External Affairs, India, September 14, 2017, www.mea.gov.in/bilateral-documents.htm?dtl/28946/IndiaJapan+Joint+Statement+during+visit+of+Prime+Minister+of+Japan+to+India+September+14+2017

43 "4th India-Australia-Japan Trilateral Dialogue", MEA, India, December 13, 2017, http://mea.gov.in/press-releases.htm?dtl/29176/4th+indiaaustraliajapan+trilateral+dialogue+december+13+2017

44 "India-Australia-Japan-U.S. Consultations on Indo-Pacific", MEA, India, November 12, 2017, , http ://mea. gov.
in/pressreleases.htm?dtl/29110/indiaaustraliajapanus+consultations+on+indopacific+november+12+2017

45"India Japan US Trilateral Foreign Ministerial Meeting", MEA, India, September 18, 2017 , http://mea.gov.in/press-releases.htm?dtl/28957/india+japan+us+trilateral+foreign+ministerial+meeting

जापान ने अपना सबसे बड़ा विध्वंसक, इजुमो भेजा, जो एक बार में 14 हेलीकॉप्टरों को ले जाने में सक्षम था।[46]

12 नवंबर, 2017 को भारत के विदेश मंत्रालय, ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्रालय विभाग, जापान के विदेश मंत्रालय और संयुक्त राज्य के राज्य विभाग के अधिकारियों ने इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में सामान्य हित के मुद्दों पर परामर्श हेतु मनीला में मुलाकात की।[47]

2.12कोरिया गणराज्य (दक्षिण कोरिया)

साल 2017 दक्षिण कोरिया में महत्वपूर्ण राजनीतिक परिवर्तन का गवाह बना। अक्टूबर 2016 से मार्च 2017 तक राष्ट्रपति पार्क ग्यून-हाय के भ्रष्टाचार के घोटाले में शामिल होने के बाद राजनीतिक संकट सामने आया। मार्च में कोरिया की संवैधानिक अदालत ने राष्ट्रपति पार्क ग्यून-हायके महाभियोग को बरकरार रखा। मई के पहले सप्ताह में हुए राष्ट्रपति चुनाव में डेमोक्रेटिक पार्टी के मून जे-इन ने जीत हासिल की। 2017 के पहली छमाही के दौरान राजनीतिक संकट का अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा, लेकिन दूसरी छमाही में स्थिति बेहतर हो गई।टीएचएएडी प्रणाली को लागू करने के दक्षिण कोरिया के फैसले के खिलाफ चीन का आर्थिक प्रतिशोध एक अन्य कारक था जिसने कोरियाई अर्थव्यवस्था को प्रभावित किया। चीन के आर्थिक प्रतिशोध ने मार्च में दक्षिण कोरिया में चीनी समूह के दौरे पर प्रतिबंध लगा दिया और एयरलाइन, पर्यटन, शुल्क-मुक्त दुकानें, डिपार्टमेंट स्टोर और होटल सहित कई कोरियाई उद्योग प्रभावित हुए।हालांकि, मई में राजनीतिक परिवर्तन में सियोल में नए प्रशासन ने रोजगार सृजन पर केंद्रित अनुपूरक बजट पास किया। 2017 मेंदक्षिण कोरिया ने 3 प्रतिशत की आर्थिक वृद्धि हासिल की, जो पिछले तीन वर्षों में सबसे अधिक है। राष्ट्रपति मून जे-इन की आर्थिक नीति जिसे "जे-नोमिक्स" कहा जाता है, में तीन स्तंभ हैं:सार्वजनिक क्षेत्र की अग्रणी भूमिका में रोजगार सृजन, बेरोजगार युवाओं और सेवानिवृत्त व्यक्तियों पर विशेष ध्यान देने के साथ सामाजिक सुरक्षा के जाल का विस्तार, और बड़े बहुराष्ट्रीय कोरियाई निगमों के सुधार, जिससे छबोल के रूप में जाना जाता है। ये नीतियां दो रूढ़िवादी सरकार की आर्थिक नीति से एक महत्वपूर्ण परिवर्तन का प्रतिनिधित्व करती हैं जिसने इस विचार को सभी के सामने रखा कि विकास के परिणामस्वरूप नौकरियों का सृजनहुआ था। सरकार ने रोजगार सृजन और आय-वृद्धि को अपने प्रमुख आर्थिक एजेंडे के रूप में घोषित किया।

सुरक्षा और विदेश नीति के मोर्चे पर 2017 में उत्तर कोरिया की ओर से जारी मिसाइल तथा परमाणु उकसावे के बाद तनाव बढ़ गया। उत्तर कोरिया के युद्ध जैसी स्थिति के जवाब मेंराष्ट्रपति मून ने

बातचीत के दरवाजे को खुला रखते हुए अवरोध तथा "अधिकतम दबाव" का मजबूत तरीका अपनाया। 29-30 अप्रैल, 2017 को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के साथ राष्ट्रपति मून के शिखर सम्मेलन के दौरान और टीएचएएडीमिसाइल रक्षा प्रणाली को तैनात करके संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ अपने गठबंधन की पुनः पुष्टि के माध्यम से सियोल की निरोधात्मक स्थिति को मजबूत किया गया।सियोल भी एकतरफा और बहुपक्षीय प्रतिबंधों को अपनाकर वाशिंगटन के "अधिकतम दबाव" अभियान में शामिल हो गया। 7 जुलाई, 2017 कोराष्ट्रपति मून ने अंतर-कोरिया जुड़ाव को बढ़ावा देते हुए उत्तर कोरियाईपरमाणु समस्या के शांतिपूर्ण समाधान की परिकल्पना करते हुए 'कोरियाई प्रायद्वीप शांति पहल'की घोषणा की। 31 अक्टूबर, 2017 कोदक्षिण कोरिया और चीन दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को सामान्य करने हेतु एक समझौते पर पहुंचे, जो कि टीएचएएडीतैनाती के लिए सियोल के निर्णय के कारण तनावपूर्ण था। "कंफर्ट वूमेन" के मुद्दे पर दोनों देशों के बीच 2015 के समझौते पर फिर से विचार करने के राष्ट्रपति मून के फैसले के बाद जापान के साथ दक्षिण कोरिया का संबंध बिगड़ गया।

46 "Japan, U.S., India begin joint naval drill in India", The Japan News, July 11, 2017, http://the-japan-news.com/news/article/0003811579

47 "India-Australia-Japan-U.S. Consultations on Indo-Pacific", MEA, India, November 12, 2017, www.mea.gov.in/press-releases.htm?dtl/29110/IndiaAustraliaJapanUS_Consultations_on_IndoPacific_November_12_2017

भारत-दक्षिण कोरिया द्विपक्षीय संबंध

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति मून जे-इन ने जर्मनी के हैम्बर्ग में जी20 शिखर सम्मेलन के अवसर पर 7 जुलाई, 2017 को अपनी पहली शिखर बैठक की।

21 अप्रैल, 2017 को भारत और कोरिया गणराज्य ने जहाज निर्माण में रक्षा उद्योग सहयोग हेतु एक अंतर सरकारी समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए। आरओके की विकास सहयोग नीति को समझाने और भारत में दाता संगठनों के साथ विकास सहयोग के अनुभवों को साझा करने हेतु 25 जुलाई, 2017 को कोरिया गणराज्य और भारत के बीच विकास सहयोग पर एक गोलमेज बैठक नई दिल्ली में आयोजित की गई थी।[48]

6 अक्टूबर, 2017 कोभारतीय और दक्षिण कोरियाई नौसेनाओं ने हिंद महासागर में एक संयुक्त ड्रिल का आयोजन किया। दक्षिण कोरियाई युद्धपोतों के बेड़े ने दोनों देशों के बीच सैन्य आदान-प्रदान के हिस्से के रूप में मुंबई का दौरा किया।[49]

48"ROK and India to Hold Roundtable Meeting on Development Cooperation ", MOFA, Republic of Korea, July 25, 2017, www.mofa.go.kr/eng/brd/m_5676/view.do?seq=318824

49"Navies of S. Korea, India hold joint drill in Indian Ocean", The Yonhap News, October 7, 2017, http://english.yonhapnews.co.kr/national/2017/10/07/0301000000AEN20171007003000320.html(Accessed on October 9, 2017)

मध्य एशिया

3.मध्य एशिया

इस क्षेत्र में स्वतंत्रता की 25वीं वर्षगांठ पर उल्लेखनीय राजनीतिक घटनाक्रम और आर्थिक प्रगति देखी गई। कुल मिलाकर, 2017 में क्षेत्र स्थिर रहा और राजनीतिक तथा आर्थिक सुधारों की उम्मीद बढ़ गई।

उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान में सुधार शुरू किए गए। किर्गिज़ गणराज्य में नए राष्ट्रपति के साथ लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई सरकार द्वारा सत्ता का पहला शांतिपूर्ण परिवर्तन देखा गया। उज्बेकिस्तान के नए प्रशासन ने किर्गिस्तान के साथ लंबे समय से प्रतीक्षित सीमा समझौते पर हस्ताक्षर किए। तुर्कमेनिस्तान और कजाकिस्तान ने अप्रैल 2017 में रणनीतिक सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए। राजनीतिक रूप से, क्षेत्र पूरे वर्ष नेतृत्व द्वारा किए गए विदेशी देशों की कई यात्राओं से सक्रिय रहा और इस क्षेत्र में संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस सहित सरकार तथा अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के विदेशी प्रमुख भी दौरे के लिए आए।मध्य एशियाई देशों के नेताओं ने 20-21 मई 2017 को सऊदी अरब की राजधानी रियाद में आयोजित अरब इस्लामिक अमेरिकी शिखर सम्मेलन में भाग लिया। कजाकिस्तान ने भविष्य की ऊर्जा के साथ-साथ विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी पर इस्लामिक सहयोग संगठन के पहले शिखर सम्मेलन में 10-11 सितंबर 2017 को अस्ताना में एक्सपो 2017 की मेजबानी की।

आर्थिक दृष्टि सेक्षेत्र के लिए तेल और गैस की कीमतों में वैश्विक मंदी का सामना करना जारी रहा। 2017 में रूसी अर्थव्यवस्था की वृद्धि ने कुछ गणराज्यों को इस संकट की स्थिति में सहायता प्रदान की जो रूस को अपने माल और मजदूरों का निर्यात करते हैं।रूस में क्षेत्र के प्रवासियों द्वारा भेजे गए धनराशि में किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान के राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद का एक बड़ा हिस्सा शामिल है। इस क्षेत्र ने परिवहन संपर्क में सुधार के साथ दुनिया के साथ अपने आर्थिक एकीकरण को भी जारी रखा। अक्टूबर 2017 में शुरू की गई त्रिपक्षीय बाकू-त्बिलिसी-कार्स(बीटीके) रेलवे लाइन न केवल अज़रबैजान, जॉर्जिया और तुर्की को जोड़ती है, बल्कि एशिया तथा यूरोप के बीच के परिवहन के समय को भी कम करती है, जिसे यूरोप और एशिया[50]और'नए यूरेशियन ब्रिज'के बीच सबसे छोटा तथा सबसे विश्वसनीय लिंककहा जाता है। गलियारा कैस्पियन सागर को तुर्की के माध्यम से यूरोप से जोड़ता है, मध्य एशियाई देशों को पश्चिमी परिवहन नेटवर्क के साथ जोड़ता है।

3.1कजाखस्तान

संसद ने 6 मार्च को देश के संविधान में कुछ संशोधनों को मंजूरी दी। इन संशोधनों से राष्ट्रपति पद की शक्ति कम हो गई और संसद तथा मंत्रियों की कैबिनेट की शक्ति बढ़ गई। शासन का अध्यक्षीय रूप बरकरार है लेकिन अन्य शाखाओं में अब अधिक स्वायत्तता होगी।[51]

कजाखस्तान ने भी 2025 तक कजाख वर्णमाला को सिरिलिक से लैटिन लिपि में बदलने का आदेश दिया।

2017 में, कजाकिस्तान ने भी राजधानी अस्ताना में सीरिया पर बातचीत की मेजबानी करने की पेशकश की। इस बीच, कजाकिस्तान ने 1 जनवरी 2017 से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के गैर-स्थायी सदस्य के रूप में अपने दो साल के कार्यकाल की शुरुआत की।

50NailiaBagirova, “Azerbaijan, Georgia, Turkey launch 'Silk Road' rail link,” Reuters, 30 October 2017, https://www.reuters.com/article/azerbaiian-railwaY/azerbaiian-georgia-turkeY-launch-silk-road-rail-link- idUSL8N1N52XR

51Ministry of Foreign Affairs, “Final Proposal Suggests Redistributing 35 Presidential Powers,” http://mfa.gov.kz/index.php/ru/astana-calling/12-material-orys/8396-astana-calling-51

3.2 किर्गिज़स्तान

अक्टूबर 2017 में हुए किर्गिज़ राष्ट्रपति चुनाव में श्री सूरोनबे जीनबेकोव को देश का नया राष्ट्रपति चुना गया। मध्य एशिया में चुनाव को महत्वपूर्ण माना जाता था क्योंकि यह इस क्षेत्र का एकमात्र देश है जहां संसदीय स्वरूप का पालन किया जाता है।

3.3 तजाकिस्तान

धार्मिक अतिवाद के खिलाफ राष्ट्रपति इमोमाली रहमोन की तल्खी जारी रही। ताजिकिस्तान सुरक्षा ने मई 2017 में ताजिकिस्तान में पूर्व कुलीन पुलिस बल कमांडर कर्नल गुलमुरोड़ हलीमोव के सबसे बड़े बेटे को गिरफ्तार किया, जिसने 2015 में दाएश को हराया था।[52]सऊदी अरब, कतर और जॉर्डन की यात्रा के साथ, अरब देशों के साथ ताजिकिस्तान के संबंध गहरे होते दिख रहे थे, लेकिन ईरान के साथ उसके संबंधों में 2017 में कुछ विकाश देखा गया। ताजिकिस्तान ने जुलाई 2017 में सी5+1 सुरक्षा कार्य समूह की बैठक की मेजबानी की। ताजिकिस्तान के अलावा, बैठक में चार अन्य गणतंत्र कजाखस्तान किर्गिज गणराज्य, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान और अमेरिका के प्रतिभागियों द्वाराभाग लिया गया। बैठक में क्षेत्र में आतंकवाद से उत्पन्न खतरे और सहयोग बढ़ाने के तरीके पर चर्चा हुई।[53]

3.4 तुर्कमेनिस्तान

तुर्कमेनिस्तान के लोगों ने फरवरी 2017 में देश के राष्ट्रपति चुनाव में मतदान किया और एक बार फिर राष्ट्रपति गुरबंगुली बर्दीमुहम्मदोव को सात साल के कार्यकाल के लिए चुना गया।[54] तुर्कमेनिस्तान सरकार ने देश में राजनीतिक सुधारों की दिशा में कदम उठाए। हाल के संवैधानिक संशोधनों के बाद, पहली बारराष्ट्रपति चुनाव में एक से अधिक दलों के उम्मीदवारों ने भाग लिया। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों के रूप में विभिन्न दलों और लोगों के समूहों के नौ उम्मीदवारों ने चुनाव में भाग लिया।[55]

3.5 उज़्बेकिस्तान

देश के महत्वपूर्ण विकासों में राष्ट्रपति मिर्जियॉयव के राष्ट्रपति पद का एक वर्ष का शांतिपूर्ण समापन था। राष्ट्रपति शवकत मिर्ज़ियोयेव ने आर्थिक, न्यायिक तथा प्रशासनिक क्षेत्रों में सुधारों की शुरुआत की, और सरकार में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर नई नियुक्तियों के माध्यम से अपनी स्थिति को मजबूत किया। नए राष्ट्रपति ने संबंधों में सुधार और क्षेत्रीय सहयोग की क्षमता का दोहन करने हेतु पड़ोसियों तक पहुंच बनाई।

उज्बेकिस्तान ने किर्गिस्तान के साथ महत्वपूर्ण सीमा समझौतों का भी समापन किया, जो लंबे समय से जारी थे। नए प्रशासन द्वारा किए गए उपायों ने आशा दी है और यह क्षेत्र में सहयोग तथा सहभागिता के वातावरण में मदद कर रहा है।

52Asia Plus, “Son of fugitive Tajik police colonel who joined IS group arrested,” 10 May 2017, https://news.ti/en/news/taiikistan/securitv/20170510/239630

53U.S. Embassy in Tajikistan, “C5+1 Meeting Held in Dushanbe,” 27 July 2017, https://tj .usembassy. gov/pr- 07272017/

54Reuters, “Turkmenistan leader certain to win third term in vote,” 12 February 2017, http://www.reuters.com/article/us-turkmenistan-election-idUSKBN15Q0TC7iK0

55 The Golden Age Online Newspaper, 12 February 2017, http://www.turkmenistan.gov.tm/eng/?id=7656

3.6 भारत और मध्य एशिया

भारत ने इस क्षेत्र में पांच गणराज्यों के साथ द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय रूप से अपने जुड़ाव को बढ़ाया। भारत और क्षेत्र ने 2017 में 25 साल के राजनयिक संबंधों को चिह्नित किया। कजाकिस्तान ने अप्रैल 2017 में चेन्नई, तमिलनाडु में अपने वाणिज्य दूतावास के उद्घाटन के साथ अपनी राजनयिक मौजूदगी बढ़ाई। इस कदम से पर्यटन सहित लोगों सेलोगों के बीच संबंधों को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। दिल्ली-अल्माटी उड़ानों के अलावा, कजाखस्तान एयर वाहक ने दिल्ली और कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना को जोड़ने वाली एक और सेवा शुरू की।

2017 मेंइस क्षेत्र के साथ बहुपक्षीय स्तर पर सबसे महत्वपूर्ण विकास जून में अस्ताना शिखर सम्मेलन में शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) में भारत की पूर्ण सदस्यता थी, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाग लिया था। भारत के गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने अगस्त 2017 में किर्गिस्तान के बिश्केक के पास इस्किक कूल में आपदा प्रबंधन पर एससीओ 9वीं मंत्रिस्तरीय बैठक में भाग लिया। गृह मंत्री ने दो प्रस्ताव किए और दोनों को सभी एससीओ सदस्यों द्वारा स्वीकार किया गया: पहला, सामूहिक तैयारियों को बेहतर बनाने हेतु 'संयुक्त शहरी भूकंप खोज तथा बचाव' अभ्यास आयोजित करना, और दूसरा, 2019 में आपदा रोकथाम से निपटने वाले एससीओ प्रमुखों की अगली बैठक की भारत द्वारा मेजबानी।अक्टूबर 2017 में, उज़्बेकिस्तान ने एससीओ सदस्यों के न्याय मंत्रियों के पांचवें सम्मेलन का आयोजन किया। प्रतिभागियों ने सदस्य राष्ट्रों के बीच कानूनी क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने और कानून के शासन, अधिकारों के संरक्षण और नागरिकों के वैध हितों को सुनिश्चित करने हेतु कई मुद्दों पर चर्चा की। उन्होंने एससीओ क्षेत्र में निवेश के लिए कानूनी सहायता के आधुनिक तंत्र की शुरुआत पर भी विचार-विमर्श किया।[56]

कजाखस्तान भारत को यूरेनियम के शीर्ष आपूर्तिकर्ता के रूप में उभरा।[57]दक्षिण एशिया-मध्य एशिया ऊर्जा परियोजना तुर्कमेनिस्तान-अफगानिस्तान-पाकिस्तान-भारत प्राकृतिक गैस पाइपलाइन (टीएपीआई) ने 2017 में कुछ प्रगति की; तय समय के अनुसार पाइपलाइन का 214 किलोमीटर का तुर्कमेन खंड बनाया जा रहा है। कार्यों को 2018 के अंत तक पूरा करने की योजना है। मई 2017 में तुर्कमेनिस्तान की अपनी यात्रा के दौरान, उज़्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शवकत मिर्ज़ियोयेव ने तापी परियोजना में उज़्बेकिस्तान की संभावित भागीदारी सहित ऊर्जा सहयोग पर चर्चा की।[58] टीएपीआईने सऊदी अरब में भी रुचि पैदा की, जिसने पाइपलाइन का समर्थन करने के लिए तत्परता व्यक्त की। सऊदी अरब के हित की घोषणा नवंबर 2017 में रियाद में की गई थी।[59] ऊर्जा, उद्योग और खनिज

संसाधन मंत्री खालिद अल-फलीह ने कहा कि राज्य टीएपीआईपाइपलाइन का "समर्थन" करता है और परियोजना को सऊदी अरब में निर्मित सामग्री प्राप्त होगी।[60]

56Diana Aliyeva, "Justice ministers of SCO member states convene in Tashkent," 21 October 2017, https://en.trend.az/casia/uzbekistan/2811031.html
57Ministry of External Affairs, Government of India, "Transcript of Media Briefing in Astana on ongoing visit of Prime Minister to Kazakhstan (June 08, 2017)," 9 June 2017, http://www.mea. gov.in/media-briefings.htm?dtl/28521/ Transcript of Media Briefing in Astana on ongoing visit of Prime Minister to K azakhstan June 08 2017
58Turkmen Petroleum, "GurbangulyBerdimuhamedov and ShavkatMirziyoev have Discussed Participation of Uzbekistan in the Project of the TAPI Gas Pipeline," 22 May 2017,
http://turkmenpetroleum.com/en/2017/05/22/gurbanguly-berdimuhamedov-and-shavkat-mirziyoev-have-
discussed-participation-of-uzbekistan-in-the-project-of-the-tapi-gas-pipeline/
59"The Nation, Saudi Arabia supports TAPI gas pipeline project ," 11 November 2017,
http://nation.com.pk/11- Nov-2017/saudi-arabia-supports-tapi-gas-pipeline-proiect?show=preview

जून 2017 मेंभारत और यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन (ईईयू) ने मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाने हेतु वार्ता की शुरुआत में एक 'याचिका' पर हस्ताक्षर किए।[61] दोनों पक्षों ने भारत-ईएईयूव्यापार क्षेत्र पर एक संयुक्त व्यवहार अध्ययन समूह की स्थापना की थी।[62]दोनों पक्षों ने संयुक्त अध्ययन समूह द्वारा तैयार रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया और याचिका पर हस्ताक्षर के साथ औपचारिक बातचीत शुरू होगी। भारत तथा मध्य एशिया के बीच सुरक्षा सहयोग के नजरिए से, वर्ष 2017 में भारत और किर्गिस्तान के बीच एक व्यस्त कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी, जिसमें मध्य एशियाई देश 2017 के मध्य क्षेत्र में कोकझंगक में अपने वार्षिक संयुक्त विशेष बल विरोधी खंजर श्रृंखला सैन्य अभ्यास का आयोजन किया गया। खंजर श्रृंखला अभ्यास पर्वतीय इलाकों में रणनीति और तकनीक हेतु विशेष बलों के प्रशिक्षण पर केंद्रित थी। अभ्यास किर्गिस्तान और भारत में आयोजित किए गए थे। भारत और कजाकिस्तान ने नवंबर 2017 में हिमाचल प्रदेश में अपना संयुक्त सैन्य अभ्यास प्रबल दोस्तीक 2017 आयोजित किया। 14 दिवसीय प्रशिक्षण अभ्यास का उद्देश्य द्विपक्षीय सैन्य संबंधों को बढ़ाने और दोनों सेनाओं के बीच अंतर को बेहतर बनाना है।[63]2016 में कजाकिस्तान में पहला 'प्रबल दोस्तीक' अभ्यास आयोजित किया गया था।

भारत और मध्य एशिया के सुरक्षा और रक्षा अधिकारियों ने एक दूसरे के देशों का दौरा किया। भारत के सेनाध्यक्ष जनरल बिपिन रावत ने 1 से 6 अगस्त 2017 तक मध्य एशियाई देशों कजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान का दौरा किया। उन्होंने दोनों देशों में उच्च स्तरीय अधिकारियों के साथ बैठक की। कजाकिस्तान ने भारत में काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन, सैन्य शिक्षा और कैडेट्स के प्रशिक्षण के क्षेत्र में क्षमता वृद्धि में भारत के समर्थन की मांग की। जनरल रावत ने कथित तौर पर कजाकिस्तान सेना प्रमुख को अपने आतंकवाद रोधी अभियानों को मजबूत करने में हरसंभव सहायता का आश्वासन दिया।[64]

60Al Arabiya (English), “Saudi Arabia eyes investments in Turkmenistan, including gas, says Falih,” 8 November 2017,http://english.alarabiva.net/en/business/energy/2017/11/08/Saudi-Arabia-eves-investments-in-Turkmenistan-including-gas-savs-Fahh.html

61Sputnik, “EAEU, India Sign Petition on Beginning of Free Trade Area Talks at SPIEF 2017,” 3 June 2017, https://sputniknews.com/business/201706031054277151 -eaeu-india-petition-trade/

62KseniaKondratieva, “India, Russia to set the ball rolling for FTA talks with Eurasian union,” The Hindu, 31 May 2017, http://www.thehindubusinessline.com/economv/policv/india-russia-to-set-the-ball-rolling-for-fta-talks-with-eurasian-union/article9717037.ece

63Press Information Bureau, Government of India, “Indo - Kazakhstan Joint Exercise ‘PRABAL DOSTYK 2017’ Begins,” 2 November 2017, http ://pib.nic.in/newsite/PrintRelease.aspx?relid=173183

64Press Information Bureau, Government of India, Ministry of Defence, “Gen BipinRawat Meets C-in-C Land Forces, Kazakhstan,” 3 August 2017, http://pib.nic.in/newsite/PrintRelease.aspx?relid=169578

पश्चिम एशिया

4.पश्चिम एशिया

पश्चिम एशियाने, जिसमें 24 देश शामिल हैं, बड़े पैमाने पर हिंसा, लोगों के विस्थापन और राजनीतिक अस्थिरता का सामना किया है। धर्म, जातीयता के आधार पर बदलाव हुए हैं, जो संसाधन तथा क्षेत्रीय मजबूरियों से रेखांकित है। इस निरंतर संघर्ष में हजारों लोगों की जान चली गई है, जिससे इस क्षेत्र के भीतर जातीय और धार्मिक समुदायों के बीच घृणा पैदा हुई है। तुर्की जैसे राष्ट्रों ने संसदीय सेट-अप को राष्ट्रपति प्रणाली में बदलते हुए जनमत संग्रह किया। सऊदी अरब के नेतृत्व में पांच अरब देशों ने मुस्लिम भाईचारेके साथ अपने संबंधों के कारण कतर के साथ राजनयिक संबंध तोड़ लिए, मिस्र ने भी सभी कतरी परिवहन के लिए अपने हवाई क्षेत्र और बंदरगाह बंद कर दिए। सऊदी अरब में खुद बड़े बदलाव देखे गए। 500 से अधिक राजकुमारों की गिरफ्तारी, सरकार के मंत्रियों के साथ-साथ विशिष्ट

वर्ग भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरे, क्राउन प्रिंस सलमान का बढ़ता प्रभाव और सऊदी समाज का धीमा आधुनिकीकरण इनमें से प्रमुख है।इस क्षेत्र में यमन की आंतरिक राजनीति में भी गंभीर हस्तक्षेप देखा गया, जिसके कारण बड़े आंतरिक संघर्ष और जान-माल की हानि हुई।

4.1.सऊदी अरब

20 मई 2017 को, अमेरिकी राष्ट्रपति ने अपनी पहली विदेश यात्रा के के लिए सऊदी अरब को चुना। रियाद में अपने दो दिवसीय प्रवास के दौरान तीन महत्वपूर्ण कार्यक्रम हुए। पहले अमेरिका और सऊदी अरब के बीच द्विपक्षीय बैठक हुई थी और इसमें दोनों पक्षों ने 110 बिलियन अमेरिकी डॉलर के सबसे बड़े रक्षा सौदों में से एक पर हस्ताक्षर किए, जिसके अगले एक दशक में 300 बिलियन अमरीकी डॉलर तक बढ़ने की संभावना है। दूसरा कार्यक्रम यूएस-जीसीसी शिखर सम्मेलन था, जो रियाद में हुआ था। इस बैठक में, अमेरिकी राष्ट्रपति ने जीसीसी देशों की ओर पूर्ववर्ती प्रशासन की उदासीन नीति को उलट दिया और अपने खाड़ी सहयोगियों को पूर्ण सहयोग और सुरक्षा का आश्वासन दिया। राष्ट्रपति ट्रम्प ने उन्हें ईरान और उसके प्रॉक्सी समूहों के खिलाफ भी आश्वासन दिया। रियाद ने शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए 50 से अधिक मुस्लिम नेताओं को आमंत्रित किया था। राष्ट्रपति ट्रम्प ने इस्लाम पर भाषण दिया और मुस्लिम नेताओं से कट्टरपंथी ताकत को खत्म करने में उनका सहयोग करने का आग्रह किया, जो इस्लाम में बढ़ रहा है। इस यात्रा के दौरान, राष्ट्रपति ट्रम्प ने रियाद में आतंकवाद विरोधी केंद्र का भी उद्घाटन किया, जिसका कार्य मुस्लिम युवाओं में आतंकवाद, उग्रवाद और बढ़ती कट्टरता की विचारधारा से मुकाबला करना होगा।

राष्ट्रपति ट्रम्प की सऊदी अरब यात्रा को दोनों देशों के बीच नई साझेदारी की शुरुआत के रूप में देखा गया। अमेरिकी राष्ट्रपति ने रियाद की सुरक्षा और आर्थिक भागीदारी में अपना पूर्ण सहयोग देने का आश्वासन दिया, खासकर जब ईरान इस क्षेत्र में तेजी से अपना प्रभाव बढ़ा रहा था। दूसरा, वाशिंगटन ने ओबामा प्रशासन द्वारा अनदेखा किए गए यमन में लड़ने हेतु सटीक हथियारों की भी आपूर्ति की। तीसरा, राष्ट्रपति ट्रम्प की सऊदी अरब की यात्रा को युवा क्राउन प्रिंस की छवि को बढ़ावा देने वाला भी बताया गया था।

जून 2017 मेंसऊदी अरब, यूएई, बहरीन और मिस्र के तीन जीसीसी सदस्य राज्यों सहित चार अरब देशों ने कतर के साथ अपने राजनयिक, परिवहन और आर्थिक संबंधों को खत्म कर दिया। उन्होंने कतर पर आतंकवादी समूहों के वित्तपोषण और समर्थन का आरोप लगाया। दोहा पर उन गैरकानूनी लोगों को शरण देने का भी आरोप लगाया गया जो अपने नागरिकों को उनकी सरकारों के खिलाफ भड़काने तथा अपने मीडिया प्लेटफॉर्म, अलजजीरा का दुरुपयोग करने और उनके विचारों को हवा देने तथा अराजकता और गड़बड़ी का अवांछित माहौल बनाने में शामिल थे। एंटी टेररिस्ट क्वार्टर (एटीक्यू) के रूप में लोकप्रिय चार अरब देशों ने 2012 में हस्ताक्षरित समझौते सहित दो समझौतों को लागू नहीं करने के लिए कतरी अमीर को दोषी ठहराया था। एटीक्यू ने निर्धारित समय सीमा में स्वीकार

की जाने वाली दस मांगें जारी की, जिसमें जीसीसीदेशों के साथ हस्ताक्षरित समझौतों को लागू करना; गैरकानूनी लोगों को उसकी जमीन से बेदखल करना; अलजज़ीरा को बंद करना, ईरान के साथ संबंध को खत्म करना, दोहा में तैनात तुर्की सैन्य को वापस बुलाना शामिल था। कतर के अमीर ने इन मांगों को स्वीकार करने से इनकार कर दिया और इसे अपनी स्वतंत्रता को कम करने का प्रयास करार दिया। हालांकि, कुवैत की सक्रिय मध्यस्थता सेएटीक्यू ने अपनी मांग को संशोधित किया और काहिरा बैठक में इसे घटाकर पांच कर दिया। लेकिन, एटीक्यू की मांगों का स्वरूप यही रहा। दोनों पक्ष अपनी मांगों को लेकर अडिग रहे। अमेरिका और कई यूरोपीय देशों द्वारा सक्रिय मध्यस्थता के बावजूद गतिरोध को नहीं तोड़ा जा सका। और यह पूरे साल जारी रहा।

नवंबर 2017 में, खबर आई कि लेबनान के प्रधानमंत्री साद हरीरी ने रियाद पहुंचने के ठीक बाद इस्तीफा दे दिया। सउदी पर कथित तौर पर साद हरीरी को अपना इस्तीफा देने हेतु मजबूर करने का आरोप लगाया गया था। उनके इस्तीफे का कारण देश के प्रशासन में हिजबुल्ला का हस्तक्षेप बताया गया था, जिसने देश के कुछ हिस्सों में अपनी समानांतर सरकार स्थापित कर रखी थी। लेबनान के राष्ट्रपति, जिनका हिज़बुल्ला के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध था, ने साद हरीरी का इस्तीफा स्वीकार नहीं किया और एक सप्ताह के बाद वे लेबनान लौट आए और अपनापद फिर से संभाला। लेबनान लौटने से पहले, साद हरीरी ने फ्रांस और मिस्र का दौरा किया और यह माना गया कि दोनों देशों की सक्रिय भागीदारी के साथ लेबनानी प्रधानमंत्री खुद को सऊदी बंधक से मुक्त करने में सक्षम थे। हालांकि सऊदी पक्ष ने साद हरीरी के किसी भी उत्पीड़न से इनकार किया और कहा कि यह इस्तीफा देना उनका व्यक्तिगत निर्णय था, लेकिन यह माना जाता था कि सामान्य रूप से इस क्षेत्र में हिज्बुल्लाह की बढ़ती भूमिका, और यमन में हौथी विद्रोहियों के साथ सक्रिय सहयोग ने युवा क्राउन प्रिंस को बेनकाब किया और हेज़बोल्ला को बदनाम करने के लिए मजबूर किया, जो लेबनान में एक गहरी स्थिति के रूप में काम कर रहे थे।

4.2.ईरान

घरेलू और क्षेत्रीय विकास

ईरान के लिएवर्ष 2017 की शुरुआत हाल के दिनों में उनके प्रमुख और व्यावहारिक नेताओं में से एक अयातुल्ला हाशमी रफसंजानी के दुखद निधन से हुई, जिन्होंने 1989 से 1997 तक लगातार दो बार ईरान के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया और 'अप्रत्याशित दिल का दौरा पड़ने'[65] से 8 जनवरी को उनकी मृत्यु हो गई।

28 दिसंबर को, मुद्रास्फीति और आवश्यक वस्तुओं की बढ़ती कीमतों के कारण ईरान अशांति में घिर गया था। यह अशांति इस्लामी गणतंत्र के मूल ताने-बाने के लिए एक गंभीर चुनौती पेश करती है। शुरू में यह ईरान के दूसरे सबसे बड़े शहर मशहद में शुरू हुआ, जिसके बाद यह राजधानी तेहरान सहित अन्य शहरों में विद्रोह फैल गया और इसने एक हिंसक मोड़ लिया जिसमें कई लोगों की मौत हो गई और सैकड़ों को कथित रूप से गिरफ्तार कर लिया गया।[66]ईरान और खराब होती अर्थव्यवस्था के लिए वर्ष 2017 में एक और बड़ा झटका 12 नवंबर को 7.3 तीव्रता[67] के शक्तिशाली भूकंप के रूप

में आया था जिसका केन्द्र ईरान और इराक की सीमा के पास था। इस प्राकृतिक आपदा, जिसमें 500 से अधिक लोग मारे गए और हजारों घायल हुए, को ईरान के पश्चिमी हिस्से में आने वाली अब तक की सबसे बड़ी आपदा माना जाता था।

65 Press TV,"An Ayatollah's death bereaves the nation," January 18, 2017, http://www.presstv.com/Detail/2017/01/18/506695/Ayatollah-Akbar-Hashemi-Rafsanjani , accessed on February 27, 2018.

सकारात्मक रुप में,वर्ष 2017 में ईरान के राष्ट्रपति के रूप में डॉ. हसन रूहानी को दूसरे कार्यकाल के लिए फिर से चुना गया। डॉ. रूहानी को व्यापक रूप से ईरानी राजनीतिक प्रणाली में मॉडरेशन शुरू करने हेतु उनके समर्थन के लिए जाना जाता है, जिन्होंने 19 मई को चुनाव जीता। 20 मई को घोषित चुनाव परिणाम में वो अपने प्रतिद्वंद्वी अब्राहिम रायसी को लगभग 20 प्रतिशत वोटों के अंतर से हराया।[68]

वर्ष 2017 के दौरान, हालांकि, संयुक्त राज्य अमेरिका के नए राष्ट्रपति के रूप में डोनाल्ड ट्रम्प के चुनाव के कारण ईरान की घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति आर्थिक तथा राजनीतिक अनिश्चितताओं से ग्रस्त थी, जिनके चुनाव अभियान में ईरान परमाणु समझौते की निंदा के नारों का बोलबाला था।

राष्ट्रपति ट्रम्प और सऊदी अरब ने ईरान को अलग करने हेतु एक महागठबंधन बनाने का प्रयास किया। ऐसा प्रयास रियाद शिखर सम्मेलन के माध्यम से किया गया था। सऊदी अरब ने अपनी राजधानी में 20-21 मई को रियाद शिखर सम्मेलन 2017 का आयोजन किया, जिसमें अमेरिका ने सऊदी अरब, खाड़ी सहयोग परिषद (जीसीसी), और इस्लामी देशों की मेजबानी के साथ तीन अलग-अलग मंचों पर बातचीत की। जबकि तीनों मंचों पर ईरानी-विरोधी चीजें दिखाई दे रही थी, अमेरिका-सऊदी अरब द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन के दौरान, 'ईरानी प्रभाव और ईरानी संबंधित खतरों'[70] के बीचदोनों देशों ने '110 अरब डॉलर के रक्षा सौदे'[69] पर हस्ताक्षर किए।

जबकि ईरान ने रियाद शिखर सम्मेलन को अमेरिका के "घृणित मुद्रा"[71] अधिनियम के रूप में खारिज कर दिया, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने ईरान पर अपने हमले में कोई अवसर नहीं छोड़ा। 19 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र महासभा (यूएनजीए) में अपने पहले भाषण[72] मेंट्रम्प ने चेतावनी दी कि अमेरिका ईरान के "घातक शासन" को क्षेत्र को अस्थिर करने नहीं देगा, न ही यह ईरान को "खतरनाक मिसाइलों" का निर्माण करने की अनुमति देगा। यह भी कहा है कि अमेरिका यदि वह "परमाणु कार्यक्रम के अंतिम निर्माण हेतु कवर प्रदान करता है, तो वह समझौते का पालन नहीं कर सकता।"[73]

66 The Telegraph, "Hundreds arrested as Ayatollah Ali Khamenei blames Iran's 'enemies' for unrest," January 2, 2018, https://www.telegraph.co.uk/news/2018/01/02/nine-dead-iran-protesters-storm-police-station-fresh- unrest/ , accessed on February 27, 2018.

67 The New York Times, “Iran-Iraq Earthquake Kills More Than 500,” November 13, 2017, https://www.nytimes.com/2017/11/13/world/middleeast/iran-iraq-earthquake.html?_r=0 , accessed on February 27, 2018.

68 iIslamic Republic News Agency (IRNA), “Brief summary of presidential candidates’ backgrounds,” April 21, 2017, http://www.irna.ir/en/News/82500644/ , accessed on February 27, 2018.

69 U.S. Department of State, “Supporting Saudi Arabia’s Defense Needs,” Press Release, May 20, 2017, https://www.state.goWr/pa/prs/ps/2017/05/270999.htm , accessed on February 27, 2018.

70 Ibid.

71 Official Website of Iran’s Supreme Leader Ayatollah Khemenei, “POTUS dances with head of a reactionaryregime, criticizes Iran’s 40-million election: Ayatollah Khamenei,” June 4,2017,

http://english.khamenei.ir/news/4890/POTUS-dances-with-head-of-a-reactionary-regime-criticizes-Iran-s, accessed on February 27, 2018.

72 The White House, “Remarks by President Trump to the 72nd Session of the United Nations General Assembly,” September 19, 2017, https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/remarks-president-trump- 72nd-session-united-nations-general-assembly/ , accessed on February 27, 2018.

एक दिन बाद, 20 सितंबर को, यूएनजीए में अपने भाषण[74] के दौरान, ईरान के राष्ट्रपति हसन रूहानी ने ट्रम्प के दावों का कड़ा विरोध करते हुए कहा कि परमाणु समझौते की "अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा सराहना की गई और इसका संकल्प 2231 के भाग के रूप में सुरक्षा समिति द्वारा समर्थन किया गया।"[75]21 सितंबर को, ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला खामेनी ने भी ईरान के खिलाफ ट्रम्प की बयानबाजी पर प्रतिक्रिया व्यक्त की और इसे "मूर्खतापूर्ण" कहा।[76]

13 अक्टूबर को, राष्ट्रपति ट्रम्प ने घोषणा की कि वह अब ईरान परमाणु समझौते को प्रमाणित नहीं करेंगे और उसी दिन उन्होंने तीन घटकों कीअपनी नई ईरान नीति को लागू किया। इनमें ईरान के"क्षेत्र में आतंकवादी गतिविधियों के लिए अस्थिर गतिविधि और समर्थन"[78]का विरोधऔर ईरान के "मिसाइलों और हथियारों के प्रसार"[80] को संबोधित करते हुएऔर ईरान को"परमाणु हथियार के सभी मार्ग"81 से हटाते हुएईरान पर "अतिरिक्त प्रतिबंध"[79] को लागू करना शामिल था। 5 जून का कतरी संकट मुख्य रूप से ईरान के साथ कतर के संबंधों के कारण उत्पन्न हुआ था।

ट्रम्प द्वारा ईरान के विरोध और अरब दुनिया में इसके अलगाव के बावजूद, 2017 के दौरानईरान सऊदी अरब के साथ अपने छद्म युद्ध में यमन में हौथी विद्रोहियों का समर्थन करने में शामिल रहा। 4 नवंबर को ईरान-सऊदी संघर्ष को और बढ़गया[83] जब लेबनान के प्रधानमंत्री साद हरीरी ने रियाद से ईरान को क्षेत्रीय मध्यस्थता के लिए दोषी ठहराते हुए अपने इस्तीफे की घोषणा की और घंटों के भीतर एक लंबी दूरी की मिसाइल को यमन से हौद विद्रोहियों द्वारा रियाद की ओर दाग दिया गया, जिसका आरोप सऊदी अरब ने ईरान पर लगाया और इसे 'युद्ध काकार्य' करार दिया।[84]

इसी तरह, ईरान ने सीरिया में भी अपनी स्थिति बनाए रखी।इसमें, ईरान को रूस और बाद में तुर्की से लगातार समर्थन मिला और उसके बाद एर्दोगन ने उसके खिलाफ विफल तख्तापलट के प्रयास के

परिणामस्वरूप अपनी सीरिया नीति को संशोधित कर लिया। अमेरिका के साथ एर्दोगन की असहमति और परिणामस्वरूप रूस तथा ईरान के साथ बढ़ती निकटता ने बशर अल-असद को बचाने की दिशा में अतिरिक्त समर्थन हासिल किया।इसका साक्षी 30-31 अक्टूबर को अस्ताना में सीरियाई संकट के समाधान के लिए ईरान, तुर्की और रूस के बीच त्रिपक्षीय वार्ता[86] में 7वें दौर की प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता[85]और 22 नवंबर, 2017 को रूस के सोची शहर में एर्दोगन यूएनएससीआर2254 के तहत 'सीरिया में शांति और स्थिरता स्थापित करने' की दिशा में ईरान के राष्ट्रपति हसन रूहानी, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तईप की वार्ता से सामने आया था।[87]

73Ibid.

74Official Website of Iran's President Hassan Rouhani, "Full text of President Rouhani's address's to the United Nations General Assembly," September 20, 2017, http://www.president.ir/en/100837, accessed on February 27,2018.

75Ibid.

76Official Website of Iran's Supreme Leader Ayatollah Khamenei, "Angry at Iran's Victories and Their Own Defeats is the Reason for America'sEnmity with Iran," September 21, 2017,http://english.khamenei.ir/news/5142/Angry-at-Iran-s-Victories-and-Their-Own-Defeats-is-the-Reason, accessed on February 27, 2018.

77 TheWhite House, "Remarksby PresidentTrumpon Iran Strategy," October 13,2017,

https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/remarks-president-trump-iran-strategy/,accessed on February 27, 2018.

78 Ibid.

79Ibid.

78 Ibid.

81Ibid.

82Ibid.

83CNN, "Missile attack 'an act of war' by Iran, Saudi Foreign Minister says," November 6, 2017, http://edition.cnn.com/2017/11/06/middleeast/saudi-foreign-minister-interview/index.html,accessed on February 27, 2018.

84 Ibid.

हालांकि, 2017 के अंत में ईरान में फैली अशांति ने यह दर्शाया कि मध्य पूर्व में ईरान के बढ़ते क्षेत्रीय लाभ और अलौकिक प्रभाव की एक घरेलू लागत और सीमा है। वर्ष 2018 में ईरान की क्षेत्रीय भूमिका के माध्यम से अपने शासन के अस्तित्व को सुनिश्चित करते हुएअयातुल्ला खुमैनी घरेलू स्थिरता और क्षेत्रीय प्रभाव का एक इष्टतम मिश्रण खोजने हेतु पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा का निवेश कर सकते हैं।

भारत-ईरान द्विपक्षीय संबंध

वर्ष 2017को भारत-ईरान संबंध को इतिहास के निर्माण के रुपमें चिह्नित किया गया, जब 11 नवंबर को लगभग 15,000 टन गेहूं ईरान में चाबहार के माध्यम से एक नए व्यापार और पारगमन मार्ग के माध्यम से पहली बार अफगानिस्तान पहुंचा। इस शिपमेंट को अक्टूबर के अंत में भारत के पश्चिमी बंदरगाह कांडला से रवाना किया गया था और यह ईरान की सीमा से लगे निम्रोज़ के अफगानिस्तान प्रांत में पहुंच गया।[88] द्विपक्षीय यात्राओं के संदर्भ में, वर्ष के दौरान भारत के सड़क परिवहन, राजमार्ग और जहाजरानी मंत्री[89] ने 5 अगस्त को आयोजित अपने दूसरे कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति रूहानी के उद्घाटन समारोह में भाग लिया।अपनी यात्रा के दौरान, श्री गडकरी ने भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का एक अभिनंदन पत्र भी राष्ट्रपति हसन रूहानी को सौंपा। इस पत्र में, प्रधानमंत्री मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति को भारत के दौरे के लिए अपना निमंत्रण दिया था।[90] भारत की विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज ने दो दिसंबर को सोची में एससीओ शिखर सम्मेलन से अपनी वापसी की यात्रा के दौरान ईरान का दौरा किया।[91]3 दिसंबर को ईरान के चाबहार में शहीद बेहिश्ती पोर्ट के चरण 1 के उद्घाटन समारोह के दौरान, भारत का प्रतिनिधित्व राज्य मंत्री (नौवहन) श्री पोन राधाकृष्णन ने किया।[91]2-3 दिसंबर, 2017 को ईरान की अपनी दो दिवसीय यात्रा के दौरान, श्री राधाकृष्णन ने चाबहार पोर्ट डेवलपमेंट पर भारत-ईरान-अफगानिस्तान मंत्री स्तरीय त्रिपक्षीय बैठक की दूसरी बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किया और इसमें ईरान तथा अफगानिस्तान के संबंधित मंत्री शामिल हुए।'[93]

85 Tasnim News, "Iran, Russia, Turkey Wrap Up Syria Peace Talks with Joint Statement," November 1, 2017,

https://www.tasnimnews.com/en/news/2017/11/01/1561953/iran-russia-turkey-wrap-up-syria-peace-talks-with- joint-statement ,accessed on February 27, 2018.

86Official Website of the President of Russia, "Joint statement by Presidents of Iran, Russia and Turkey,"

November 22, 2017, http://en.kremlin.ru/supplement/5256, accessed on February 27, 2018.

87 Ibid.

88Press TV,"Indian wheat cargo reaches Afghanistan via Iran," November 12, 2017,

http://www.presstv.com/Detail/2017/11/12/541905/Indian-wheat-cargo-reaches-Afghanistan-via-Iran, accessedon February 26, 2018.

89Ministry of External Affairs, Government of India, "Minister of Road Transport, Highways and Shipping represents India at the Inauguration Ceremony of President Dr. Hassan Rouhani of Iran," August 6, 2017, http://www.mea.gov.in/press-releases.htm?dtl/28812/minister+of+road+transport+highways+and+shipping+represents+mdia+at+the+inaugur ation+ceremony+of+president+dr+hassan+rouhani+of+iran, accessed on February 26, 2018.

90Ibid.

91Ministry of External Affairs, Government of India, "Visit of External Affairs Minister to Iran on December 2,

2017,"December2,2017,http://www.mea.gov.in/press-releases.htm?dtl/29145/visit+of+external+affairs+minister+to+iran+december+2+2017, accessed on February 26, 2018.

4.3. इजराइल

इजरायल ने 2017 के दौरान आंतरिक रूप से क्षेत्र में महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना किया। सीरिया में संकट, ईरान के साथ मनमुटाव, अपने क्षेत्र के भीतर आतंकवाद को नियंत्रित करने तथा यहूदी विरोधीताओं के बढ़ने जैसे मुद्दों ने इजरायल के निर्णय निर्माताओं को व्यस्त रखा है। मानवाधिकारों के हनन, इजरायल के कब्जे वाले क्षेत्रों में लोगों के इलाज और इसी तरह संयुक्त राष्ट्र में पारित कई प्रस्तावों ने नेतृत्व को उन देशों के साथ सक्रिय रूप से जुड़ने के लिए प्रेरित किया है, जो पहले नहीं पहुंचे थे। 2017 में प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने पूरे यूरोप, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका का व्यापक दौरा किया। पूरे वर्ष के दौरान, इजरायल और फिलिस्तीनी प्राधिकरण के बीच संबंधों में कोई विगलन नहीं हुआ तथा पूरे वर्ष में अधिक भूख हड़ताल, संगठित और सहज रैलियां, पत्थर फेंकने और सीमा पर हमले हुए। घरेलू स्तर परप्रधानमंत्री नेतन्याहू सहित प्रमुख राजनीतिक हस्तियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के कई मामले दर्ज किए गए। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प की दिसंबर 2017 में अमेरिकी दूतावास को यरूशलेम में स्थानांतरित करने की घोषणा ने वैश्विक कूटनीति में भी लहर पैदा कर दी, जिसके कारण सुरक्षा परिषद ने इस तरह के कदम के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया।

भारत इजरायल द्विपक्षीय संबंध

राजनयिक संबंधों की 25वीं वर्षगांठ को चिह्नित करते हुएप्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इज़राइल की अपनी पहली यात्रा की, जो किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा भारत में पहली बार की गई। अपने तीन दिवसीय दौरे (3-5 जुलाई, 2017) परभारत और इज़राइल ने विभिन्न समझौतों हुएतथा समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए।

भारत-इजरायल औद्योगिक अनुसंधान एवं विकास और तकनीकी नवाचार निधि (आई4एफ) की स्थापना के लिए भारत के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, और इजराइल के राष्ट्रीय तकनीकी नवाचार प्राधिकरण, के बीच समझौता ज्ञापन; भारत में जल संरक्षण के लिए राष्ट्रीय अभियान पर भारत गणराज्य के पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय तथा इजराइल के राष्ट्रीय अवसंरचना, ऊर्जा और जल संसाधन मंत्रालय के बीच समझौता ज्ञापन;भारत में राज्य जल उपयोगिता सुधार पर भारत गणराज्य के उत्तर प्रदेश सरकार की उत्तर प्रदेश जल निगम और इजराइल के राष्ट्रीय अवसंरचना, ऊर्जा और जल संसाधन मंत्रालय के बीच समझौता ज्ञापन;भारत-इजरायल विकास सहयोग - कृषि के क्षेत्र में तीन वर्षीय कार्ययोजना 2018-2020;परमाणु घड़ियों में सहयोग के संबंध में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) और इजरायल अंतरिक्ष संस्था (आईएसए) के बीच सहयोग की योजना; जीईओ-एलईओ प्रकाशीय संपर्क में सहयोग के संबंध में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) और इजरायल अंतरिक्ष संस्था (आईएसए) के बीच समझौता ज्ञापन;लघु उपग्रहों के लिए विद्युत

प्रणोदन में सहयोग के संबंध में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) और इजरायल अंतरिक्ष एजेंसी (आईएसए) के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।

92 Ministry of External Affairs, Government of India, "Inauguration ceremony of ShahidBeheshti Port at Chabahar, Iran," December 3, 2017, http://www.mea.gov.in/press-releases.htm?dtl/29146/inauguration+ceremony+of+shahid+beheshti+port+at+chabahar+iran , accessed on February 26, 2018.

93 Ibid.

4.4 तुर्की

देश की अर्थव्यवस्था ने पिछले कई वर्षों से 905 बिलियन अमेरिकी डॉलर के सकल घरेलू उत्पाद के साथ दुनिया की शीर्ष बिसवीं अर्थव्यवस्थाओं के बीच अच्छा प्रदर्शन किया।[3]तुर्की सांख्यिकी विभाग के अनुसार, जर्मनी तुर्की के शीर्ष निर्यात बाजार में 11 बिलियनअमेरिकी डॉलर या कुल निर्यात का 9.6 प्रतिशत हिस्सा रहा, और तुर्की निर्यात का 53.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर जनवरी से सितंबर 2017 तक यूरोपीय संघ के देशों में वितरित किया गया, जिससे तुर्की एक अभिन्न अंग बन गया, जिसमें यूरोपीय अर्थव्यवस्था के बावजूद, राजनीतिक संबंधों में तनाव नहीं है।

2016 से 13.4 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 2017 में तुर्की का विदेशी व्यापार 284 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया। अरब दुनिया के साथ तुर्की के करीबी आर्थिक संबंध और भी गहरे हो गए, तुर्की निर्यात ($ 7.8 बिलियन) के सबसे बड़ाप्राप्तकर्ताबन गया, जिसके बाद इराक (7 बिलियन डॉलर), यूके (7 बिलियन डॉलर) और यूएस (6.5 बिलियन डॉलर) है। हालांकि, तुर्की के आयात में विविधता आई है और चीन और रूस क्रमशः17 बिलियन डॉलर और 13.9 बिलियन डॉलर के साथ प्रमुख निर्यात भागीदार बन गए हैं।[4]

वर्ष 2017 में रूस के साथ अभूतपूर्व सामान्यीकरण प्रक्रिया देखी गई थी लेकिन यूरोपीय देशों के साथ इसके संबंध कई मुद्दों पर तनावपूर्ण रहे। फतुल्लाह आतंकवादी संगठन (एफईटीओ) के खिलाफ तुर्की की निरंतर कार्रवाई और सीरिया में कुर्द आतंकवादी समूहों के लिए अमेरिकी सैन्य समर्थन पर मतभेद, मुख्य रूप से पीकेकेसंबद्ध समूह पीवाईडी-वाईपीजीने तुर्की और उसके पश्चिमी सहयोगियों के बीच विश्वास की खाई को और बढ़ाया।जब तक इराक की कुर्द क्षेत्रीय सरकार (केआरजी) ने अपने क्षेत्रीय सहयोगी मुख्य रूप से तुर्की और इराक और यूरोपीय देशों के केंद्रीय प्राधिकरण के परामर्श की अवहेलना करते हुए एक स्वतंत्र जनमत संग्रह कराने का फैसला किया, तुर्की ने स्वतंत्रता जनमत संग्रह पर एक आम प्रतिक्रिया पर इराक, इराक और सीरिया को एकसूत्र में पिरोने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

तुर्की के विदेश मंत्रालय ने असफल सैन्य तख्तापलट के संबंध में यूरोपीय संघ के अधिकारियों से अपनी स्थिति स्पष्ट करने की मांग जारी रखी, जिस पर कई यूरोपीय देशों को संदेह है और यहां तक कि उन लोगों और व्यक्तियों के प्रति सहानुभूति है जिनपर तुर्की ने तख्तापलट की साजिश रचने का

आरोप लगाया था। यूरोप के साथ तुर्की के संबंधों में एकमात्र अपवाद ब्रिटेन था जिसकी नेता थेरेसा मे ने जनवरी में अंकारा का दौरा किया था।

असफल सैन्य तख्तापलट की कोशिश में अमेरिकी दूतावास की भूमिका पर अमेरिका-तुर्की संबंधों में मुश्किल सवालों का सामना करना जारी रहा, जिसपर तुर्क ने गहरा संदेह जाताया। 29 मार्च को, अंकारा में अमेरिकी दूतावास ने स्वीकार किया कि 21 जुलाई, 2017 को इस्तांबुल में अमेरिकी वाणिज्य दूतावास ने एफईटीओके भगोड़े आदिल ओक्सुज का वीजा रद्द कर दिया था और उन्होंने इस संबंध में उनसे संपर्क किया था। 30 मार्च को, अमेरिकी विदेश मंत्री रेक्स टिलरसन ने अंकारा जाकर और तुर्की को तुर्की का विश्वसनीय सहयोगी बताकर संबंधों को सुधारने की कोशिश की। मई में, राष्ट्रपति रेसेप तईप एर्दोगन ने ट्रम्प प्रशासन के साथ अपने देश के संबंधों को सामान्य करने की उम्मीद में अमेरिका का दौरा किया। लेकिन यात्रा विफल रही और इसके बजाय, तुर्की के दूतावास के बाहर राष्ट्रपति एर्दोगन के सुरक्षा कर्मचारियों और प्रमुख-पीकेके प्रदर्शनकारियों के बीच विवाद ने मीडिया कवरेज को व्याकुल कर दिया।पीकेके से जुड़े सीरिया के उग्रवादी समूह पीवाईडीऔर वाईपीजीसे हथियार की आपूर्ति को रोकने के तुर्की के आग्रह पर दोनों पक्षों के बीच संबंध और बिगड़ गए। जैसे ही प्रयास विफल हुए, अमेरिका के खिलाफ तुर्की की प्रतिक्रिया तेज हो गई, मुख्य रूप से संदिग्ध गतिविधियों में अमेरिकी दूतावास के कर्मचारियों की भागीदारी को इंगित करके और दूतावास के कुछ तुर्की कर्मचारियों को हिरासत में लेकर। प्रतिक्रिया के रूप में8 अक्टूबर को, अंकारा में अमेरिकी दूतावास ने तुर्की में अपने सभी मिशनों में गैर-आप्रवासी वीजा अनुप्रयोगों के प्रसंस्करण को निलंबित कर दिया, जो एक ऐसा निर्णय था जिसे तुर्की ने संयुक्त राज्य अमेरिका में सभी तुर्की वाणिज्य दूतावासों में अमेरिकी नागरिकों के लिए वीजा सेवाओं को निलंबित करके तुरंत लागू किया।

यूएस-तुर्की संबंधआमतौर पर कई विक्षेप और व्यवधानोंद्वारा तनावपूर्ण हो गए। एक तुर्की-ईरानी व्यापारी रेजा सर्राफ के खिलाफ अमेरिकी न्यायपालिका प्रक्रिया एक और प्रमुख मुद्दा था जिसका रिश्ते पर स्थायी प्रभाव पड़ा। नवंबर में, तुर्की ने रेजा सर्राफ के स्वास्थ्य स्थिति पर ध्यान दिलाया, यह जानने के बाद कि उसे हिरासत से किसी अज्ञात स्थान पर भेज दिया गया है, इस डर से कि रेजा सर्राफ तुर्की के खिलाफ गवाह बनने हेतु सहमत हो गया था। वाशिंगटन स्थित तुर्की दूतावास को अमेरिकी न्याय विभाग और विदेश विभाग दोनों से जवाब मिला कि सर्राफ सुरक्षित हैं और उनका स्वास्थ्य अच्छा है। रजा सर्राफ के गवाह बनने के बाद, ईरान पर लगाए गए प्रतिबंधों के उल्लंघन के लिए तुर्की को आर्थिक प्रतिबंध या भारी जुर्माना लगाने की संभावनाओं का सामना करना पड़ेगा। वर्ष 2017 समाप्त होने से पहले, सीरियाई कुर्दिश आतंकवादी समूहों को अमेरिका के समर्थन के मुद्दे ने दोनों पक्षों को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प को अपने तुर्की समकक्ष रेसेपयटिप एर्दोगन को फोन पर 'अब से, कोई हथियार नहीं वाईपीजी [पीकेके / पीवाईडी] को नहीं दिया जाए' बोलकर आश्वस्त करने के लिए दो पक्षों को पूरा करने के लिए मजबूर कर दिया। हालांकि, तुर्की अमेरिका के दावों पर संदेह करता रहा और अफरीन में पीवाईडीके खिलाफ सैन्य अभियान के लिए अपनी तैयारी जारी रखी जो जनवरी 2018 में शुरू होगी।

क्षेत्रीय राजनीतिक परिदृश्य में, तुर्की को नए खिलाड़ियों तक पहुंच बनानी है। तुर्की ने 2014 में बंद होने के बाद लीबिया के त्रिपोली में भी अपना दूतावास फिर से खोल दिया। तुर्की ने यह भी घोषित किया कि वह "संवैधानिक परिवर्तनों पर जनमत संग्रह" को मान्यता नहीं देगा, जिसकी ऊपरी काराबाख में 20 फरवरी मेंकड़ी आलोचना की गई थी, ऐसा क्षेत्र जो अर्मेनियाई के कब्जे में है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे जो तुर्की का सामना करना पड़ा, वह जनमत संग्रह का था जिसकी मांग इराक की कुर्द क्षेत्रीय सरकार ने इराक से संप्रभुता तथा स्वतंत्रता का दावा करने के लिए की थी। अपनी संप्रभुता का दावा करने की प्रक्रिया तब शुरू हुई जब केआरजी ने पेशमार्ग को आईएसआईएस से किरकुक पर कब्जा कर लिया और इसे प्रांतीय कार्यालयों पर केआरजी ध्वज फहराकर केआरजी नियंत्रण के तहत लाया। तुर्की के विदेश मंत्रालय ने उल्लेख किया है कि "ये किर्कुक की बहुसांस्कृतिक पहचान को खतरे में डालते हैं, जो कि इराक की सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक संपदा द्वारा सन्निहित है।" तुर्की ने अपने नियोजित स्वतंत्रता जनमत संग्रह को रोकने के लिए केआरजी को आगाह किया जिसपर केआरजी ने ध्यान नहीं दिया और अपनी योजना को आगे बढ़ाता रहा। तुर्की ने ईरान और इराक के साथ समन्वय के परिणामस्वरूप न केवल जनमत संग्रह को खारिज कर दिया, बल्कि इराक को पेशमर्गा के नियंत्रण से कर्क को हटाने हेतु प्रोत्साहित किया। तुर्की और इराक के बीच तेजी से सुरक्षा सहयोग ने केआरजी की महत्वाकांक्षाओं को समाप्त कर दिया और बरज़ानी सरकार के खिलाफ एक और राजनीतिक संकट पैदा कर दिया। इराक के साथ लंबे समय से तनावपूर्ण संबंधों के बाद तुर्की ने इराक के साथ अपने संबंधों को फिर से स्थापित किया।

तुर्की और उसके पश्चिमी सहयोगियों के बीच विश्वास की खाई को बड़ा बनाने के साथ, तुर्की को अपनी दक्षिणी सीमाओं, इराक और सीरिया में दो गंभीर सुरक्षा चुनौतियों के बीच छोड़ दिया गया था, जहां आतंकवादी समूहों और शासन-विरोधी विद्रोहियों ने सरकारों के खिलाफ हिंसा को जारी रखा है। तुर्की की लगभग एक हजार किलोमीटर सीमा आतंक और अवैध प्रवासन समस्याओं के खिलाफ पूरी तरह से सुरक्षित नहीं हो सकी। तुर्की ने रूस और ईरान के साथ संबंधों को बदलने और स्थिति को सुधारने और बातचीत की राजनीतिक प्रक्रिया के लिए दबाव बनाने का अवसर देखा, हालांकि कम उम्मीदों पर। अस्ताना शांति प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने में तुर्की की महत्वपूर्ण भूमिका ने सीरिया में हिंसा के स्तर को काफी नीचे ला दिया और कई वृद्धि क्षेत्रों की स्थापना की। 2017 के अंत तक, तुर्की ने सीरिया के भविष्य में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने में कामयाबी हासिल की है और रूस तथा ईरान से सुरक्षित आश्वासन दिया गया है कि देश को जातीय सीमाओं में विभाजित नहीं होने दिया जाए क्योंकि अमेरिकी नीतियों का स्पष्ट रूप से देश को विभाजित करने का लक्ष्य है। राष्ट्रपति एर्दोगन और राष्ट्रपति पुतिन ने शांति प्रक्रिया को आगे बढ़ाने हेतु नियमित रूप से बातचीत की और मुलाकात की। राष्ट्रपति एर्दोगन ने ईरान का दौरा किया और प्रधानमंत्री बेनाली येल्डेरिम ने इराक का दौरा किया।

दूसरी ओर, रियाद ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के साथ अरब इस्लामिक देशों के सम्मेलन की मेजबानी ते दौरान तुर्की ने खुद को नए सऊदी नेतृत्व द्वारा हाशिए पर पाया। सम्मेलन के तुरंत बाद, शक्तिशाली खाड़ी देशों सऊदी अरब, बहरीन और यूएई ने कतर की व्यापक सीमा का बहिष्कार करने

की घोषणा की, जिससे डर था कि तुर्की एक गुप्त सैन्य हस्तक्षेप या प्रत्यक्ष शासन परिवर्तन का प्रयास कर सकता है। तुर्की की तीव्र प्रतिक्रिया ईरान, रूस और इराक के बीच घनिष्ठ समन्वय में आई और इस संकल्प का मध्यस्थता करने के लिए बहिष्कार करने वाले देशों के साथ एक संचार लाइन खोली। राष्ट्रपति एर्दोगन और उनके मंत्रियों ने अक्सर क़तर, ईरान और अन्य खाड़ी देशों के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए क्षेत्र का दौरा किया। 2017 के अंत तक, तुर्की ने सऊदी अरब के साथ अपने संबंधों को नुकसान पहुंचाए बिना खाड़ी में अपनी सैन्य और राजनयिक उपस्थिति को मजबूत किया।

भारत तुर्की द्विपक्षीय संबंध

महामहिम श्री रेसेप तईप एर्दोगन के राष्ट्रपति और तुर्की गणराज्य के श्रीमती एमिन एर्दोगन का भारत-तुर्की द्विपक्षीय संबंधों का मुख्य कार्यक्रम था, जिसमें दोनों पक्षों ने कई संवाद किए और कई क्षेत्रों में सहयोग करने पर सहमति व्यक्त की। दो दिवसीय (30 अप्रैल -1 मई 2017) दौरा माननीय राष्ट्रपति जी के साथ बैठक करते हुए प्रधानमंत्री मोदी के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। अलोस राष्ट्रपति एर्दोगन को मानवीय सहायता प्रदान करने तथा संघर्ष प्रभावित देशों, सीरिया, सोमालिया, इराक और अन्य देशों से शरणार्थियों की मेजबानी करने में उनके उत्कृष्ट योगदान हेतु मानद उपाधि (ऑनोरिस कॉसा) जामिया मिल्लिया इस्लामिया (केंद्रीय विश्वविद्यालय) से सम्मानित किया गया। माननीय उपराष्ट्रपति और विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने भी राष्ट्रपति एर्दोगन से मुलाकात की।

दोनों नेताओं के संयुक्त राष्ट्रपति के बयान में दोनों देशों के बीच घनिष्ठ तथा ऐतिहासिक संबंधों को रेखांकित किया गया। मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी[1] ने कहा कि संस्कृति और भाषा के संबंध में हमारे समाजों को सैकड़ों वर्षों से जोड़ते हैं। लगभग 6 बिलियन डॉलर का हमारा द्विपक्षीय व्यापार कारोबार हमारी अर्थव्यवस्थाओं में समानता के लिए पूर्ण न्याय नहीं करता है। जाहिर है, दोनों ओर का व्यापार और उद्योग बहुत कुछ कर सकता है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि तुर्की के कब्ज़े से बढ़ते भारत में निहित विविध और अच्छे अवसरों का दोहन करने के लिए त्वरित होगा। उन्होंने यह भी कहा कि हमारे समाज हर दिन नए अवसरों और चुनौतियों का सामना करते हैं। विशेष रूप से, आतंकवाद लगातार बढ़ रही हमारी साझा चिंता है। मैंने इस विषय पर राष्ट्रपति के साथ व्यापक बातचीत की। दोनों नेता इक्कीसवीं सदी की दुनिया को प्रतिबिंबित करने हेतु संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आवश्यकता की पहचान करते हैं, न कि इस सदी की। भारत- तुर्की बिजनेस समिट में अपने भाषण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा:[2] द्विपक्षीय भागीदारी को बढ़ाने की बहुत बड़ी संभावनाएं और अवसर हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत के एमटीसीआर की सदस्यता और परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह और वासेनार व्यवस्था में शामिल होने हेतु आवेदन के लिए राष्ट्रपति एर्दोगन को धन्यवाद दिया। काउंटर टेररिज्म पर दोनों नेताओं ने सामान्य चिंता के अन्य अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान-प्रदान किया, विशेष रूप से आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई पर। दोनों देशों ने 2017-2020 के लिए सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम, भारत के विदेशी सेवा संस्थान और तुर्की की कूटनीति अकादमी के बीच

सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन, तुर्की गणराज्य की सरकार और भारत गणराज्य सरकार के बीच समझौता, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) के बीच राजनयिक मिशन या कांसुलर पोस्ट के सदस्यों और समझौता ज्ञापन के परिवार के सदस्यों के लिए, भारत और सूचना और संचार प्रौद्योगिकी प्राधिकरण (आईसीटीए), तुर्की और प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया (पीटीआई) और तुर्की की अनादोलु एजेंसी (एए) के बीच सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए।

11 जुलाई 2017 को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तांबुल में 22वीं विश्व पेट्रोलियम कांग्रेस में भाग लेने के लिए इस्तांबुल का दौरा किया, जहां उन्होंने 11 जुलाई को तुर्की के ऊर्जा मंत्री बेराअलैबारक के साथ बैठकें भी कीं।

4.5 फिलिस्तीन

महामहिम फिलिस्तीन के राष्ट्रपति श्री महमूद अब्बास, भारत के राष्ट्रपति श्री प्रणव मुखर्जी के निमंत्रण पर 14 से 17 मई, 2017 तक भारत की यात्रा पर थे। यह उनकी पांचवीं यात्रा थी और भारत की तीसरी राज्यकीय यात्रा थी। इससे पहले उन्होंने सितंबर 2015 में न्यूयॉर्क में यूएनजीए में हाशिये के मुद्दे पर पीएम मोदी के साथ महत्वपूर्ण बैठक की थी। राष्ट्रपति अब्बास ने फिलिस्तीन के बीच 15 मई को नोएडा में सी-डैक का दौरा किया, जो फिलिस्तीन में भारत द्वारा बनाया जा रहा इंडिया टेक्नो पार्क और इंडियन आईटी उद्योग है। उन्होंने भारतीय इस्लामी केंद्र में व्याख्यान भी दिया। यात्रा के दौरान दोनों पक्षों ने संबंधों के पूर्ण विस्तार की समीक्षा की। भारत ने कई मुद्दों पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के अलावा फिलिस्तीन को तकनीकी और वित्तीय सहायता का आश्वासन दिया।

4.6 कतर

कतर के विदेश मामलों के मंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुलरहमान अल-थानी 25-26 अगस्त को भारत आए थे। कतर के गणमान्य जन की मेजबानी विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज द्वारा की गई थी। उन्होंने 26 अगस्त को प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की, जिसके दौरान द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मामलों से संबंधित पारस्परिक हित के मामलों पर चर्चा की गई। दोनों पक्षों ने उच्च स्तरीय द्विपक्षीय यात्राओं के दौरान लिए गए प्रमुख निर्णयों के बाद प्रगति की समीक्षा की, जो दोनों देशों के बीच पारस्परिक रूप से लाभकारी साझेदारी के निर्माण में योगदान दे रहे हैं।

भारत ने निर्बाध ऊर्जा विशेष रूप से एलएनजी की आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु कतर को धन्यवाद दिया, जबकि कतरी मंत्री ने 6,30,000 मजबूत भारतीय समुदाय के योगदान की सराहना की, जो कतर में सबसे बड़ा प्रवासी समुदाय है। उन्होंने भारतीय श्रमिकों की सुरक्षा, कल्याण और कुशलता का आश्वासन दिया तथा नए श्रम कानूनों के बारे में जानकारी दी, जो प्रवासी श्रमिकों के पक्ष में हैं।

मंत्री ने कतर के बुनियादी ढांचे के विकास में परियोजना निर्यात के माध्यम से भारतीय कंपनियों की भागीदारी का भी स्वागत किया, जिसमें फीफा 2022 से संबंधित बुनियादी ढाँचा शामिल है। मंत्री ने क्षेत्रीय मुद्दों पर भी चर्चा की और भारतीय पक्ष ने भारत की स्थिति के बारे में भी बताया कि खाड़ी क्षेत्र में शांति तथा स्थिरता उसके राष्ट्रीय हित के लिए कितनी महत्वपूर्ण है। दोनों पक्षों ने आतंकवाद, उग्रवाद और बढ़ते धार्मिक असहिष्णुता पर भी चर्चा की, जो न केवल क्षेत्रीय स्थिरता के लिए, बल्कि वैश्विक शांति और व्यवस्था के लिए भी गंभीर खतरा है। भारत का विचार है कि दलों को रचनात्मक बातचीत और शांतिपूर्ण वार्ता की प्रक्रिया के माध्यम से अपने मतभेदों को हल करना चाहिए।

4.7 ओमान की सल्तनत

महामहिम श्री यूसुफ बिन अलवाई बिन अब्दुल्ला, विदेश मामलों के मंत्री, ओमान की सल्तनत ने माननीय विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज के निमंत्रण पर 2-3 अप्रैल 2017 को भारत की आधिकारिक यात्रा की। यात्रा के दौरान, दोनों पक्षों ने पारस्परिक हित के द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और अन्य मुद्दों पर चर्चा की।

4.8 जॉर्डन

27-28 दिसंबर को आयान अल सफादी, जॉर्डन के विदेशी मामलों के मंत्री ने फरवरी 2018 में किंग जॉर्डन की भारत यात्रा की तैयारी हेतु भारत का दौरा किया। मंत्री ने इस क्षेत्र में भारत की अधिक भूमिका के लिए जोर दिया। विश्व मामलों की भारतीय परिषद में अपने व्याख्यान के दौरान, मंत्री ने 'अवसर की कमी' पर जोर दिया, जो इस क्षेत्र में अस्थिरता के मूल कारण को दूर करने के लिए एक खतरा और आग्रहपूर्ण देश है। उन्होंने आतंकवाद, उग्रवाद और कट्टरता का मुकाबला करने के लिए एक एकीकृत नीति की आवश्यकता को भी रेखांकित किया।

अफ्रीका

5. अफ्रीका

उत्तर अफ्रीका

उत्तरी अफ्रीका (मिस्र, मोरक्को, ट्यूनीशिया, लीबिया और अल्जीरिया) के लिए वर्ष 2017 में आर्थिक और राजनीतिक दोनों मोर्चों पर भयानक तस्वीर दिखाई दी। यह क्षेत्र संबंधित शासनों द्वारा किए गए सभी दावों के बावजूद राजनीतिक स्थिरता या आर्थिक समृद्धि में प्रमुख स्थान बनाने में विफल रहा। मिस्र में 2017 में कई आतंकवादी हमलें हुए और उनमें से कुछ हाल के इतिहास में सबसे बुरे हमलों में से थे। आर्थिक मोर्चे पर, भारी करों को लागू करने और बुनियादी वस्तुओं पर सब्सिडी हटाने के कारण बड़े पैमाने पर विरोध हुआ। इसी तरह मोरक्को और ट्यूनीशिया आर्थिक प्रगति का वांछित स्तर नहीं बना सके, लेकिन राजनीतिक रूप से ये दोनों राष्ट्र सापेक्ष स्थिर और शांत बने रहे। लीबिया में सबसे खराब राजनीतिक और आर्थिक गतिरोध देखा गया था, जहां राज्य की संस्थाएं थम रही हैं और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में जल्द सुधार न होने के लक्षण के साथ लगातार गिरावट के संकेत है।

5.1 मिस्र

वर्ष 2017 में राष्ट्रपति मोर्सी के सत्ता से बाहर होने के बाद से वर्ष 2017 मिस्र के लिए सबसे खराब साल था। 2017 के अप्रैल महीने में पहला बड़ा हमला हुआ था जब टांटा और अलेक्जेंड्रिया शहर में दो कॉप्टिक ईसाई चर्चों पर हमला किया गया था, जिसमें पैंतालीस व्यक्ति मारे गए और कई घायल हुए। शहर टांटा में हुए हमले में 27 लोग मारे गए थे जबकि शहर अलेक्जेंड्रिया में 15 लोग मारे गए थे। उसके तुरंत बाद राष्ट्रपति अल-सीसी ने देश में देशव्यापी आपातकाल के विस्तार की घोषणा की।

शुक्रवार की नमाज के दौरान 24 नवंबर, 2017 को एक और हमला हुआ, जब सशस्त्र हमलावरों के एक समूह ने उत्तरी सिनाई के रावडा गांव में बेलाल मस्जिद में उपासकों पर हमला किया, जिसमें 27 बच्चों सहित 311 नागरिकों की मौत हो गई और 128 घायल हो गए।

राजनयिक मोर्चे पर देश में प्रमुख विकास हुआ जब मिस्र ने एयूई, सऊदी अरब और बहरीन के साथ जून 2017 में कतर के साथ अपने राजनयिक संबंध में कटौती करने की घोषणा की। बहिष्कार करने वाले देशों ने कहा कि वे कतर के साथ भूमि, हवाई और समुद्री यातायात को रोक देंगे, अपने राजनयिकों को अस्वीकार करेंगे और राष्ट्रों को छोड़ने के लिए कतरी नागरिकों को आदेश दें। कतर के खिलाफ लगाए गए कई आरोपों में से एक क्षेत्र में आतंकवाद को खत्म करने और एमबीएच के सदस्यों को आश्रय देने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था और आधिकारिक तौर पर आतंकवादी संगठन मिस्र घोषित किया गया था।

प्रमुख शक्ति के साथ अपने संबंधों पर, एक प्रमुख राजनीतिक और रणनीतिक समूह वापस आ गया जब अमेरिका, मिस्र के इस क्षेत्र के सबसे पुराने रणनीतिक सहयोगी ने सितंबर 2017 में घोषणा की थी कि यह मिस्र को 95.7 मिलियन डॉलर की सहायता और बाद में 195 मिलियन डॉलर की सहायता देगा, क्योंकि देश के मानवाधिकारों को लागू करने में कमी आई है।

मिस्र द्वारा फिलिस्तीनी-फिलिस्तीनी संवाद को प्रायोजित किया और हमास तथा फतह (दो युद्धरत गुटों) को काहिरा में बातचीत के लिए तैयार करने के कारण फिलिस्तीन के साथ अपने संबंध पर सकारात्मक विकास हुआ। मिस्र फिलिस्तीन-इज़राइल संकट में एक महत्वपूर्ण कारक बना रहा और फिलिस्तीनी एकता के लिए मिस्र के राजनीतिक नेतृत्व की उत्सुकता ने कई सकारात्मक परिणाम हासिल किए।

राजनीतिक मोर्चे पर मिस्र ने मार्च 2018 में राष्ट्रपति चुनाव कराने की घोषणा की। मिस्र के राष्ट्रपति अल-सिसी मार्च 2018 के महीने में आगामी चुनाव में दूसरी बार राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ेंगे। केवल वह श्री मुस्तफा एकमात्र दावेदार है जो उन्हें चुनौती देंगे। पहले के कई उम्मीदवारों ने अपना नामांकन वापस ले लिया है या चुनाव छोड़ने के लिए मजबूर हो गए हैं। देश की राष्ट्रीय राजनीति में एक और दुर्जेय बल एमबीएम ने चुनाव का बहिष्कार करने का आह्वान किया है।

आर्थिक क्षेत्र में गिरावट के वर्षों के बाद मिस्र की अर्थव्यवस्था वापस पटरी पर आ गई है देश में राजनीतिक उथल-पुथल के बीच लगभग छह वर्षों तक ऋणात्मक वृद्धि हुई थी। मिस्र की अर्थव्यवस्था में 2017 के दौरान सकारात्मक विकास देखा गया, इस प्रकार मजबूत संदेश मिलता है

कि मिस्र की अर्थव्यवस्था सही रास्ते पर है। वित्त वर्ष 2016-2017 के दौरान मिस्र के आर्थिक प्रदर्शन के संकेतक सरकार द्वारा "स्टार्ट मिस्र", "योर आइडिया इज योर कंपनी" और "इस्टैब्लिस योर ओन सर्विस" जैसी कुछ पहल के साथ आने के बाद सभी क्षेत्रों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।

भारत - मिस्र द्विपक्षीय संबंध

द्विपक्षीय राजनीतिक और आर्थिक मोर्चे पर भारत और मिस्र के बीच वर्ष 2017 में बहुत कुछ नहीं हुआ। लेकिन 2017 में दोनों देशों के बीच कुछ सांस्कृतिक सक्रियता देखी गई। काहिरा में मौलाना आजाद सांस्कृतिक केंद्र, मिस्र में भारतीय दूतावास के सांस्कृतिक विंग ने रवींद्रनाथ टैगोर की 156वीं जयंती मनाने के लिए टैगोर सांस्कृतिक उत्सव का आयोजन किया। यह त्यौहार 8-12 मई 2017 के बीच मिस्र के संस्कृति मंत्रालय, काहिरा ओपेरा हाउस, सांस्कृतिक उत्पादन क्षेत्र, डांसर्स गिल्ड और मिस्र में भारतीय समुदाय संघ के सहयोग से आयोजित किया गया था।

5.2 मोरक्को का साम्राज्य

स्थिरता के मोर्चे पर सतत रहने के बाद देश में आखिरकार अप्रैल 2017 में एक नई गठबंधन सरकार बनी। मोरक्को के साम्राज्य को आखिरकार इस्लामिक पार्टी ऑफ जस्टिस एंड डेवलपमेंट के तहत प्रधानमंत्री ओथमानी के रुप में एक नई गठबंधन सरकार मिली। राष्ट्रीय राजनीति में गतिरोध के छह महीने के अंत में नई सरकार का गठन हुआ। सरकार बनाने के लिए श्री ओथमानी को रूढ़िवादी, समाजवादी और समर्थक बाजार दलों के साथ गठजोड़ करना था। यहां यह उल्लेखनीय है कि विद्रोह के बीच पूर्व उपाय के रूप में मोरक्को के राजा ने राजनीतिक सुधारों की एक श्रृंखला शुरू की थी।

भारत- मोरक्को द्विपक्षीय संबंध

मोरक्को के साथ द्विपक्षीय मोर्चे पर, भारत में 2017 में कुछ सांस्कृतिक बातचीत हुई। एफआईसीएमईसी नादोर फिल्म महोत्सव के 6 वें संस्करण का आयोजन 07-12 नवंबर 2017 को नादोर शहर में 'मेमोरी ऑफ ओशन' विषय पर किया गया था। इस कार्यक्रम में भारत को अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था।

5.3 ट्यूनीशियाई गणराज्य

असुरक्षा और राजनीतिक अस्थिरता के कारण गिरावट के वर्षों के बाद ट्यूनीशिया में पर्यटन उद्योग में वृद्धि वापस आ गई है। राष्ट्रीय ट्यूनीशियाई पर्यटन कार्यालय (ओओनटीटी) के नवीनतम आंकड़े बताते हैं कि 31 जुलाई तक 3.6 मिलियन पर्यटक ट्यूनीशिया आए, जो पिछले वर्ष से 27% की वृद्धि थी। इसी अवधि में यूरोप से आने वाले पर्यटकों में 15% की वृद्धि हुई। बाद में यह आंकड़ा फ्रांस और जर्मनी के बाद ट्यूनीशिया की यात्रा के खिलाफ एक सलाहकार की वापसी से और बढ़ गया, जिसने पहले ही प्रतिबंधों में छूट दी थी।

राजनीतिक मोर्चे पर ट्यूनीशिया को राजनीतिक विरोध और देशव्यापी बहिष्कार की श्रृंखला का सामना करना पड़ा। उनमें से एक मई 2017 के महीने में हुई थी जब बड़ी संख्या में लोग आर्थिक सुलह कानून के विरोध में सड़क पर उतर आए थे। राष्ट्र के विभिन्न हिस्सों में प्रस्तावित आर्थिक सुलह कानून के खिलाफ प्रदर्शन हुए, जो पूर्व शासन के तहत भ्रष्टाचार के आरोपी व्यापारियों तथा सिविल सेवकों को आम माफ़ी प्रदान करेंगे। द्विपक्षीय मोर्चे पर शरणार्थियों के मुद्दे पर अप्रैल 2017 में मोरक्को और अल्जीरिया के बीच दरार पैदा हुई। मोरोक्को और अल्जीरिया ने मोरक्को की सरकार के आरोप के बाद एक-दूसरे के राजदूतों और व्यापारिक आरोपों को तलब किया कि अल्जीरियाई अधिकारियों ने 54 सीरियाई लोगों को "अवैध रूप से प्रवेश" करने हेतु मोरक्को में आपसी सीमा पर तनाव पैदा करने वाला कदम बताया था। मोरक्को ने कहा कि सीरियाई लोगों ने 17 अप्रैल से 19 के बीच सीमावर्ती शहर फिगुइग के माध्यम से मोरक्को में प्रवेश करने का प्रयास किया। इसने अल्जीरिया पर मोरक्को की सीमा पार करने के लिए मजबूर करने का आरोप लगाया।

भारत-ट्यूनीशिया द्विपक्षीय संबंध

भारत और ट्यूनीशिया के बीच द्विपक्षीय मोर्चे पर ट्यूनीशिया के विदेश मंत्री श्री खेमईस झिनौई ने श्रीमती सुषमा स्वराज, भारत की विदेश मंत्री के साथ 12वीं भारत-ट्यूनीशिया संयुक्त आयोग की बैठक की अध्यक्षता के लिए 28-31 अक्टूबर, 2017 के बीच भारत का दौरा किया। उनके साथ व्यापार, उद्योग और निवेश के विविध क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने वाला एक उच्च-स्तरीय व्यापार प्रतिनिधिमंडल भी आया था।

विदेश मंत्री ने माननीय प्रधानमंत्री को आमंत्रित किया। आधिकारिक बैठकों के अलावा, ट्यूनीशिया के विदेश मंत्री ने वाणिज्य तथा उद्योग के सर्वोच्च कक्षों द्वारा आयोजित व्यावसायिक सत्रों को संबोधित किया और विश्व मामलों की भारतीय परिषद में "नई ट्यूनीशिया और चुनौतियों और वैश्विक खतरों के युग में उभरते लोकतंत्र" पर एक भाषण दिया।

5.4 लीबिया राज्य

लीबिया के डर्ना शहर पर मई 2017 में मिस्र की वायु सेना द्वारा आईएसआईएस को खदेड़ने के लिए भारी हवाई हमला किया गया था। इस्लामिक स्टेट समूह द्वारा एक बस में कई ईसाइयों पर घात लगाने और उन्हें मारने की जिम्मेदारी लेने के बाद मिस्र की सेना ने डर्ना में कथित जिहादी प्रशिक्षण शिविरों के खिलाफ हवाई हमले किए।

जून 2017 में अचानक राजनीतिक विकास में, लीबिया के मिलिशिया समूह ने कहा कि उसने सैफ अल-इस्लाम गद्दाफी को मुक्त कर दिया, जिसका पिता-गद्दाफी द्वारा उसका पालन पोषण किया जा रहा था और वह देश के दिवंगत तानाशाह मुअम्मर गद्दाफी का सबसे बड़ा पुत्र था। उन्हें जेल में कैद में पांच साल से अधिक समय के बाद रिहा कर दिया गया था। ज़िंटन स्थित अबू बक्र अल-सादिक ब्रिगेड ने कहा कि पूर्वी-पूर्वी संसद द्वारा पिछले साल पारित किए गए माफी कानून के तहत सैफ

अल-इस्लाम को रिहा कर दिया है। समूह ने कहा कि उन्होंने सैफ अल-इस्लाम मुअम्मर गद्दाफी को मुक्त करने का फैसला किया। वह अब स्वतंत्र है और ज़िंटन शहर छोड़ दिया है।

जुलाई 2017 में, लीबिया के पूर्वी कमांडर खलीफा हफ़्टर ने घोषणा की कि इस्लामिक स्टेट समूह को वर्षों से लंबी लड़ाई के बाद बेंगाज़ी से हटा दिया गया है। उन्होंने कहा कि उनकी सेनाओं ने तीन साल के अभियान के बाद प्रतिद्वंद्वी सशस्त्र समूहों से लीबिया के दूसरे शहर बेंगाजी का पूरा नियंत्रण ले लिया है। श्री हफ़्फ़ार की स्वयंभू लीबिया नेशनल आर्मी (एलएनए) और इस्लामिक आतंकवादियों और अन्य सेनानियों की सरणी के बीच बेनगाज़ी की लड़ाई एक व्यापक संघर्ष का हिस्सा रही है क्योंकि 2011 में मजबूत मुअम्मर गद्दाफी के पतन के बाद लीबिया में अराजकता फैल गई थी।

अक्टूबर 2017 में, बेंगाजी में अमेरिकी राजदूत के संदिग्ध हत्यारे को पकड़ लिया गया था। आधिकारिक स्रोत सीन लीबिया ने कहा कि लीबिया में अमेरिकी विशेष बलों ने 2012 में बेंगाजी में अमेरिकी राजनयिक परिसर पर हमले में शामिल होने के संदेह में एक व्यक्ति को पकड़ा है।

उप-सहारा अफ्रीका

उप-सहाराअफ्रीकाअफ्रीकाने2017
मेंवर्षकेदौरानमेंबड़ेराजनीतिकपरिवर्तनदेखे।अफ्रीकाकेराष्ट्रपतिजैकबजुमाकोअफ्रीकीराष्ट्रीयकांग्रेस (एएनसी) द्वाराएकनएनेतासिरिलरामाफोसाकेचुनेजानेकेबाददोपांचसालकेकार्यकालकेबादपदसेहटनापड़ा।जुमाऔरउनके सहयोगियोंपरकईभ्रष्टाचारकेआरोपलगाएगएथे, जिसनेबड़ेविरोधप्रदर्शनोंकोजन्मदियाऔरएएनसीपार्टी मेंगहरेविभाजनपैदाकिए।इनविवादोंनेदेशकेआर्थिकप्रदर्शनपरअसरडालाऔरदक्षिणअफ्रीकामेंनीतिनिर्माणकोभी प्रभावितकिया।जिम्बाब्वेने37 वर्षोंकेबादएकबड़ीराजनीतिकउथल-पुथलदेखी, रॉबर्टमुगाबेकोसैन्यतख्तापलटकेबादजिम्बाब्वेकेराष्ट्रपतिकेरूपमेंपदछोड़नापड़ा।अंगोलामें, अफ्रीकाकेसबसेलंबेराजनैतिकशासनकालमेंसेएककाअंतहुआ, डॉससैंटोसकेस्थानपररक्षामंत्रीजोआओमैनुएलगोंगलवसलौरेंगोकोदेशकेतीसरेराष्ट्रपतिकेरूपमेंप्रतिस्थापितकि यागया,
जिसकेबादअंगोलनकानूनयहकहताहैकिजीतनेवालीपार्टीकाशीर्षउम्मीदवारस्वचालितरूपसेराष्ट्रपतिबनजाताहै। साहसिक राजनीतिक कदम उठाते हुए, डॉस सैंटोस परिवार के व्यापक संरक्षण नेटवर्क को नष्ट करने के प्रयास में लूर्गेनो ने 14 नवंबर को राज्य के स्वामित्व वाले तेल उद्यम, सोनांगोल के प्रमुख के पद से पूर्व राष्ट्रपति की बेटी, इसाबेल डॉस सैंटोस को अप्रत्याशित रूप से पदच्युत कर दिया। केन्यामेंउहुरूकेन्याटा28 नवंबरकोदूसरीबारकार्यकालकेलिएकेन्याकेराष्ट्रपतिबने, पहलीबार26 अक्टूबरकेचुनावमेंअपनीजीतकोरद्दकरनेकेलिएसुप्रीमकोर्टकेफैसलेकेबाद बने थे।लंबेसमयतकचुनावकीअवधिनेराजनीतिकअनिश्चितताऔरछिटपुटहिंसाउत्पन्नकी, जिसनेअर्थव्यवस्थाकोनकारात्मकरूपसेप्रभावितकिया।

आर्थिक मोर्चे पर, उप-सहारा अफ्रीका में विकास 2016 में तेजी से 1.3 प्रतिशत की गिरावट के बाद2017में 2.7 प्रतिशत पर पहुंच गया। इस वृद्धि का नेतृत्व क्षेत्र की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं,

अंगोला, नाइजीरिया और दक्षिण अफ्रीका ने किया, और वृद्धि को ऊर्जा और धातुओं की कीमतों में, अनुकूल वैश्विक वित्त पोषण की स्थिति, गैर-ऊर्जा क्षेत्रों में सुधार, बढ़ती और बढ़ी हुई पूंजी प्रवाह सहित समर्थन मिला।

5.1 पश्चिम अफ्रीका

प्रमुख तेल तथा गैस उत्पादकों के रूप में पश्चिम अफ्रीकी देशों के बढ़ते महत्व और साथ में आतंकवादी गतिविधियों के बढ़ने के कारण 2017 में इस क्षेत्र ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ध्यान आकर्षित किया। पश्चिम अफ्रीका को राजनीतिक, सुरक्षा, आर्थिक और सामाजिक विकास के क्षेत्र में रचनात्मक और नकारात्मक दोनों घटनाओं का सामना करना पड़ा।

राजनीतिक मोर्चे पर, इस क्षेत्र के सबसे महत्वपूर्ण देशों में से एक यानी लाइबेरिया 10 अक्टूबर 201794 को निर्विघ्न और शांतिपूर्ण चुनावों का गवाह बना।[94] पूर्व अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल स्टार जॉर्ज वॉह, नोबेल पुरस्कार विजेता और 4.5 मिलियन आबादी वाले देश में अफ्रीका की पहली लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई महिला राष्ट्रपति एलेन जॉनसन- सिर्लेफ जहां 2.18 मिलियन पंजीकृत मतदाताओं ने लोकतांत्रिक मतदान के लिए अपनी प्रतिबद्धता दिखाई। भले ही एलेन जॉनसन-सिर्लेफ को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त है, जिन्होंने युद्धग्रस्त देश में स्थिरता लाने का कार्य किया, फिर भी उन्हें भ्रष्टाचार के विभिन्न आरोपों का सामना करना पड़ा, जो अंततः उनके पतन का कारण बना। उदारवादियों ने जॉर्ज वॉह से बहुत उम्मीदें की, जिन्हें उच्च स्तर पर पहुंच चुकी बेरोजगारी को उखाड़ने और देश की कमजोर स्वास्थ्य प्रणाली के पुनर्गठन हेतु काम करना है।[95]

क्षेत्रीय शांति और सुरक्षा के क्षेत्र में, वर्ष 2017 को उतार-चढ़ाव भरी घटनाओं द्वारा चिह्नित किया गया था। विशेष रूप से इस क्षेत्र को आतंकवादी इस्लामी समूह बोको हराम द्वारा कई सुरक्षा चुनौतियों का सामना करना पड़ा। समूह का विद्रोह नाइजीरिया, कैमरून, चाड और नाइजर क्षेत्र के आसपास बढ़ रहा था। आतंकी समूह ने अत्यधिक गरीबी में रहने वाले बच्चों को भर्ती करने की रणनीति अपनाई और उन्हें अपने हिंसक एजेंडे में शामिल किया। 25 जुलाई 2017 को, आतंकवादी समूह ने नाइजीरिया के राष्ट्रीय पेट्रोलियम निगम के कर्मचारियों के एक काफिले पर हमला किया, जो उत्तर-पूर्वी राज्य बोर्नो में स्थित मैगुमेरी क्षेत्र में भू-वैज्ञानिकों से मिलकर बना था।[96] हमले के दौरान लगभग 50 लोग मारे गए थे। हमले के बाद, नाइजीरियाई सरकार ने चाड बेसिन के पास तेल अन्वेषण परियोजना को रोकने का फैसला किया था। 21 नवंबर 2017 को, बोको हराम ने नाइजीरिया के उत्तर-पूर्वी हिस्से में स्थित आदमवा राज्य के मुबी में आत्मघाती हमला किया। राष्ट्रपति मुहम्मदु बुहारी के 2015 में सत्ता में आने के बाद कुल कार्यवाहियों में 50 लोग शामिल थे, जिन्हें सबसे क्रूर हमले में से एक माना जाता था। हालांकि, राष्ट्रपति मुहम्मदु बुहारी के अधीन सरकार ने दावा किया था कि आतंकवादी समूह, बोको हराम की हिंसक गतिविधियों को खत्म करने में सफल रही है। लाखों नाइजीरियाई लोगों को अपने देश से भागने पर मजबूर होना पड़ा।

आतंकवादी हमलों के अलावा, सरकार और नागरिकों के एक वर्ग के बीच झड़पों की बढ़ती संख्या को इस क्षेत्र में बढ़ती सुरक्षा चिंता के रूप में देखा गया।

पूर्व-लड़ाकों द्वारा 12 -16 मई से पांच दिन काविद्रोह कोटे-डी'वायर में हुआ, जिसने पूरे देश को पंगु बना दिया। बोनस के भुगतान में कमी के कारण, देश के दूसरे सबसे बड़े शहर यानी बॉउके में जनवरी 2017 की शुरुआत में सरकार के खिलाफ विद्रोहियों ने विद्रोह कर दिया और बाद में डलाओ, कोरहोगो जैसे अन्य शहरों में भी इसका विस्तार हो गया। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस स्टेशनों से हथियार जब्त किए और गोलाबारी की। कोटे डी'वायर में खंडित और हताश सशस्त्र बलों ने आइवरियन सेना के परिवर्तन के लिए बुलाया।[97] सत्तारूढ़ ग्नसिंगबे परिवार वंश के खिलाफ हिंसक प्रदर्शन अगस्त 2017 में टोगो में शुरू हुआ।[98] विपक्षी पीएनपी पार्टी ने राष्ट्रपति फ्योर ग्नसिंगबे को पद छोड़ने के लिए कहा क्योंकि वह पिछले 15 वर्षों से सत्ता में थे। प्रदर्शनकारियों ने विपक्ष पर अंकुश लगाने के लिए 1992 में वर्तमान राष्ट्रपति के पिता ग्नसिंगबेइदादेमा द्वारा पेश किए गए संविधान के प्रतिस्थापन के लिए भी कहा।[99]

94ECOWAS observation mission satisfied with liberian election, calls for calm, ECOWAS, , 29 December 2017, http://www.ecowas.int/ecowas-observation-mission-satisfied-with-liberian-election-calls-for-calm/, accessed 5 February, 2018

95"George Weah Wins Liberia Election", New York Times, 28 December 2017,https://www.nytimes.com/2017/12/28/world/africa/george-weah-liberia-election.html accessed 5 February 2018.

96AU, UN, AND ECOWAS' statement on Terrorist Attack against a Convoy of Nigerian National Petroleum Company (NNPC) in Maiduguri, ECOWAS, 30 July 2017, ECOWAS, http://www.ecowas.int/au-un-and- ecowas-statement-on-terrorist-attack-against-a-convov-of-nigerian-national-petroleum-companv-nnpc-in- maiduguri/, accessed 2 February 2018.

कई अंतरराष्ट्रीय नेताओं ने 2017 में पश्चिम अफ्रीकी क्षेत्र का दौरा किया, जो अफ्रीका के साथ निकट संबंध रखने की उनकी इच्छा को दर्शाता है। 19 मई 2017 को फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रोन ने आतंकवाद से लड़ने और नाजुक अफ्रीकी देश में शांति प्रक्रिया के पुनर्निर्माण के लिए माली में तैनात फ्रांसीसी सैनिकों का दौरा किया। फ्रांस ने उत्तरी और पश्चिमी अफ्रीका में इस्लामी आतंकवादियों द्वारा हिंसा को खत्म करने की कसम खाई। इसने एक समन्वित और स्थायी तरीके से आतंकवाद का मुकाबला करने की दिशा में अपना प्रयास बढ़ाया। साहेल क्षेत्र में सुरक्षा से निपटने के लिए फ्रांस के सहयोग से पांच अफ्रीकी देशों द्वारा एक नया बहुराष्ट्रीय सैन्य बल बनाया गया था।[100]2 जुलाई 2017 को माली की राजधानी बामाको में आयोजित एक क्षेत्रीय शिखर सम्मेलन में जी 5 सहेल नेताओं यानी माली, मॉरिटानिया, बुर्किना फासो, नाइजर और चाड की उपस्थिति में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रॉन ने घोषणा की कि फ्रांस नई सेना को $9 मिलियन प्रदान करेंगे, जो संयुक्त रूप से फ्रांसीसी सैनिकों के साथ काम करते हैं और माली यानी एमआईएनयूएसएमएमें संयुक्त राष्ट्र शांति सेना के बल रखते हैं।[101]

पश्चिम अफ्रीकी राज्यों के आर्थिक समुदाय (ईसीओडब्ल्यूएएस) शिखर सम्मेलन के इतिहास में पहली बार, एक गैर-अफ्रीकी नेता यानी इज़राइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने 4 जून 2017को इजरायल और पश्चिम अफ्रीका के बीच संबंधों को मजबूत बनाने के लिए लाइबेरिया की राजधानी मोनरोविया में 51वेंईसीओडब्ल्यूएएस शिखर सम्मेलन के प्रमुखों को संबोधित किया।[102] इजरायल के प्रधानमंत्री ने अफ्रीका में विकास प्रक्रिया की सहायता के लिए प्रौद्योगिकी, कृषि और सुरक्षा के क्षेत्रों में सहयोग की घोषणा की।

इस वर्ष के अंत तक, हमने देखा है कि अफ्रीका में कई देशों ने स्पष्ट संकेत दिया कि वे अन्य देशों के साथ विशेष रूप से यूरोपीय देशों के साथ अपने जुड़ाव में समानता की इच्छा रखते हैं। आबिदजान में पांचवें एयू-ईयू शिखर सम्मेलन के बाद, घाना के राष्ट्रपति ने अफ्रीकी देशों की स्वायत्तता पर स्पष्ट बयान दिया जब फ्रांसीसी राष्ट्रपति उनके देश के दौरे पर थे।[103] उन्होंने इस तथ्य पर अपने विचार व्यक्त किए कि घाना के स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्र को यूरोपीय देशों द्वारा वित्तपोषित किया जा रहा है और घाना के लिए इस निर्भरता को खत्मकरने तता अपनी मूल आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए स्वतंत्र रूप से बाहर आने काअच्छा समय है।

97"Cote d'Ivoire: The mutiny may be over, but the army's problems are not", African Arguments, 17 May 2017, http://africanarguments.org/2017/05/17/cote-divoire-the-mutinY-maY-be-over-but-the-armYS-problems-are-not/ accessed 15 January 2018

98Message of Sympathy from the ECOWAS Commission President in the wake of violent demonstrations in Togo. ECOWAS. 23 October 2017. http://www.ecowas.int/message-of-svmpathv-from-the-ecowas-commission-president-in-the-wake-of-violent-demonstrations-in-togo/ accessed 3 February 2017.

99"Two killed in Togo in protests against 50-year ruling dynasty", Reuters, 19 August 2017, https://www.reuters.com/article/us-togo-protests/two-killed-in-togo-in-protests-against-50-vear-ruling-dvnastv-idUSKCN1 AZ0KM accessed 3 February 2018.100Aljazeera. 2 July 2017. http://allafrica.com/stories/201707030730.html accessed 1 March 2017.

101Diallo, T, "French and West African presidents launch Sahel force", Reuters, 3 July 2017, https://af.reuters.com/article/topNews/idAFKBN19O0KE-OZATP Accessed 2 February 2018.

102Fulbright and Ahren, "Seeking to boost ties, Netanyahu meets with African leaders", The Times of Israel, 4 June 2017. https://www.timesofisrael.com/seeking-to-boost-ties-netanyahu-meets-with-african-leaders/

भारत-पश्चिम अफ्रीका द्विपक्षीय संबंध

वर्ष 2017 में, गिनी को छोड़कर भारत और पश्चिम अफ्रीकी देशों के बीच कोई उच्च-स्तरीय यात्रा नहीं हुई थी। गिनी के विदेश मंत्री श्री ममाडी ताउरे द्वारा3-6 नवंबर, 2017 तक भारत का दौरा करने के दौरान भारत और गिनी ने एक नई मित्रता स्थापित की। दोनों नेताओं ने देशों के बीच द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने हेतु विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। गिनी के आर्थिक विकास के लिए भारत की सहायता की सराहना करते हुए, विदेश मंत्री ने व्यापार सहयोग हेतु भारतीय दानदाताओं और निवेशकों का स्वागत किया। इस बीच, भारतीय विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज ने गिनी में लाइन्स ऑफ क्रेडिट और क्षमता निर्माण की पहल पर अपनी खुशी व्यक्त की। भारत सरकार ने गिनी को नई दिल्ली में

आयोजित होने वाले अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की शिखर स्तरीय बैठक में भाग लेने हेतु आमंत्रित किया जिसकी गिनी ने हाल ही में पुष्टि की है।[104]

5.2 पूर्वी अफ्रीका

पूर्वी अफ्रीका में वर्ष 2017 में कुछ महत्वपूर्ण राजनीतिक घटनाक्रम देखें गए। बुरुंडी अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय (आईसीसी) से बाहर निकलने वाला पहला राष्ट्र बना, केन्या को राष्ट्रपति चुनावों के सवालों के कारण राजनीतिक अनिश्चितता का सामना करना पड़ा, और दक्षिण सूडान को संघर्ष और संघर्ष विराम के बीच संघर्षके अलावा अकाल का सामना करना पड़ा। युगांडा की संसद ने राष्ट्रपति की आयु सीमा को खत्म करने हेतु मतदान किया, और रवांडा ने 98 प्रतिशत वोटों के साथ पॉल कागमे को फिर से चुना। यह दावा किया गया था कि यह आधार अफ्रीका और पश्चिम एशिया में एस्कॉर्टिंग, शांति बनाए रखने और मानवीय सहायता जैसे मिशनों के चीन के प्रदर्शन को सुनिश्चित करेगा।

आईसीसी से बुरुंडी का निष्कासन 27 अक्टूबर, 2017 से प्रभावी हुआ।[105] हालांकि, आईसीसी बुरुंडी के क्षेत्र में या उसके नागरिकों द्वारा रोम रोम्यूट में सूचीबद्ध अपराधों पर अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग 1 दिसंबर 2004 से 26 अक्टूबर, 2017 तक कर सकता है।[106]आईसीसी अभियोजक, 25 अक्टूबर, 2017 को, बुरुंडी में और उसके बाहर बुरुंडियन नागरिकों द्वारा मानवता के खिलाफ अपराध की जांच के लिए अधिकृत है।

केन्याई राजनीतिक कैलेंडर को घरेलू राजनीति की वैधता और नियंत्रण के लिए तीव्र प्रतिस्पर्धा द्वारा चिह्नित किया गया था। केन्या में 2017 में दो राष्ट्रपति चुनाव हुए। अगस्त में पहले चुनाव में अनियमितताओं का हवाला देते हुए केन्याई सुप्रीम कोर्ट द्वारा राष्ट्रपति के रूप में उहुरू केन्याटा के फिर से चुनाव को रद्द कर दिया गया था।[107]इसी अदालत ने सर्वसम्मति से राष्ट्रपति केन्याटा के पुनर्विचार के खिलाफ दो याचिकाओं को खारिज कर दिया और 26 अक्टूबर के चुनाव को अंतिम घोषित किया। हालांकि, विरोधी नेता श्री राला ओडिंगाने चुनावों को चुनौती दी, जिससे राजनीतिक अनिश्चितता का दौर पैदा हुआ। पूरी चुनाव प्रक्रिया पर सवाल उठाया गया क्योंकि चुनाव आयुक्त चुनाव से पहले देश से भाग गये और अपनी जान को खतरा बताते हुए इस्तीफा दे दिया। श्री ओडिंगा ने भी चुनाव में भाग नहीं लिया और वापसी से पहले कुछ समय के लिए देश छोड़ दिया। उन्होंने सरकार की वैधता को चिन्हित नहीं किया।

103Africans Press, 5 December 2017, https://africanspress.org/2017/12/05/ghana-president-akufo-addo-schools- france-president-macron/ accessed 5 March 2018.

104Visit of Minister of Foreign Affairs of the Republic of Guinea to India (November 3-6. 2017). Ministry of External Affairs. 6 November 2017. http://mea. gov.in/incoming-visit-detail.htm?29092/Visit+of+Minister+of+Foreign+Affairs+of+the+Republic+of+Guinea+to+India+November+36+2017accessed 15 February 2018

105"Burundi becomes first nation to leave international criminal court", The Guardian, 28 October 2017, https://www.theguardian.com/law/2017/oct/28/burundi-becomes-first-nation-to-leave-international-criminal- court

106Situation in the Republic of Burundi. International Criminal Court. International Criminal Court. 14 March 2018. https://www.icc-cpi.int/burundi/

दक्षिण सूडान के राष्ट्रपति सल्वा कीर ने राष्ट्रीय संवाद के मद्देनजर एकपक्षीय संघर्ष विराम की घोषणा की थी, जिसकी विरोधी समूहों द्वारा आलोचना की गई थी।[108]हालांकि, शांतिकाल और युद्धकाल के बीच कई उतार-चढ़ाव के साथ, दक्षिण सूडान सरकार और विद्रोही समूहों ने दिसंबर 2017 में एक आईजीएडी (अंतर सरकारी विकास प्राधिकरण)मध्यस्थता में युद्ध विराम समझौते पर हस्ताक्षर किए।[109]क्षेत्रीय स्तर पर, आपदा आपातकालीन एजेंसी और एक्शन एड के अनुसार, पूर्वी अफ्रीका में लंबे समय तक सूखे और संघर्ष की स्थितियों की वजह से16 मिलियन से अधिक लोगों को भूख और भोजन सहायता की तत्काल आवश्यकता के बीच लाकर खड़ा कर दिया। अकाल ने इथियोपिया, सोमालिया, केन्या और दक्षिण सूडान को प्रभावित किया।[110] मौजूदा संघर्ष की स्थिति और प्रभावित लोगों के लिए सहायता के लिए बाधा के कारण स्थिति बिगड़ गई। सूखे और संघर्ष ने मिलकर क्षेत्र में ऐतिहासिक शरणार्थी संकट पैदा कर दिया। मार्च 2017 में यूएनएचसीआरने दक्षिण सूडान संकट को दुनिया का सबसे तेजी से बढ़ता शरणार्थी संकट बताया। फरवरी में शरणार्थियों की आमद एक दिन में बढ़कर 6000 हो गई।[111]

इस बीच, क्षेत्रीय कनेक्टिविटी में प्रगति के संकेत के रूप में, 752 किलोमीटर लंबी अदीस अबाबा-जिबूती रेलवे लाइन का उद्घाटन जनवरी 2017 में किया गया था। नई उद्घाटन की गई रेलवे की गति अपेक्षाकृत अधिक है क्योंकि इसपर यात्री गाड़ियों की गति160 किमी / घंटा की गति तक पहुंच सकती है और कार्गो के लिए यह 120 किमी / घंटा है। परियोजना को चीनी ऋणों द्वारा अधिक (70 प्रतिशत) वित्त पोषित किया गया था, और चीन रेलवे समूह द्वारा बनाया गया था।[112]

इथियोपिया और मिस्र के बीच पुनर्जागरण बांध का मुद्दा सुस्त पड़ गया लेकिन, दोनों देशों कीस्थितियों को देखते हुए, कोई तत्काल समाधान नहीं दिखाई दिया। हालांकि, बातचीत के प्रयास किए गए थे।

भारत-पूर्वी अफ्रीका द्विपक्षीय संबंध

पूर्वी अफ्रीका और भारत के बीच उच्च स्तरीय यात्राओं का आदान-प्रदान हुआ। भारत के राष्ट्रपति राम नाथकोविंद ने इथियोपिया और जिबूती का दौरा किया जबकि उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने युगांडा और रवांडा का दौरा किया। अफ्रीकी पक्ष से, केन्या और रवांडा के राष्ट्रपति ने भी नई दिल्ली का दौरा किया। उप प्रधानमंत्री और विदेश मामलों के मंत्री और कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य (डीआरसी) के क्षेत्रीय एकीकरण, और सोमालिया के विदेश मंत्री आधिकारिक यात्राओं पर भारत में थे। भारत के विदेश राज्य मंत्री, श्री एम. जे. अकबर ने भी कांगो गणराज्य का दौरा किया।

107"Kenya court upholds President's election win", The New York Times, 20 November 2017, https://www.nYtimes.com/2017/ll/20/world/africa/kenYa-supreme-court-ruling.html

108"S. Sudan's Kiir announces truce, national dialogue", Voice of America, 24 May 2017, https://www.voanews.com/a/south-sudan-kiir-announces-ceasefire-national-dialogue/3869423.html

109"South Sudan govt, rebel groups sign IGAD ceasefire deal in Ethiopia", Africa News, 21 December 2017, http://www.africanews.com/2017/12/21/south-sudan-govt-rebel-groups-sign-igad-ceasefire-deal-in-ethiopia/

110"Food crisis in East Africa 2017", Action Aid, 8 August 2017, https://www.actionaid.org.uk/about-us/what- we-do/emergencies-disasters-humanitarian-response/east-africa-crisis-facts-and-figures

111"South Sudan's refugee crisis now world's fastest growing, Uganda and region in critical need of help", UNHCR, 17 March 2017, http://www.unhcr.org/news/briefing/2017/3/58cba77f4/south-sudans-refugee-crisis-worlds-fastest-growing-uganda-region-critical.html

112New African railways ride on Chinese loans", Voice of America, 24 January 2017, https://www.voanews.com/a/new-african-railwavs-ride-chinese-loans/3690287.html

इन यात्राओं ने भारत-पूर्वी अफ्रीका के जुड़ाव का एक अभूतपूर्व स्तरदर्शाया। रक्षा, कृषि, समुद्री क्षेत्र, नीली अर्थव्यवस्था, आईसीटी और स्वास्थ्य इन यात्राओं में सहयोग के सबसे प्रमुख विषय थे। भारत और इथियोपिया ने भारतीय राष्ट्रपति की देश की यात्रा के दौरान दो समझौतों पर हस्ताक्षर किए।[113] पहला व्यापार समझौता था, जबकि दूसरा सूचना, संचार और मीडिया के क्षेत्र में सहयोग पर था। इथियोपिया के सबसे बड़े व्यापार, निवेश और विकास साझेदारों में से एक होने के नाते, भारत ने अफ्रीका को अपनेलाइन ऑफ क्रेडिट का सबसे बड़ा हिस्सा प्रदान करना जारी रखा।[114] अक्टूबर की शुरुआत में राष्ट्रपति कोविंद की जिबूती की यात्रा जिबूती के राष्ट्रपति के निमंत्रण पर महामहिमश्री इस्माइल उमर गुलेह; और इसे जिबूती द्वारा एक संतुलनकारी कार्य के रूप में देखा जा सकता है। यह दोनों राष्ट्रों के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना के बाद से भारत के राज्य प्रमुख या जिबूती गणराज्य की सरकार की पहली यात्रा थी।[115] दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय मुद्दों पर नियमित विचार-विमर्श करने और सहयोग के सहमत एजेंडे में विविधता लाने पर जोर दिया। जिबूती के अध्यक्ष ने लघु एवं मध्यम उद्योगों पर ध्यान देने के साथ जिबूती के आर्थिक विकास में भारत के लिए एक बड़ी भूमिका का आह्वान किया।[116]

जब केन्याई राष्ट्रपति ने नई दिल्ली का दौरा किया, तब कृषि यांत्रिकीकरण हेतु100 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए गए; और दोनों पक्षों ने अपने रक्षा सहयोग के त्वरित संचालन कोआगे बढ़ाया।[117]दोनों के बीच एक संयुक्त समूह को साइबर सुरक्षा, आतंकवाद का मुकाबला करने, ड्रग्स, नशीले पदार्थों, मानव तस्करी और मनी लॉन्ड्रिंग पर ध्यान केंद्रित करने हेतु गठित किया गया था जनवरी 2017 में रवांडा के राष्ट्रपति पॉल कागामे पहली बार भारत आए थे। यह यात्रा भारत के रूप में ऐतिहासिक थी और रवांडा ने अपने संबंधों को सामरिक भागीदारी स्तर तक बढ़ाने के प्रभाव के लिए घोषणा जारी की।[118] जहां भारत ने ऊर्जा उत्पादन के लिए किवू झील में अप्रयुक्त विशाल मीथेन भंडार की खोज में रुचि दिखाई, वहीं रवांडा ने भारत द्वारा चलाए जा रहे डिजिटल समावेश कार्यक्रमों की प्रतिकृति बनाने में रुचि दिखाई।[119]80 मिलियन अमेरिकी डॉलर की लाइन ऑफ क्रेडिट के साथ रवांडा के बिजली उत्पादन में भारत की सहायता को भी मंजूर किया गया। इसके अलावा, भारत ने रवांडा में नयाबारोंगोबिजली परियोजना, तकनीकी और व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र (टीवीईटी) और हूये-कीबेहोसड़क परियोजना के चरण II के लिए लाइन ऑफ क्रेडिट प्रदान करने के लिए अपनी तत्परता व्यक्त की। इसने भारत से चिकित्सा उपकरणों की सोर्सिंग के

लिए यूएस $2 मिलियन दवाओं और 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर के नकद अनुदान की भी घोषणा की।[120]

113"List of agreements signed during State Visit of President to Ethiopia (October 05, 2017)", Ministry of External Affairs, http://www.mea.gov.in/bilateral-documents.htm?dtl/29001/List of Agreements signed during State Visit of President to Ethiopia October 05 2017

114"State visit of President of India to Djibouti and Ethiopia (3-6 October, 2017)",Ministry of External Affairs.http://www.mea.gov.in/press-releases.htm?dtl/28987/State Visit of President of India to Djibouti and Ethiopia 36 October 2017

115"State Visit of President of India to Djibouti and Ethiopia (3-6 October, 2017)",Ministry of External Affairs.http://www.mea.gov.in/press-releases.htm?dtl/28987/State Visit of President of India to Djibouti and Ethiopia 36 October 2017

116"India-Djibouti Joint Statement during the State Visit of President to Djibouti (October 04, 2017)", Ministry of External Affairs. http://www.mea.gov.in/bilateral-documents.htm?dtl/28999/IndiaDiibouti Joint Statement during the State Visit of President to Djibouti O ctober 04 2017

117"Press Statement by Prime Minister during the State visit of President of Kenya to India", Ministry of External Affairs. 11 January 2017. http://www.mea.gov.in/Speeches-Statements.htm?dtl/27922/Press Statement by Prime Minister during the State visit of President of Keny a to India

118 "Declaration on Strategic Partnership between India and Rwanda", Ministry of External Affairs, 10 January 2017. http://www.mea.gov.in/bilateral-d.ocuments.htm?dtl/27915/DECLARATION ON STRATEGIC PARTNERSHIP BETWEEN INDIA AND RWANDA

युगांडा और भारत के बीच बढ़ते रक्षा सहयोग को भी विशेष रूप से युगांडा पीपुल्स डिफेंस फोर्स (यूपीडीएफ) के प्रशिक्षण के माध्यम से विभिन्न भारतीय सेना प्रशिक्षण संस्थानों के साथ-साथ युगांडा के वरिष्ठ कमांड और स्टाफ कॉलेज किमाका में अपनी सैन्य प्रशिक्षण टीम की तैनाती के बारे में बताया गया।[121] डीआरसीके वाइस प्रीमियर ने शांति, खनन, शिक्षा और चुनावी प्रक्रिया जैसे उनके हित के मुद्दों पर चर्चा की। भारत ने सोमाली विदेश मंत्री की यात्रा के दौरान कैदियों के विनिमय समझौते पर भी हस्ताक्षर किए। विश्व की वास्तविकताओं में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा सुधारों का मुद्दा दोनों पक्षों की यात्राओं के दौरान चर्चा की सुसंगत विशेषता थी। क्षेत्र में भारतीय प्रवासियों के साथ भारत की सक्रिय भागीदारी को भी ध्यान में रखा गया।

5.3 दक्षिणी अफ्रीका

अंगोला और जिम्बाब्वे में अफ्रीका के सबसे लंबे समय तक शासन करने वाले दो राष्ट्रपति वर्ष 2017 में सत्ता से बाहर हो गए। अंगोला में परिवर्तनकाल सुचारू था और निवर्तमान राष्ट्रपति श्री जोस एडुआर्डो डॉस सैंटोस द्वारा सचित्र किया गया था, जबकि जिम्बाब्वे में राष्ट्रपति रॉबर्ट मुगाबे सेसेना के सत्ता संभालने और उन्हें इस्तीफा देने तक अपने आवास में कैद में डालने की वजह से परिवर्तन का यह दौरा काफी बुरा था।

अंगोला के स्वास्थ्य अध्यक्ष सैंटोस के असफल होने की अटकलों के बीच, जो 1979 से पदपर थे, उन्होंने घोषणा की कि वह अगस्त 2017 में होने वाले चुनावों में एक और कार्यकाल के लिए नहीं लड़ेंगे। हालांकि, उन्होंने अपने त्याग के कारणों केबारे में नहीं बताया।देश में सत्तारूढ़ पार्टी गृह युद्ध के अंत के बाद सेविशेषज्ञों ने एमपीएलए के भीतर कुछ आंतरिक दबावों का अनुमान लगाया। यह भी कहा जाता है कि श्री सैंटोस ने अपने बेटे को सत्ता और राजनीति के अगले केंद्र के रूप में स्थापित करने का प्रयास किया, लेकिन पार्टी के भीतर विरोध ने उन्हें अपने उत्तराधिकारी के रूप में तत्कालीन रक्षा मंत्री जोआओ लौरेंको को आगे बढ़ाने और सामने लाने के लिए मजबूर होना पड़ा।[122]

119Joint Communique on the visit of the Vice President of India to the Republic of Rwanda, Kigali, Ministry of External Affairs, 21 February 2017,http://www.mea.gov.in/Uploads/PublicationDocs/28083 JointStatement.pdf

120 "India-Rwanda Joint Statement during the visit of President of Rwanda to India (January 9-11, 2017)', Ministry of External Affairs, http://www.mea.gov.in/bilateral-documents.htm?dtl/27914/IndiaRwanda Joint Statement during the visit of President of Rwanda to India January 911 2017

121Joint Statement on the Occasion of the visit to Uganda of the Vice President of India, Mr Mohammad Hamid Ansari From 21 - 23 February 2017, Ministry of External Affairs,http://www.mea.gov.in/Uploads/PublicationDocs/28095 Uganda Joint Statement new.pdf

122 "Angola prepares for life after Dos Santos", Chatham House, 20 February 2017, https://www.chathamhouse.org/expert/comment/angola-prepares-life-after-dos-santos

दूसरी ओर, जिम्बाब्वे के रॉबर्ट मुगाबे को सैन्य अधिग्रहण का सामना करना पड़ा। संसद में महाभियोग की प्रक्रिया शुरू करने और उन्हें उनके आवास तक सीमित रहने के बीच राजनीतिक और लोकप्रिय दबाव ने श्री मुगाबे को 1980 के बाद से 37 वर्षों तक देश पर शासन करने के बाद इस्तीफा देने के लिए मजबूर होना पड़ा। अजीब तरह से, सैन्य भागीदारी मुगाबे को मजबूर करने और श्री इमर्सन म्नांगगवा को सत्ता सौंपने के लिए हुई, जिन्हें उनके द्वारा उपराष्ट्रपति के पद से हटा दिया गया था, जो कि परिवर्तन की घटनाओं के नाटकीय समूह से ठीक पहले हुआ। श्री मुगाबे के जबरन बाहर निकलने के बाद हुए सौदे की वजह से उन्हें जिम्बाब्वे की स्वतंत्रता के लिए उनकी भूमिका को स्वीकार करते हुए गरिमा के साथ रहने दिया गया। श्री इमर्सन म्नांगगवा ने देश के नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली।[123] दक्षिण अफ्रीका में राष्ट्रपति जैकब जुमा को भ्रष्टाचार और धन इकट्ठा करना के लिए कथित रूप से सत्ता के दुरुपयोग के लिए कड़ी आलोचना का सामना करना पड़ा। उनकी पार्टी (अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस) के साथ-साथ विपक्षी दल भी ज़ुमा के इस्तीफे के लिए दबाव बना रहे थे। श्री जुमा अपने खिलाफ आरोपों की एक श्रृंखला के साथ राष्ट्रपति पद का कार्यभार संभाले हुए थे। हालांकि, अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस (एएनसी) के अध्यक्ष के रूप में सिरिल रामफोसा के चुनाव और जुमा के खिलाफ कड़ा रुख अपनाने वाली अदालतों के साथ[124], जुमा की राष्ट्रपति पद से विदाई बस कुछ ही समय में होते हुए नजर आई। वास्तव में, एएनसीके भीतर के नेताओं ने संकेत दिया कि ज़ुमा के हटाने के नियमों और शर्तों पर बातचीत की जा रही थी।[125]

इस क्षेत्र में कुछ अन्य महत्वपूर्ण विकास के लिए, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो (डीआरीसी) हिंसा[126] तथा शरणार्थी संकट[127] के एक अन्य दौर में आ गया।हिंसा में देश के 15 तंजानियाई शांति सैनिकों की भी मौत हुई।[128]मेडागास्कर को एक प्लेग प्रकोप का सामना करना पड़ा; दक्षिणी अफ्रीका के सबसे स्थिर देशों में से एक, ज़ाम्बिया, विपक्षी प्रेरित आगजनी और तोड़फोड़ के कृत्यों से निपटने के लिए 'आपातकाल की स्थिति'[129] का सामना करने लगा; और एयर नामीबिया[130] को अमेरिका में उड़ान भरने का अधिकार दिया गया था, जोएक ऐसा विशेषाधिकार है जिसे अब तक केवल दक्षिण अफ्रीकी एयरवेज, इथियोपियाई एयरलाइंस, मिस्र एयर, मोरक्को रॉयल एयर मैरो और केप वर्डे की टीएसीवी एयरलाइन को दिया गया था।[131]

123"Zimbabwe swears in a new president, in the first transfer of power since independence", NPR, 24 November 2017, https://www.npr.org/sections/thetwo-wav/2017/11/24/566341627/zimbabwe-swears-in-a-new-president- in-the-first-transfer-of-power-since-independ

124"South African court raises pressure for Zuma to Go", The New York Times, 29 December 2017, https://www.nvtimes.com/2017/12/29/world/africa/south-africa-court-zuma-impeach.html?mtrref=www.google.co.in&gwh=62DCABE3EBD6723ABBE47269E80D5FF3&gwt=pav

125"Cyril Ramaphosa chosen to lead South Africa's ruling ANC party", The Guardian, 18 December 2017, https://www.theguardian.com/world/2017/dec/18/cvril-ramaphosa-chosen-to-lead-south-africas-ruling-anc-partv

126"Fighting kills more than 3,000 in Congo's Kasai region: Catholic Church", Reuters, 20 June 2017, https://www.reuters.com/article/us-congo-violence/fighting-kills-more-than-3000-in-congos-kasai-region-catholic-church-idUSKBN19B0YX

127"DR Congo forces kill at least 36 Burundi refugees", Al Jazeera, 17 September 2017, https://www.aliazeera.com/news/2017/09/dr-congo-forces-kill-18-burundi-refugees-170916094527832.html

128"Magufuli 'shocked' by killings of Tanzanian soldiers in DRC", Daily Nation, 9 December 2017, https://www.nation.co.ke/news/africa/Magufuli-mourns-TZ-soldiers-DRC/1066-4221572-ukqg0g/index.html

129"Zambia edges towards dictatorship", Mail & Guardian, 5 July 2017, https://mg.co.za/article/2017-07-05-zambia

130"Zambia emergency powers decree to end at midnight on Wednesday", Reuters, 11 October 2017, https://www.reuters.com/article/us-zambia-politics/zambia-emergencv-powers-decree-to-end-at-midnight-on- wednesdav-idUSKBN1 CG24X

131 "Air Namibia granted right to fly into US", New Era, 22 May 2017,https://www.newera.com.na/2017/05/22/air-namibia-granted-right-to-flv-into-us/

आर्थिक मोर्चे पर, तुर्की को तंजानिया रेलवे निर्माण में संभावित निवेशक के रूप में देखा गया। विकासके क्षेत्र में बुनियादी ढांचे के निर्माण में चीन के साथ तंजानिया के भविष्य के सहयोग के बारे में कुछ संदेह सामने आए।[132] क्षेत्रीय एकीकरण तथा विकास के एक अन्य प्रयास में, एएफडीबीने 300 मिलियन डॉलर के साथ मोज़ाम्बिक के नकला रेल परियोजना का समर्थन करने का निर्णय लिया। इस परियोजना में 912 किमी रेलवेखंड बंदरगाह है जो कि मोज़ाम्बिक के पश्चिमी क्षेत्र और लैंडलाक

मलावी को जोड़ने और खोलने हेतु बंदरगाह प्रदान करता है।[133] इस क्षेत्र के विकास में दक्षिणी अफ्रीका में राजनीतिक-आर्थिक नीतिगत उत्पीड़न के संदर्भ में नतीजे होंगे। लंबे तानाशाही शासन के हिंसक परिवर्तनों के अफ्रीका के इतिहास से विकास की दिशादिखाते हुए, हिंसा के बिना, अंगोला और जिम्बाब्वे में बदलाव वास्तव में सराहनीय थे। नेताओं द्वारा इस क्षेत्र में राजनीतिक और आर्थिक बदलावों को संभालना क्षेत्र में प्रगति, राजनीतिक स्थिरता और विकास की इच्छा को दर्शाता है।

भारत-दक्षिणी अफ्रीका द्विपक्षीय संबंध

उच्च स्तरीय यात्राओं के संदर्भ में, मॉरीशस के प्रधानमंत्री ने नियुक्ति के बाद किसी भी देश की अपनी पहली आधिकारिक यात्रा पर भारत का दौरा किया। दोनों पक्ष अपने तटों पर और ईईजेड में सामूहिक समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु अपनी जिम्मेदारी पर सहमत हुए। उन्होंने इस क्षेत्र में आपसी सहयोग और क्षमता निर्माण को मजबूत करने के लिए द्विपक्षीय समुद्री सुरक्षा समझौते का भी निष्कर्ष निकाला। वे हाइड्रोग्राफी पर व्यापक सहयोग, और प्रोजेक्ट ट्राइडेंट के माध्यम से कोस्ट गार्ड को मजबूत करने के लिए सहमत हुए। भारत ने मॉरीशस को 500 मिलियन डॉलर का लाइन ऑफ क्रेडिट (एलओसी) भी प्रदान किया।

उप प्रधानमंत्री और विदेश मामलों और डीआरसी के क्षेत्रीय एकीकरण के मंत्री महामहिम लियोनार्ड शी ओकीतुंडु लुंडुला ने भी नवंबर 2017 में नई दिल्ली का दौरा किया। उन्होंने डीआरसी के अध्यक्ष का एक पत्र भारतीय प्रधानमंत्री को प्रदान कर उनके देश की यात्रा करने हेतु आमंत्रित किया। श्री लुंडुला ने खनन, शिक्षा और चुनावी प्रक्रिया में सहयोग बढ़ाने की इच्छा व्यक्त की। दोनों पक्ष 2018 की शुरुआत में द्विपक्षीय संयुक्त आयोग की बैठक आयोजित करने पर भी सहमत हुए।

कुछ अन्य भारत-दक्षिणी अफ्रीका के घटनाक्रम में, भारत लेसोथो संयुक्त द्विपक्षीय सहयोग आयोग का तीसरा दौर दिसंबर 2017 में आयोजित किया गया था; और भारत ने सेशेल्स को चिकित्सा उपकरण और दवाओं की आपूर्ति के लिए 8.76 मिलियन डॉलर के हिस्से के रूप में सेशेल्स को तीन करोड़ रुपये की दवाएं भेंट कीं। ओवीएल (ओएनजीसी विदेश लिमिटेड), भारतीयओएनजीसीकी विदेशी निवेश शाखा, ने नामीबिया ब्लॉक[134] में हिस्सेदारी खरीदने का फैसला किया;और भारतीय कंपनी लार्सन एंड टुब्रो ने मॉरीशस[135] में 3,375 करोड़ रुपये की मेट्रो रेल परियोजना का कार्य हासिल की। भारत ने मॉरीशस में तरल गैस परियोजना पर भी चर्चा की।[136]

132"Tanzania courts Turkey for its rail megaproject, casting doubt on China's role", Global Construction Review, 24 January 2017, http://www.globalconstructionreview.com/news/tanzania-courts-turkey-its-rail-megaproj ect-castin/

133The AfDB signs US$300 mn loan agreement for Nacala Corridor project", African Review, 29 December 2017, http://www.africanreview.com/transport-a-logistics/rail/the-afdb-signs-us-300mm-loan-agreement-for-nacala-corridor-project

134“ONGC Videsh to acquire 15% stake in Namibia block”, Business Line, 21 November 2017, https://www.thehindubusinessline.com/companies/ongc-videsh-to-acquire-15-stake-in-namibia-block/article9968307.ece

135“L&T bags Rs 3,375 crore metro rail project in Mauritius”, The Economic Times, 2 August 2017, https://economictimes.indiatimes.com/industry/indl-goods/svs/engineering/lt-bags-rs-3375-crore-metro-rail-project-in-mauritius/articleshow/59884799,cms

136“India to expand energy outreach with Mauritius gas project ”, The Times of India, 26 May 2017,https://timesofindia.indiatimes.com/business/india-business/india-to-expand-energy-outreach-with-mauritius-gas-project/articleshow/58861108,cms

भारतीय महासागर द्वीप समूह

5. भारतीय महासागर द्वीप समूह

जकार्ता में 07 मार्च, 2017 को राज्यों के प्रमुखों के अपने पहले शिखर सम्मेलन और जकार्ता कॉनकॉर्ड और आईओआरएकार्य योजना को जारी करने के साथ हिंद महासागर तटीय सहयोग संघ(आईओआपए) मोर्चे पर बड़ा विकास हुआ। जकार्ता शिखर सम्मेलन में 21 आईओआरए सदस्य देशों के नेताओं तथा इसके सात संवाद भागीदारों के साथ-साथ अन्य विशेष आमंत्रित लोगों ने भाग लिया। भारत की ओर सेभारत के तत्कालीन उपराष्ट्रपति श्री हामिद अंसारी ने शिखर सम्मेलन में भाग लिया।श्री जोको विडोडो, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति, श्री जैकब जुमा, दक्षिण अफ्रीका के तत्कालीन राष्ट्रपति, श्री मैथिपाला सिरिसेना, श्रीलंका के राष्ट्रपति, श्री अब्दुर्रबू मंसूर हादी, यमन के राष्ट्रपति, और श्री मोहम्मद जावेद जरीफ, विदेश मंत्री ईरान के अन्य प्रमुख प्रतिभागियों में से थे।

शिखर सम्मेलन के दौरान, जकार्ता ने "शांतिपूर्ण, स्थिर और समृद्ध हिंद महासागर हेतु क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देने" के समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। इसके अलावा, अगले पांच वर्षों (2017-2021) के लिए आईओआरए कार्य योजना और मंत्रिमंडल (सीओएम) की बैठक और वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक (एसओएम) को क्रमशः 06 मार्च और 05 मार्च 2017 के दौरान हिंसक अतिवाद को रोकने और मुकाबला करने पर घोषणा को अपनाया गया।

इंडोनेशिया ने 18 अक्टूबर 2017को 2017-19 की अवधि के लिए 17वीं आईओआरएमंत्रिपरिषद की बैठक के दौरान हिंद महासागर रिम एसोसिएशन (आईओआरए) की अध्यक्षता दक्षिण अफ्रीका को

सौंपी। संयुक्त अरब अमीरात इस अवधि के दौरान उपाध्यक्ष होगा। 17वीं मंत्रिपरिषद ने डरबन विज्ञप्ति की पुष्टि की।

दूसरे ब्लू इकोनॉमी कॉन्फ्रेंस (08-10 मई 2017) के दौरान आईओआरएके सदस्य राज्यों ने ब्लू इकोनॉमी की पहल जैसे कि मत्स्य पालन और जलीय कृषि, अंतर बंदरगाह सहयोग, समुद्री पर्यटन आदि से सहयोग की आवश्यकता पर जोर दिया। भारत की ओर सेविदेश राज्य मंत्री एम. जे.अकबर ने सम्मेलन में भाग लिया।

"समुद्री स्थानिक योजना - हिंद महासागर के सतत उपयोग की ओर" पर आईओआरए हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन 22- 23 नवंबर 2017 को मॉरीशस में किया गया था। समुद्री जलकुंभी और मछली स्वास्थ्य प्रबंधन 2017 पर कार्यशाला 21-28 नवंबर 2017 को इंडोनेशिया में आयोजित की गई। आईओआरए ने सोमालिया और यमन हेतु विशेष क्षमता निर्माण कार्यक्रम का आयोजन किया।[137] कार्यक्रम 13-14 अगस्त 2017 को अबू धाबी में संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के विदेश मंत्रालय और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग मंत्रालय (एमओएफएआईसी) द्वारा आयोजित किया गया था।[138]

चीन ने 11 जुलाई 2017 को अफ्रीका के हॉर्न के जिबूती में अपना पहला विदेशी सैन्य अड्डा स्थापित करने हेतु कर्मियों को ले जाने वाले जहाज भेजे।[139] चीनी मीडिया ने जिबूती में अपने पहले विदेशी सैन्य अड्डे को सैन्य बेस नहीं बल्कि एक रसद सुविधा बनाया।[140]

137IORA Somalia and Yemen Development Programme (SYDP) on Banking & Artisanal Fisheries Abu Dhabi, United Arab Emirates, 13-14 August 2017, IORA Press Release, http://www.iora.net/sydp-uae-13-14-august-2017.aspx(accessed on 14 August 2017).

138Ibid.

139China to open first overseas military base in Djibouti, 12 July 2017,http://www.aliazeera.com/news/2017/07/china-open-overseas-military-base-diibouti-170712135241977.html

140Djibouti a logistic centre, not a military base like US: Chinese media, August 23, 2016, http://www.hindustantimes.com/world-news/diibouti-a-logistic-centre-not-a-military-base-like-us-chinese-media/storv-aF9OdvodONeOCZZa5lp1nO.html, accessed on 17 July 2017

नई दिल्ली में समुद्री सुरक्षा एवंबचाव विशेषज्ञों की बैठक आईओआरए (हिंद महासागर तटीय सहयोग संघ) के दौरान मुख्य मुद्दों पर ध्यान केन्द्रित करते हुए 7-8 नवंबर कोविदेश सचिव ने समुद्री सुरक्षा सहयोग, नेविगेशन की स्वतंत्रता, और अखंडता का सम्मान करनेतथा हिंद महासागर क्षेत्र के देशों से समुद्री सुरक्षा के हितों को सुरक्षित करने कीआवश्यकता पर प्रकाश डाला और क्षेत्रीय सहयोग बढ़ाने का आग्रह किया।[141]विदेश राज्य मंत्री श्री एम.जे. अकबर ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के विशेष दूत के रूप में 21-22 फरवरी, 2017 को मालदीव का दौरा किया।[142]यात्रा के दौरान, श्री अकबर ने मालदीव गणराज्य के तत्कालीन राष्ट्रपति श्री अब्दुल्ला यामीन अब्दुल गयूम से मुलाकात की और विदेश मंत्री

डॉ. मोहम्मद आसिम के साथ बैठक की।[143]यात्रा के दौरान उन्होंने एक स्थिर, लोकतांत्रिक, शांतिपूर्ण और समृद्ध मालदीव के लिए भारत के समर्थन को दोहराया।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत-हिंद महासागर में सेशेल्स के बीच मजबूत और जीवंत संबंधों का आह्वान किया। 10 अगस्त, 2017 को नई दिल्ली में सेशेल्स संसदीय प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक के दौरान, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत और सेशेल्स के बीच "मजबूत और जीवंत संबंधों" का स्वागत किया।[144] सेशेल्स नेशनल असेंबली के स्पीकर पैट्रिक पिल्ले के नेतृत्व में सेशेल्स संसदीय प्रतिनिधिमंडल लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन के निमंत्रण पर भारत की आधिकारिक यात्रा की थी।[145] तत्कालीन विदेश सचिव डॉ. एस. जयशंकर ने अक्टूबर 2017 के दूसरे सप्ताह के दौरान सेशेल्स का दौरा किया। इस यात्रा का उद्देश्य द्विपक्षीय विकास सहयोग और समुद्री सहयोग को मजबूत करना था।[146] यात्रा के दौरान, विदेश सचिव ने सेशेल्स के राष्ट्रपति, उप-राष्ट्रपति, विपक्ष के नेता और मंत्रिमंडल के सदस्यों के साथ मुलाकात की।[147]

मॉरीशस के प्रधानमंत्री प्रवीण जुगनाथ ने 26-27 मई 2017 में भारत का दौरा किया। उन्होंने समुद्री सुरक्षा सहयोग पर द्विपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए, जबकि भारत ने मॉरीशस के लिए500 मिलियन डॉलरके लाइन ऑफ क्रेडिट की घोषणा की।[148]इंटरनेशनल सीबड अथॉरिटी ने 18 अगस्त, 2017 को किंग्स्टन, जमैका में आयोजित इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी (आईएसए) के 23वें सत्र में सेंट्रल इंडियन ओशन सीबेड बेसिन से पॉलीमेटैलिक नोड्यूल का पता लगाने हेतु भारत के विशेष अधिकारों में विस्तार किया।[149] भारत सरकार, भू-विज्ञान मंत्रालय को भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र (आई.एन.सी.ओ.आई.एस.) ने पोर्ट मोरेस्बी, पापुआ न्यू गिनी में एशिया और अफ्रीका(आर.आई.एम.ई.एस.) के लिए क्षेत्रीय एकीकृत बहु-खतरा प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली की तीसरी मंत्रिस्तरीय बैठक में कोमोरोस, मेडागास्कर और मोज़ाम्बिक के लिए महासागर पूर्वानुमान प्रणाली का उद्घाटन किया।

141 India calls on Indian Ocean nations to secure interests of maritime security, regional cooperation, November 8, 2017, http://indiatoday.intoday.in/storv/indian-ocean-nations-maritime-securitv-china-iapan-unclos-indo- pacific-region/1/1084931.html (accessed on 13 November, 2017)

142Visit of Minister of State for External Affairs, Shri M J Akbar to the Republic of Maldives, http://www.mea. gov.in/press-releases.htm?dtl/28087/visit+of+minister+of+state+for+external+affairs+shri+m+i+akbar+to+the+republic+of+ maldives (Accessed on 11February 2018)

143Ibid.

144Modi hails India-Seychelles partnership in Indian Ocean, August 10, 2017,http://www.india.com/news/agencies/modi-hails-india-seychelles-partnership-in-indian-ocean-2392233/ (accessed on August 14, 2017).

145Ibid.

146S Jaishankar in Seychelles: As China shadow looms, India must quickly iron out disputes over Assumption Island, http://www.firstpost.com/india/s-iaishankar-in-seychelles-as-china-shadow-looms-india-must-quickly-iron-out-disputes-over-assumption-island-4134995.html, (accessed on 16 October 2017)

147FS Seychelles visit focus was on developmental, maritime cooperation: MEA, 12 October,2017 https://news.webindia123.com/news/Articles/India/20171012/3201224.html(accessed on 16 October 2017)

148India reaches out to Mauritius with $500 million pledge, May 28, 2017,http://economictimes.indiatimes.comhttp://economictimes.indiatimes.com/news/politics-and-nation/india-reaches-out-to-mauritius-with-500-million-pledge/printarticle/58880622.cms?utm source=contentofinterest&utm medium=text&utm campaign=cppst,(accessed on 28 May 2017).

मालदीव में कुछ राजनीतिक उथल-पुथल को छोड़कर यह क्षेत्र आमतौर पर शांतिपूर्ण रहा। हिंद महासागर के साथ सहयोग बढ़ाना भारत की प्राथमिकता है। सोमालिया के जल से कुछ समुद्री डकैती हुईं, जो 2010 के बाद कम हो गई थीं।

कोलंबो में 01 सितंबर, 2017 को द्वितीय हिंद महासागर सम्मेलन 2017 के गणमान्य सत्र को संबोधित करते हुए, श्रीलंका के राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरीसेना ने शांति क्षेत्र के रूप में हिंद महासागर(आई.ओ.जेड.पी.) के विचार की वकालत की।[150]

149Ibid.

150President emphasizes importance of making Indian Ocean a zone of peace,httn://www.defence.lk/new.asp?fname=President emphasizes importance of making Indian Ocean a zone o f peace 20170904 01, (accessed on September 04, 2017).

लैटिन अमेरिका / कैरेबियन

6. लैटिन अमेरिका/कैरेबियन

राजनीतिक घटनाक्रम मेंब्राजील के तत्कालीन राष्ट्रपति लुइज़ इनकियो लूला डा सिल्वा को भ्रष्टाचार के आरोपों में 9 साल 6 महीने जेल की सजा सुनाई गई थी। 12 जुलाई, 2017 को जज सर्जियो मोरो ने लूला को इंजीनियरिंग फर्म ओएएससे 3.7 मिलियन रियाल (1.2 मिलियन डॉलर) की रिश्वत लेने का दोषी पाया, अभियोजन पक्ष ने कहा कि कंपनी ने राज्य की तेल कंपनी पेट्रोएलो ब्रासीलेरो के साथ अनुबंध जीतने में उसकी मदद के बदले लूला के लिए एक समुद्र तट अपार्टमेंट का नवीनीकरण किया।लूला के भ्रष्टाचार घोटाले के बारे में निर्णय केवल पांच में से पहला था।

वेनेजुएला कोअब तक के सबसे खराब राजनीतिक संघर्ष का सामना करना पड़ा, जो आर्थिक और सामाजिक संकट से और अधिक जटिल हो गया था। 2017 में मुद्रास्फीति 127.8 प्रतिशत थी और देश में मानवीय संकट पैदा करते हुए भोजन तथा आवश्यक दवाओं की भारी कमी हुई। राष्ट्रपति मादुरो का विरोध करने वाली पार्टियों ने पूरे देश में बड़ी रैलियों का आयोजन किया। राष्ट्रपति मादुरो को निंदा और दबाव का सामना करना पड़ा, जिसमें लैटिन अमेरिका में क्षेत्रीय मुक्त व्यापार ब्लॉक, मर्कोसुर से वेनेजुएला का निलंबन तथा अमेरिकी प्रतिबंधों के कई दौर शामिल हैं। विदेश मंत्री डेल्सी

रोड्रिग्ज ने समूह के वाशिंगटन मुख्यालय में संक्षिप्त लेकिन विवादास्पद बैठक के बाद अमेरिकी राज्यों के संगठन (ओएएस) से हटने के निर्णय की घोषणा की, जिसमें इसकी स्थायी परिषद ने वेनेजुएला के संकट का मूल्यांकन करने हेतु विशेष सत्र आयोजित करने के पक्ष में मतदान किया।

आर्थिक परिप्रेक्ष्य में, अर्जेंटीना एशियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक (एआईआईबी) का छठा लैटिन अमेरिकी सदस्य बनने के लिए बोलिविया, ब्राजील, चिली, पेरू और वेनेजुएला के साथ शामिल हो गया। ऋण संकट के निपटारे के बाद और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सहायता तथा दबाव में, राष्ट्रपति मौरिसियो मैक्री के प्रशासन ने एक से डेढ़ साल पुरानी बहुपक्षीय वित्तीय संस्था से फंडिंग हेतु नए माध्यमों की तलाश करने के लिए यह कदम उठाया। पूरे लैटिन अमेरिका में एआईआईबी केविकास ने एशिया के साथ क्षेत्र के घनिष्ठ संबंधों को दर्शाया और साथ ही साथ द्विपक्षीय बॉन्ड की तलाश भी की।

"ऑपरेशन विक फ्लेश" नामक दो साल की जांच के बाद, ग्लोबल फूडप्रोसेसिंग दिग्गज, जेबीएस और बीआरएफके साथ दर्जनों छोटी कंपनियों ने मीटपैकर्स ने इंस्पेक्टरों और राजनेताओं द्वारा मिलावटी या प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों, पानी में इंजेक्ट किए गए मांस और गलत तरीके से सैनिटरी परमिट तथा उनकी उपेक्षा करने के सबूत पाएं। ब्राजील के रोटेन मांस घोटाले में गिरावट 20 मार्च 2017 को तेज हो गई जब बड़े बाजारअमेरिका, चीन नेआयात निलंबित कर दिया और यूरोपीय संघ तथा दक्षिण कोरिया ने आंशिक प्रतिबंध लगाने की मांग की। चिली ने "अस्थायी" प्रतिबंध भी लगाया था। बारबाडोस सेंट विंसेंट और ग्रेनेडाइंस, अल्जीरिया, जमैका, त्रिनिदाद और टोबैगो, पनामा, कतर, मैक्सिको और बहामा ने भी ब्राजील से सभी मांस और मांस उत्पादों के तत्काल आयात प्रतिबंध को लागू किया था।

वेनेजुएला ने 15 सितंबर, 2017 को पहली बार अमेरिकी डॉलर में छंटनी के अपने वादे को प्रदर्शित करते हुए चीनी युआन में अपने तेल की कीमतें प्रकाशित कीं। 8 सितंबर, 2017 को राष्ट्रपति मादुरो ने आगामी बदलाव की घोषणा की थी।

भारत -लटिन अमेरिका संबंध

ज़ियामी, चीनमें 9वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के उद्घाटन में भाग लेने के दौरानब्राज़ील के राष्ट्रपति मिशेल टेमर नेपांच देशों के बीच व्यापार के संबंध में आर्थिक बाधाओं को कम करने तथा नौकरशाही में कमी लाने का आग्रह किया और कहा कि दक्षिण अमेरिकी देशब्रिक्स के भागीदारदेशों के विदेशी निवेश का स्वागत करते हैं।

वेनेजुएला के शासन के खिलाफ ट्रम्प प्रशासन के प्रतिबंधों के बाद, जो अमेरिकी बाजारों में नए वेनेजुएला के जुड़ाव में बाधा बना, चीन ने शून्य भरने का काम किया और आवश्यक वित्तीय लाइफलाइन प्रदान की। वेनेजुएला के अधिकारियों ने दोनों देशों के बीच निवेश निधि पर बातचीत करने के प्रयास में अगस्त 2017 के मध्य में चीन की यात्रा की। उस निधि के पीछे की रणनीति 2017 और 2018 में परिपक्व होने वाले बॉन्ड पर छूट पर,वेनेजुएला और पीडीवीएसए पैसे को बचाने की थी।

रूस ने राष्ट्रपति मादुरो को अधिक अनुकूल शर्तों के साथ 3 बिलियन अमरीकी डॉलर के ऋण का पुनर्गठन करने की अनुमति दी, जबकि चीन ने वेनेजुएला के साथ भविष्य के तेल वितरण हेतु ऋण का आदान-प्रदान करने के लिए उच्च जोखिम वाला जुआ जारी रखा। दिसंबर 2017 को, वेनेजुएला ने ब्राजील और कनाडा के राजदूतों को व्यक्तिगत नॉन-ग्रेता घोषित किया।

यूरोपीय संघ के साथ समझौते को खत्म करने के करीब होने के अलावा, दक्षिण अमेरिकी व्यापार समझौता ब्लाक (मर्कोसुर) ने यूनाइटेड किंगडम के साथ संभावित व्यापार समझौते पर चर्चा की। ब्रेक्सिट के बाद समझौता प्रभावी हो सकता है। ब्रेक्सिट के कारण, ब्रिटेन को मर्कसूर और यूरोपीय संघ के बीच व्यापार समझौते से बाहर रखा जाएगा, और दक्षिण अमेरिकी देशों के साथ अलग व्यापार समझौते पर बातचीत करनी होगी। मर्कोसुर और यूरोपीय संघ (ईयू) के बीच मुक्त व्यापार समझौते की बातचीत 1999 से चल रही है। 2017 के अंत में, दोनों पक्षों मे चर्चाओं को आगे बढ़ाया, लेकिन समझौते पर हस्ताक्षर 2018 तक स्थगित कर दिए गए।

उत्तरी अमेरिका

7. उत्तरी अमेरिका

8.1 कनाडा

संयुक्त राज्य के साथ दक्षिण और रूस के निकटतम उत्तरी पड़ोसी के रूप में, कनाडा को वर्ष 2017 में कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ा। अमेरिका ने नाफ्टा के पुनः मध्यस्थता का आह्वान किया, जिससे यह स्पष्ट हो गया कि जरूरत पड़ने पर वह समझौते से हटने को तैयार है, जिससे कनाडा को बाकी दुनिया के साथ अपनी आर्थिक भागीदारी को मजबूत करने हेतु मजबूर होना पड़ा। प्रधानमंत्री, जस्टिन ट्रूडो ने 16 से 17 फरवरी, 2017 तक फ्रांस और जर्मनी की सफल यात्रा की। यात्रा के दौरान, प्रधानमंत्री ने फ्रांस के स्ट्रासबर्ग में यूरोपीय संसद को संबोधित किया, और बर्लिन तथा हैम्बर्ग, जर्मनी का दौरा किया। यह प्रगतिशील व्यापार और निवेश पर एक अग्रणी के रूप में कनाडा की भूमिका को बढ़ावा देने का अवसर था, इस पर प्रकाश डाला गया कि कैसे कनाडा- यूरोपीय संघ व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता (सीईटीए) की अच्छी सेवा देने वाले, बोली लगाने वाले साझा समृद्धि पैदा करेगा, और मध्यम वर्ग के विकास में मदद करेगा।प्रधानमंत्री ट्रूडो ने चीन (03-07 दिसंबर, 2017) का दौरा किया, जिसका उद्देश्य "प्रगतिशील व्यापार एजेंडा और पर्यटन पहल को बढ़ावा देना है जो अच्छे,

मध्यम वर्ग की नौकरियां पैदा करेगा" और जलवायु परिवर्तन से लड़ने में अधिक से अधिक सहयोग का आह्वान करेगा।

पड़ोस में रूस की सैन्य शक्तियों के बढ़ने के साथ, एन.ओ.आर.ए.डी. के हिस्से के रूप में अपनी बैलिस्टिक मिसाइल रणनीति की समीक्षा करने हेतु कनाडा के भीतर मांग उठी। प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने उत्तरी अमेरिका पर हमला करने हेतु उत्तर कोरिया की नई क्षमताओं के विरोध में कनाडा के लंबे समय के विरोध को उलटते हुए, अमेरिकी बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा कार्यक्रम में शामिल होने का दरवाजा खोल दिया। प्रधानमंत्री ट्रूडो ने कहा कि उत्तर कोरिया का "लापरवाह व्यवहार" वैश्विक शांति के लिए खतरा है।

कनाडा ने अपनी नाटो नीति पर पुनः विचार किया। जबकि कनाडा ने नाटो में अपने योगदान का बचाव किया, अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा समान बोझ साझाकरण के लिए लगातार आलोचना ने भी कनाडा के नाटो नीति में काम किया। प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो और रक्षा मंत्री श्री हरजीत एस. सज्जन ने अपने अमेरिकी समकक्षों के साथ आव्रजन और आर्थिक सहयोग के मुद्दों और नाटो एवं सैन्य सहयोग के अन्य क्षेत्रों को मजबूत करने पर चर्चा की। पूर्वी यूरोप में संभावित रूसी महत्वाकांक्षाओं पर लगाम लगाने हेतु पहली कनाडाई सेना जून 2017 में लातविया पहुंची थी। चार देशों - अल्बानिया, इटली, पोलैंड और स्लोवेनिया ने कनाडा के नेतृत्व वाली टुकड़ी में सैनिकों और उपकरणों का योगदान देने का वादा किया। लिबरल सरकार ने लगभग दो वर्षों तक इराक में कनाडा के सैन्य मिशन को बढ़ावा दिया। मिशन को 31 मार्च, 2019 तक बढ़ाया गया था। ओटावा ने अगले दशक में 30 बिलियन डॉलर से अधिक सैन्य खर्च को बढ़ावा देने की योजना का खुलासा किया है। रक्षा खर्च के खाके में कनाडा की संप्रभुता की विशाल आर्कटिक पहुंच में रक्षा के लिए अधिक मुखर भूमिका शामिल थी। यह योजना लिबरल पार्टी के लिए एक अप्रत्याशित धुरी थी, जिसने पिछले चुनाव में सामाजिक खर्च और बुनियादी ढांचे के वादों पर काफी प्रचार किया था।

कनाडा ने चार साल के लिए मध्य पूर्व के जल में अंतरराष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा मिशन हेतु अपनी प्रतिबद्धता को बढ़ाया। संघीय सरकार ने विस्तार का समर्थन करने हेतु 131.4 मिलियन डॉलर तक की मंजूरी दी, जिसके तहत 375 सैन्य कर्मियों की तैनाती की जाएगी। कनाडा और संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) ने रक्षा सहयोग व्यवस्था पर हस्ताक्षर किए।

आर्थिक मोर्चे परकनाडा उन 11 देशों में शामिल था, जिन्होंने अमेरिका के पीछे हटने के बाद भी टीपीपी पर बातचीत जारी रखी थी। प्रधानमंत्री ट्रूडो ने ट्रांस-पैसिफिक पार्टनरशिप पर कनाडा की कार्रवाई का बचाव हुए कहाथा कि देश केवल संस्कृति और मोटर वाहन क्षेत्र की चिंताओं के कारण अंतिम रूप देने हेतु तैयार नहीं था।

घरेलू मोर्चे पर नई डेमोक्रेटिक पार्टी से श्री जगमीत सिंह चुनाव जीता, जिससे वो कनाडा में एक प्रमुख राजनीतिक दल के पहले गैर-श्वेत नेता बन गए।

भारत-कनाडा द्विपक्षीय संबंध

द्विपक्षीय मोर्चे परभारतीय मूल के कनाडा के रक्षामंत्री, हरजीत सिंह सज्जन, 19 से 22 अप्रैल तक भारत आए। कनाडा के साथ भारत के रक्षा संबंध अभी शुरुआती अवस्था में हैं, लेकिन यह उत्तरी अमेरिकी राष्ट्र के तकनीकी कौशल, ठंडी जलवायु विशेषज्ञता, और यहां तक कि कनाडा के रक्षा निर्माताओं के मेक इन इंडिया पहल का हिस्सा बनने की संभावना की वजह से लाभदायक हो सकता है।

8.2 मेक्सिको

2017 में मेक्सिको, राष्ट्र के भीतर आने वाली प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के साथ-साथ अमेरिका की निरंतर आलोचना से निपटता है। राष्ट्रपति ट्रम्प के बयानों में बार-बार मैक्सिकन लोगों का अपमान करने और मेक्सिको से अवैध प्रवासियों से संयुक्त राज्य अमेरिका की रक्षा हेतु दीवार बनाने कीबात करने की वजह से राष्ट्रपति पेना नीटो ने संयुक्त राज्य अमेरिका की अपनी यात्रा रद्द कर दी। उन्होंने यह भी कहा कि मेक्सिको सीमा की दीवार के लिए भुगतान करेगा जो दो देशों के बीच सबसे विवादास्पद मुद्दा रहा है।

मैक्सिको ने संयुक्त राज्य अमेरिका के नए राजदूत के रूप में उत्तरी अमेरिकी विकास बैंक के प्रमुख श्री गेरोनिमो गुतिरेज़ कोनियुक्त किया। श्री गुतिरेज़ ने श्री कार्लोस साडा का स्थान लिया, जिन्होंने उत्तर अमेरिकी संबंधों के लिए उप मंत्री पद संभाला।

नाफ्टा कीपुनः मध्यस्थता के साथ, मेक्सिको ने कनाडा के साथ अपने संबंधों को मजबूत किया। चीन और मैक्सिको ने नाफ्टा के पुन: समझौते के साथ-साथ मुक्त व्यापार समझौते के बारे में चर्चा शुरू की। यूरोपीय संघ और मैक्सिको के बीच वैश्विक समझौते को आधुनिक बनाने हेतु विचार-विमर्श किया गया। राष्ट्रपति पेना नीटो ने अपने व्यापार संबंधों में विविधता लाने के लिए चीन में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लिया। मेक्सिको ने इजरायल के साथ मजबूत आर्थिक संबंध भी बनाए। राष्ट्रपति नीटो ने जल्द से जल्द ट्रांस-पैसिफिक पार्टनरशिप (टीपीपी 11) को प्रभावी बनाने तु क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण व्यापारिक नेटवर्क और अन्य भागीदारों को मजबूत करने के लिए एपीईसी शिखर सम्मेलन में भाग लिया।

मेक्सिको ने वेनेजुएला संकट को हल करने के प्रयास किए। मैक्सिकन सरकार ने अगर राष्ट्रपति निकोलस पुरुरो की सरकार गिर गई तो वेनेजुएला के तेल कार्यक्रम पेट्रोकारिब को बदलने हेतु कदम उठाने की संभावना का अध्ययन करना शुरू कर दिया। वेनेज़ुएला में तनावपूर्ण राजनीतिक स्थिति को हल करने में मदद करने हेतु मैक्सिकन विदेश मंत्री ने हवाना का दौरा किया, क्योंकि बाद में प्रवासियों की संख्या में काफी वृद्धि देखी गई थी। इसके अलावा, मेक्सिको के साथ-साथ क्षेत्र के अन्य देशों में भूकंप और तूफान जैसी प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना पड़ा। बेलीज ने पुनर्निर्माण की प्रक्रिया पर एक साथ काम करने हेतुकैरीकॉम और मेक्सिको की सरकार के प्रमुखों के बीच ऐतिहासिक बैठक की मेजबानी की।

इस वर्ष के दौरान, मैक्सिकन सरकार ने देश के परमाणु परीक्षणों के विरोध में मेक्सिको परसोना नॉन ग्रेटाउत्तर कोरियाई राजदूत घोषित किया।

घरेलू तौर पर, मैक्सिकन सरकार को अपने नागरिकों के विरोध का सामना करना पड़ा। राष्ट्रपति पेना नीटो मेक्सिको के आंतरिक सुरक्षा कानून को अंतरराष्ट्रीय समुदाय से कड़ी आलोचना मिली, जिसमें कहा गया था कि नए कानून से मानव अधिकारों को खतरा है और नागरिकों की सुरक्षा खतरे में है। संयुक्त राष्ट्र के प्रतिनिधियों, मानवाधिकारों पर अंतर-अमेरिकी आयोग और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने उस कानून की निंदा की जिसमें नागरिक सुरक्षा संगठनों में सैन्य बलों को शामिल किया गया था।

मैक्सिकन सरकार ने भी घोषणा की कि वह पेट्रोल पर सब्सिडी देना बंद कर देगी। 1 जनवरी को 20% की वृद्धि हुई। इससे एक लीटर पेट्रोल की कीमत 18 पेसो (0.85 डॉलर; 0.70पाउंड) तक बढ़ गई। इससे पेट्रोल के एक गैलन का औसत मूल्य दैनिक न्यूनतम मजदूरी - 80 पेसो (3.77 डॉलर, 3.07पाउंड) के बराबर हो गया - और इस वृद्धि ने उन लोगों में नाराजगी पैदा कर दी जो अपनी नौकरी के लिए पेट्रोल पर निर्भर थे।

2018 में चुनावों के साथ, मेक्सिको की रूढ़िवादी विपक्षी नेशनल एक्शन पार्टी (पीएएन) और वामपंथी डेमोक्रेटिक रिवोल्यूशनरी पार्टी (पीआरडी) ने सत्तारूढ़ ॥ पार्टी और वामपंथी आंद्रेस मैनुअल लोपेज़ ओब्रेडोरको हटाने की कोशिश में 2018 के राष्ट्रपति चुनावों हेतु "व्यापक गठबंधन" का आह्वान किया है।

भारत-मेक्सिको द्विपक्षीय संबंध

द्विपक्षीय संबंधों परउच्च स्तरीय दौरे नहीं हुए। भारत और मेक्सिको क्षेत्रीय और वैश्विक निरस्त्रीकरण पर महत्वपूर्ण सम्मेलन आयोजित करने हेतु सहमत हुए हैं। यह बैठक भारतीय पक्ष से विदेश मंत्रालय (एमईए) के निरस्त्रीकरण प्रभाग के संयुक्त सचिव की अध्यक्षता में होगी। इसे मेक्सिको सिटी में 23 जून को आयोजित मैक्सिको-भारत संयुक्त आयोग (जेसीएम) की सातवीं बैठक और चौथे कार्यालय के विदेश दौर के परामर्श के दौरान किया गया था।

प्रमुख शक्तियां

9. प्रमुख शक्तियां

9.1 संयुक्त राज्य

वर्ष 2017 ने ओबामा प्रशासन से ट्रम्प प्रशासन के परिवर्तनकाल को चिह्नित किया। राष्ट्रपति ट्रम्प ने संयुक्त राज्य अमेरिका के 45वें राष्ट्रपति के रूप में सत्ता संभालीथी। कांग्रेस को अपने पहले संबोधन में, राष्ट्रपति ट्रम्प ने उल्लेख किया कि 8 नवंबर को चुनाव के बाद से शेयर बाजार में

लगभग 3 ट्रिलियन डॉलर कीराशि प्राप्त हुई है, जो एक रिकॉर्ड है। सरकार ने गैर-सैन्य और गैर-आवश्यक संघीय श्रमिकों को काम पर रखने का शुल्क निर्धारित किया। अपने अभियान के वादों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने अमेरिका को टीपीपी से अलग कर दिया और कनाडा तथा मैक्सिको के साथ मिलकर उत्तर अटलांटिक मुक्त व्यापार समझौता (नाफ्टा) फिर से शुरू कर दिया। राष्ट्रपति ट्रम्प ने जलवायु परिवर्तन पर पेरिस समझौते से भी अमेरिका को अलगकर दिया और कहा कि इससे अमेरिकी उद्योगों पर अनुचित बोझ पड़ा और विकास में बाधा उत्पन्न हुई। राष्ट्रपति ट्रम्प ने मध्य पूर्व और यूरोप में पदभार ग्रहण करने के बाद से अपनी पहली विदेश यात्रा की शुरुआत की। नाटो नेताओं की बैठक के लिए उन्होंने जिन देशों का दौरा किया वे सऊदी अरब, इज़राइल, इटली और बेल्जियम थे। राष्ट्रपति ट्रम्प ने टोर्मिना में जी7 बैठक के लिए सिसिली में यात्रा की। राष्ट्रपति ट्रम्प की वार्षिक शिखर बैठक के दौरान नाटो के अनुच्छेद पांच का समर्थन नहीं करने के लिए आलोचना की गई थी।

जर्मनी में जी20 शिखर सम्मेलन में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ ट्रम्प की पहली बैठक में संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस और जॉर्डन पश्चिम एशिया में "डी-एस्केलेशन समझौते" पर पहुंचे। उन्होंने सीरिया के लिए संघर्ष विरामपर सहमति व्यक्त की। सऊदी क्षमताओं को बढ़ाने के प्रयास में अमेरिकी सरकार ने सऊदी अरब को अपने उन्नत टर्मिनल हाई-एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस (थाड) की रक्षा प्रणाली को बेचने की मंजूरी दे दी। वर्ष के अंत में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने घोषणा की कि अमेरिका ने यरूशलम को इजरायल की राजधानी के रूप में मान्यता दी और जिससे वहां अमेरिकी दूतावास स्थापित किया जाया जाएगा।

अफ़ग़ानिस्तान और दक्षिण एशिया के प्रति अपनी नीति को रेखांकित करते हुएउन्होंने यह स्पष्ट किया कि अमेरिका अफगान सरकार का समर्थन करना जारी रखेगा, लेकिन वह चाहेगा कि पड़ोसी देशसक्रिय भूमिका निभाएं। राष्ट्रपति ट्रम्प ने अफगानिस्तान के लिए अपनी रणनीति की घोषणा करते हुए पाकिस्तान को विद्रोहियों को शरण देने हेतु दंडित करने की धमकी दी और भारत को अफगानिस्तान के भविष्य में अधिक शामिल होने हेतु आमंत्रित किया। अमेरिकी प्रशासन ने कहा कि इस्लामाबाद ने तालिबान और हक्कानी नेटवर्क जैसे आतंकवादी समूहों के खिलाफ जो कदम उठाए हैं, पाकिस्तान को अमेरिका की सुरक्षा सहायता "अनुकूलित" होगी। अपनी अफगानिस्तान नीति के अनुसरण में, अमेरिकी रक्षा मंत्री जेम्स मैटिस ने अफगानिस्तान का दौरा किया, जहां उन्होंने राष्ट्रपति अशरफ गनी सहित सरकारी अधिकारियों से मुलाकात की।

पूर्वी एशिया के अपने दौरे के दौरान, राष्ट्रपति ट्रम्प ने अपने आर्थिक सहयोगी चीन के रूप में जापान और दक्षिण कोरिया के सहयोगियों का दौरा किया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने वियतनाम में एशिया-प्रशांत देशों की बैठक में व्यापार पर एक मजबूत संदेश दिया, जिसमें कहा गया था कि अमेरिकी अब पुराने व्यापार अपमान को बर्दाश्त नहीं कर सकता है और निष्पक्ष और समान नीतियों पर जोर देगा। ट्रम्प ने कहा कि अमेरिका इस क्षेत्र में किसी भी देश के साथ द्विपक्षीय समझौता करने के लिए तैयार है, लेकिन केवल "आपसी सम्मान और पारस्परिक लाभ" के आधार पर।

ईरान के मुद्दे पर अमेरिकी राष्ट्रपति ने ईरान परमाणु समझौते से हटने की बात कही। हालांकि, प्रमाणन को वापस लेने के अलावा, प्रशासन और अमेरिकी कांग्रेस ने इस सौदे में बदलाव नहीं किया।

उत्तर कोरिया परराष्ट्रपति ट्रम्प ने यह स्पष्ट किया कि सैन्य सहित सभी विकल्प संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए उपलब्ध हैं और उत्तरी कोरिया को चेतावनी दी कि वे क्षेत्रीय और वैश्विक शांति हेतु रणनीतिक खतरा पैदा न करें।

राष्ट्रपति ट्रम्प ने अपने प्रशासन के ब्लूप्रिंट के साथ वर्ष का समापन अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति पेश किया। व्यापक दस्तावेज एक ऐसी विश्वासघाती दुनिया की चेतावनी देता है जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका उभरते रूस और चीन से बढ़ते खतरों का सामना करता है, साथ ही साथ इसमें उत्तर कोरिया और ईरान जैसे सरकारें भी शामिल हैं।

घरेलू मोर्चे परप्रशासन को लगातार आरोपों की चुनौती का सामना करना पड़ा कि अमेरिकी राष्ट्रपति चुनावों में रूसी हस्तक्षेप से छेड़छाड़ की गई थी, और अमेरिकी कांग्रेस ने उसकी जांच की। राष्ट्रपति ट्रम्प ने मई 2017 में एफबीआई के पूर्व निदेशक जेम्स कॉमी को निकाल दिया। कोमी ने ट्रंप की उम्मीदवारी को बढ़ावा देने हेतु विकसित किए गए 2016 में रूसी हस्तक्षेप से संबंधित चल रहे आतंकवाद और आपराधिक जांच में संभावित व्हाइट हाउस के हस्तक्षेप के बारे में सीनेट खुफिया समिति के समक्ष गवाही दी। इस तरह के आरोपों ने राष्ट्रपति ट्रम्प की रूस के साथ बेहतर संबंध बनाने की क्षमता में बाधा डाली, जो उनके अभियान में से एक था। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने कानून कानून में हस्ताक्षर किए, जिसने रूस के खिलाफ नए प्रतिबंध लगाए और मास्को के खिलाफ प्रतिबंधों को कम करने हेतु ट्रम्प की खुद की क्षमता को प्रतिबंधित कर दिया। राष्ट्रपति ट्रम्प को अपनी आव्रजन नीतियों के कारण आलोचना का भी सामना करना पड़ा। राष्ट्रपति ट्रम्प ने कार्यकारी आदेशों पर हस्ताक्षर किए जिसके कारण कुछ मुस्लिम बहुसंख्यक देशों से आने वाले शरणार्थियों के लिए यूएस रिफ्यूजी एडमिशन प्रोग्राम को स्थगित कर दिया गया। डेमोक्रेट्स ने वर्जीनिया और न्यू जर्सी में महत्वपूर्ण मुकाबले जीते, जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के कार्यकाल के दौरान उनकी पहली बड़ी जीत है और 2018 के मध्य के लिए बढ़त है, जो यूएस हाउस और सीनेट के नियंत्रण के समय उपयोगी होगी।

भारत-अमेरिका द्विपक्षीय संबंध

द्विपक्षीय पहलू प, भारत और अमेरिका के बीच संबंधों में प्रगति जारी रही। द्विपक्षीय पहलू पर, भारत और अमेरिका के बीच संबंधों में प्रगति जारी रही। 26 जून को वाशिंगटन, डी.सी. की आधिकारिक यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी कि मेजबानी व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति ट्रम्प द्वारा की गई थी। उन्होंने भारत-प्रशांत क्षेत्र के नेतृत्व के बारे में बात की, वैश्विक आतंकवाद से लड़ने, राष्ट्रों से नेविगेशन की स्वतंत्रता पर अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन करने और निष्पक्ष तथा मुक्त व्यापार बढ़ाने के लिए आह्वान किया। विदेश मंत्री सुश्री स्वराज ने संयुक्त राष्ट्र महासभा (18-24 सितंबर 2017) के 72 सत्र को संबोधित करने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका का दौरा किया। उनके बयान में आतंकवाद के खिलाफ लड़ने के लिए राष्ट्रों का आह्वान किया गया और विशेष रूप से सीमा पार

आतंकवाद पर बात की गई, जिनका सामना भारत कर रहा है। उन्होंने यह सुनिश्चित करते हुए अपनी अर्थव्यवस्था के समावेशी विकास हेतु भारत की योजनाओं के बारे में भी बताया।

राज्य के सचिव श्री रेक्स टिलरसन ने 25 अक्टूबर 2017 को भारत का दौरा किया, पीएम मोदी, विदेश मंत्री सुश्री स्वराज और एनएसए अजीत डोभाल से मुलाकात करते हुए, उन्होंने आतंकवाद के मुद्दों पर चर्चा की, अफगानिस्तान को समर्थन और पाकिस्तान से आतंकवादी समूहों के लिए सुरक्षित पनाहगाहों को हटाने हेतु कदम उठाने का आग्रह किया। अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (एनएसए) लेफ्टिनेंट जनरल एच. आर. मैकमास्टर ने दक्षिण एशिया की अपनी पहली यात्रा से पहले अपने भारतीय समकक्ष अजीत डोभाल और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ वार्ता के दौरान अमेरिका के "प्रमुख रक्षा भागीदार" के रूप में भारत की स्थिति की फिर से पुष्टि की। जनरल वीके सिंह ने अमेरिकी विदेश मंत्री रेक्स टिलरसन से मनीला में आसियान विदेश मंत्रियों की बैठक के मौके पर मुलाकात की। अमेरिकी रक्षा मंत्री जेम्स मैटिस ने नई दिल्ली का दौरा किया। मैटिस की यात्रा के दौरान, भारत ने अमेरिका को स्पष्ट कर दिया कि वह युद्धग्रस्त अफगानिस्तान में सैनिकों को तैनात नहीं करेगा। भारत और अमेरिका ने आतंकवाद के वैश्विक संकट से निपटने के लिए अपनी प्रतिबद्धता की फिर से पुष्टि की। अमेरिका ने भारतीय नौसेना के भविष्य के विमान वाहक के लिए महत्वपूर्ण इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एयरक्राफ्ट लॉन्च सिस्टम जारी करने का भी फैसला किया। भारत में अमेरिका के नए राजदूत केनेथ जस्टर ने राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद को अपनापरिचय पत्र सौंपा।

9.2 चीन

चीनी सरकार ने कहा कि 2017 चीन और दुनिया दोनों के लिए विशेष महत्व वाला साल रहा। चीनी विदेश मंत्रालय ने निम्नलिखित पाँच पहलुओं में अपनी उपलब्धियों पर प्रकाश डाला:

सबसे पहले, चीन ने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को संयुक्त रूप से शुरू करने का खाका खींचा। बीजिंग में राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अंतर्राष्ट्रीय सहयोग (बीआरएफ) के लिए पहले बेल्ट एंड रोड फोरम की सफलतापूर्वक अध्यक्षता की। 29 विदेशी देशों के राज्य / सरकार के प्रमुख, 130 से अधिक देशों के वरिष्ठ प्रतिनिधि और 70 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रमुखों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया।

हालांकि, यहां यह ध्यान देने की आवश्यकता है कि भारत ने बीआरएफमें भाग नहीं लिया था। दूसरा, चीन ने आर्थिक वैश्वीकरण की जोरदार वकालत की। जनवरी 2017 में राष्ट्रपति शी जिनपिंग की दावोस यात्रा ने वैश्विक आत्मविश्वास को बढ़ाया और आर्थिक वैश्वीकरण हेतु आगे बढ़ने का मार्ग प्रशस्त किया। तीसरा, चीन ने प्रमुख देशों के बीच स्थिर संबंधों का आह्वानकिया। चौथा, चीन ने अपने पड़ोस में स्थिरता और क्षेत्रीय सहयोग की ध्वनि गति को बनाए रखने की दिशा में काम किया।पांचवां, चीनी विदेश मंत्रालय ने उल्लेख किया कि पांच ब्रिक्स देशों के ठोस प्रयासों और विभिन्न निराशावादी बयानबाजी के बावजूद ब्रिक्स तंत्र की वृद्धि, और ब्रिक्स ज़ियामी शिखर सम्मेलन में सफलता मिली।

चीन के विदेश मंत्रालय ने यह भी कहा कि चीन की कम्युनिस्ट पार्टी (अक्टूबर 2017) की 19वीं राष्ट्रीय कांग्रेस ने चीन के बाहरी संबंधों के लिए पाठ्यक्रम को पूरा करते हुए बड़ी सफलता हासिल की। महासचिव शी जिनपिंग ने कांग्रेस को अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट किया कि चीन अंतरराष्ट्रीय संबंधों के एक नए रूप को बढ़ावा देने और मानव जाति हेतु साझा भविष्य के साथ समुदाय बनाने का प्रयास करेगा।

जनवरी 2017 में चीन ने एशिया-प्रशांत सुरक्षा सहयोग पर चीन की नीतियों का अपना श्वेत पत्र जारी किया। यह श्वेत पत्र "इसकी सुरक्षा और विकास के हित चीन के आधुनिकीकरण अभियान में रणनीतिक कार्य है।"

जून 2017 में, "बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत समुद्री सहयोग के लिए विजन" संयुक्त रूप से राष्ट्रीय विकास और सुधार आयोग और चीन के राज्य महासागरीय प्रशासन द्वारा जारी किया गया था।

2017 में भारत-चीन संबंध

वर्ष 2017 भारत-चीन संबंधों के लिए शांति कावर्ष नहीं था। हालांकि, भारत और चीन दोनों ने बहुपक्षीय और द्विपक्षीय स्तर पर उच्च स्तरीय आदान-प्रदान जारी रखा, डोकलाम क्षेत्र में उत्पन्न हुई स्थिति को भारत और चीन के बीच राजनयिक चर्चा के बाद हल किया गया था। 2017 की कुछ महत्वपूर्ण बैठकें / कार्यक्रम इस प्रकार सूचीबद्ध किए जा सकते हैं:

9 जून 2017 को अस्ताना में शी जिनपिंग के साथ प्रधानमंत्री मोदी की बैठक

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति शी जिनपिंग को चीन द्वारा एससीओ में भारत के समर्थन के लिए धन्यवाद दिया।

डोकलाम विघटन पर समझ

2017 में, डोकलाम क्षेत्र में आमने-सामने की स्थिति पैदा हुई, जिसे भारत और चीन के बीच राजनयिक चर्चा के बाद हल किया गया था, जिसके आधार पर दोनों पक्ष आमने-सामने स्थलपर अपने सीमा कर्मियों को हटाने पर सहमत हुए।

भूटान के डोकलाम क्षेत्र में भारतीय और चीनी सीमा कर्मियों के बीच आमने-सामने की स्थिति तब शुरू हुई जब चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (पीएलए) की एक बड़ी निर्माण कंपनी ने 16 जून 2017 को इस क्षेत्र में प्रवेश किया और भूटान और भारत दोनों के साथ अपनी मौजूदा समझ के उल्लंघन के क्षेत्र मेंसड़क बनाकर यथास्थिति को बदलने की कोशिश की। भूटान और भारत दोनों ने मौजूदा प्रोटोकॉल और समझ के अनुसार चीन से संपर्क किया, ताकि यथास्थिति को बदलने के उद्देश्य से चीनी कार्रवाई को रोका जा सके। इन प्रयासों के विफल होने के बाद ही भारतीय सीमा के कर्मियों ने, भूटान के साथ निकट परामर्श और समन्वय में, सड़क निर्माण को रोकने हेतु हस्तक्षेप किया।

डोकलाम क्षेत्र में भारतीय और चीनी सीमा कर्मियों को हटाने का कार्य 28 अगस्त 2017 को पूरा हुआ था।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नौवीं वार्षिक ब्रिक्स शिखर सम्मेलन, ज़ियामी के 5 सितंबर, 2017 को राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ द्विपक्षीय बैठक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 सितंबर 2017 को ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के मौके पर राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की। द्विपक्षीय बैठक के दौरान एक अन्य महत्वपूर्ण बिंदु प्रकाश डाला गया था कि सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और स्थिरता हमारे संबंधों के आगे विकास हेतु एक शर्त थी और दोनों पक्षों के बीच आपसी विश्वास के स्तर को वास्तव में बढ़ाने और मजबूत करने हेतु अधिक प्रयास किए जाने चाहिए।

9.3 यूरोपीय संघ

यूरोपियन यूनियन ने 25 मार्च, 2017 को रोम की संधियों पर हस्ताक्षर करने की 60वीं वर्षगांठ मनाई। इस समारोह के अंत में नेताओं ने अपनाए गए घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए एवं भविष्य के लिए एक संयुक्त दृष्टिकोणअपनाने की बात की। यूरोपीय संघ में पूरे साल आर्थिक विकास दर्ज किया गया। यूरोपीय संघ में सुधार हेतु आह्वान को और मजबूती मिली। हालांकि अभी तक दक्षिणी दलों ने अपने चुनावी आधार को बड़ा किया, लेकिन प्रमुख मामलों में, मुख्यधारा की पार्टियां सत्ता में रहीं, सरकारें बनीं। फ्रांस में एक नई पार्टी चुनाव जीतने में सफल रही। सुदूर राष्ट्रीय मोर्चा के उम्मीदवार मरीन ले पेन के खिलाफ फ्रांसीसी राष्ट्रपति चुनाव में इमैनुएल मैक्रॉन की जीत को यूरोपीय संघ के सुधारों के साथ-साथ यूरोपीय एकीकरण हेतु राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण माना जाता था। जर्मन संघीय चुनावों में, चांसलर मैर्केल के सीडीयू और सामाजिक डेमोक्रेट दोनों के लिए समर्थन में अपेक्षाकृत गिरावट आई। जर्मनी (एएफडी) के लिए बहुत दूर की पार्टी के विकल्प ने जीत दर्ज की और जर्मन संसद में प्रवेश किया। चांसलर मैर्केल ने सोशल डेमोक्रेट्स के साथ एक और महागठबंधन का गठजोड़ किया। नीदरलैंड में एक अन्य महत्वपूर्ण चुनाव में, जेरेट वाइल्डर्स की बहुत दूर की फ्रीडम पार्टी ने अपना वोट शेयर बढ़ाया लेकिन प्रधानमंत्री मर्क रुटे की पार्टी चुनावों में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी और क्रिश्चियन डेमोक्रेट्स, डी66 और क्रिश्चियन यूनियन के साथ गठबंधन सरकार बनाने में कामयाब रही।

यूरोपीय संघ को प्रवासी संकट, यूक्रेन संकट और सामाजिक आर्थिक मुद्दों की चुनौतियों का सामना करना पड़ा। 2017 में प्रवासियों काअन्तर्वाह कम हुआ; यूरोपीय संघ को कोटा प्रणाली के अनुसार नियोजित प्रवासियों को बसाने में संघर्ष का सामना करना पड़ा। कुछ सदस्य राज्यों ने शरणार्थियों और प्रवासियों को अपनाने से इनकार कर दिया। यूरोपीय संघ और उसके सदस्य राज्यों के बीच अंतर देखे गए।

ब्रेक्सिट पर बातचीत शुरू हुई। लेकिन अनिश्चितता यूरोपीय संघ और ब्रिटेन के बीच अंतिम समझौते पर बनी रही। हालांकि यूके और यूरोपीय संघ ने अपनी बातचीत में आगे बढ़ने का फैसला किया, लेकिन वार्ता काफी जटिल रही। प्रधानमंत्री थेरेसा मे द्वारा कराए गए स्नैप चुनाव ने कंजर्वेटिव पार्टी में उनकी स्थिति को कमजोर कर दिया।

बाहरी रूप से, ट्रम्प प्रशासन की नीति ने जलवायु परिवर्तन, व्यापार शुल्क, बोझ साझाकरण- अधिक रक्षा व्यय, पारगमन साझेदारी में मध्य पूर्व के क्षेत्रों में अंतर को और अधिक बढ़ा दिया। यूरोपीय देशों ने अधिक से अधिक रक्षा सहयोग की तलाश की। 25 सदस्य राज्यों ने आपस में रक्षा सहयोग के विस्तार हेतु स्थायी संरचित सहयोग (पी.ई.एस.सी.ओ.) पर हस्ताक्षर किए। यूरोपीय संघ ने यूक्रेन में शांति और स्थिरता लाने की कोशिश की। उन्होंने मिन्स्क समझौते के कार्यान्वयन पर जोर दिया। यूरोपीय संघ कतर संकट, लेबनान के प्रधानमंत्री साद हरीरी के इस्तीफे और मध्य पूर्व क्षेत्र में बाद के विकास सहित संकटों को फैलाने के प्रयासों को रोकने में भी सक्रिय भूमिका में था। रूस के साथ तनाव जारी रहा, लेकिन नए फ्रांसीसी राष्ट्रपति मैक्रोन ने सीरिया सहित रूस के क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों के साथ सहयोग के बारे में बात की। यूरोपीय देशों ने ईरान के साथ परमाणु समझौते का बचाव किया, हालांकि उन्हें ईरान मिसाइल कार्यक्रम और इसकी क्षेत्रीय भूमिका पर चिंता व्यक्त की थी। राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगन द्वारा तख्तापलट और उसके बाद की कार्रवाइयों के बाद यूरोपीय संघ-तुर्की संबंध भी तनावपूर्ण हो गए। यूरोपीय देशों ने तुर्की में राजनीतिक विकास और मानव अधिकारों पर अपनी चिंता व्यक्त की थी।

भारत और यूरोपीय देशों के बीच द्विपक्षीय संबंध

पुर्तगाल के प्रधानमंत्री एंटोनियो कोस्टा 6-12 जनवरी 2017 के दौरान भारत आए थे। प्रधानमंत्री कोस्टा ने 8-9 जनवरी 2017 को बेंगलुरु में मुख्य अतिथि के रूप में प्रवासी भारतीय दिवस में भाग लिया और इसके साथ-साथकुछ व्यावसायिक कार्यक्रमों में भी शामिल हुए। उन्होंने 10 जनवरी 2017 को गांधीनगर में वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट में भी भाग लिया।

साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस अनास्तासीड्स ने 25 से 29 अप्रैल, 2017 तक भारत की राजकीय यात्रा की। राष्ट्रपति अनास्तासीड्स ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता हेतु साइप्रस के समर्थन की पुष्टि की। उन्होंने यह भी कहा कि 48-सदस्यीय ब्लॉक के सदस्य के रूप में उनका देश परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह (एनएसजी) की सदस्यता हेतु भारत की बोली का समर्थन करता है।

भारत के उपराष्ट्रपति, हामिद अंसारी ने 24 अप्रैल, 2017 से आर्मेनिया और पोलैंड की पांच दिवसीय आधिकारिक यात्रा की। पोलिश प्रधानमंत्री बीटा स्ज़ाइडलो ने मजबूत व्यापार संबंधों और अधिक निवेश की वकालत की। पोलैंड ने एनएसजीमें भारत की सदस्यता और यूएनएससीमें स्थायी सदस्यता का समर्थन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीन यूरोपीय देशों, यानि जर्मनी, स्पेन और फ्रांस का दौरा किया। अपनी यात्रा के पहले चरण में, प्रधानमंत्री मोदी ने जर्मनी का दौरा किया और जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल और जर्मन राष्ट्रपति फ्रैंक-वाल्टर स्टीनमीयर से मुलाकात की। भारत ने डिजिटलीकरण, सशक्तीकरण और आर्थिक प्रभाव, कौशल विकास, साइबर नीति, वैकल्पिक चिकित्सा, रेलवे सुरक्षा, सतत विकास और शहरी विकास के क्षेत्रों में सहयोग हेतु जर्मनी के साथ 12 संयुक्त घोषणापत्र (जेडीआई) और समझौतों पर हस्ताक्षर किए। जर्मनी के बाद, प्रधानमंत्री ने स्पेन की यात्रा की। 1988 के बाद यह किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यात्रा थी। उन्होंने किंग फिलिप VI और प्रधानमंत्री मारियानो

राजोय से मुलाकात की। दोनों देशों ने साइबर सुरक्षा, नागरिक उड्डयन, नवीकरणीय ऊर्जा, आदि के क्षेत्र में सहयोग पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। अपनी यात्रा के अंतिम चरण में, प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस गए। उन्होंने 3 जून, 2017 को नव-निर्वाचित फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रॉन के साथ मुलाकात की। दोनों नेताओं ने पारस्परिक महत्व के मुद्दे पर चर्चा की।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जून 2017 में पुर्तगाल और नीदरलैंड का दौरा किया। यह किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा पुर्तगाल का पहला द्विपक्षीय दौरा था। उन्होंने द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देने हेतु अपने पुर्तगाली समकक्ष एंटोनियो कोस्टा के साथ बातचीत की। भारत और पुर्तगाल ने आतंकवाद, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष, जलवायु अध्ययन के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर बातचीत की। नीदरलैंड में, प्रधानमंत्री मोदी ने अपने समकक्ष प्रधानमंत्री मार्क रुटे के साथ वार्ता की। उन्हें राजा विलेम-अलेक्जेंडर द्वारा निमंत्रण दिया गया और उन्होंने रानी मैक्सिमा से मुलाकात की।

14वें भारत-यूरोपीय संघ का शिखर सम्मेलन 6 अक्टूबर 2017 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष डोनाल्ड टस्क और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष जीन क्लाउड जुनकर ने शिखर सम्मेलन में यूरोपीय संघ का प्रतिनिधित्व करने हेतु नई दिल्ली का दौरा किया। भारत और यूरोपीय संघ ने माना कि वे प्राकृतिक रुप से साझेदार हैं और रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता की पुनः पुष्टि की।

बेल्जियम के राजा फिलिप और रानी मैथिल्डे 5 नवंबर 2017 को सात दिवसीय भारत यात्रा पर आए, जिसमें बेल्जियम की कंपनियों के सीईओ का एक व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल भी शामिल था।

इतालवी प्रधानमंत्री पाओलो जेंटिलोनी ने अक्टूबर 2017 में भारत का दौरा किया। जीन- यवेस ले ड्रियन, फ्रांस के यूरोप और विदेश मामलों के मंत्री ने 17 से 19 नवंबर, 2017 तक भारत का दौरा किया। भारत और फ्रांस ने भारत-फ्रांस द्विपक्षीय संबंधों की पूरी श्रृंखला की समीक्षा की और इसमें पारस्परिक हित के क्षेत्रीय, वैश्विक और बहुपक्षीय मुद्दों पर विचारों का आदान-प्रदान किया।

9.4 रूस

वर्ष 2017 में, रूस 2016 के अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में देश की भागीदारी और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प की जीत के विवाद में घिर गया था। रूस पर आरोप लगाया गया था कि वह चुनाव पर ध्यान केंद्रित कर रहा था जिससे क्रेमलिन ने इनकार कर दिया था। इन आरोपों के कारण दोनों देशों के बीच संबंध कड़वे हो गए। 1 जून को राष्ट्रपति पुतिन ने स्वीकार किया कि कुछ "देशभक्त" लोग हैकिंग में लगे हुए हो सकते हैं, लेकिन रूस ने एक देश के तौर पर कभी ऐसा नहीं किया।[151] हालांकि, जेल गए एक रूसी हैकर ने क्रेमलिन के निर्देशों पर डेमोक्रेटिक नेशनल कमेटी के कंप्यूटरों में हैक करने की बात कही।[152]

रूस और अमेरिका के संबंधों का प्रभाव क्षेत्रीय और अन्य वैश्विक मुद्दों पर भी पड़ा। क्रीमिया के संबंध में तनाव तब भी जारी रहा जब तक यूक्रेन के संबंध में रूस पर प्रतिबंधों कायम रहा जब तक कि उसने क्रीमिया का यूक्रेन पर पूर्ण नियंत्रण वापस नहीं कर लिया। रूस ने मॉस्को पर प्रतिबंधों को

"पूर्ण आर्थिक युद्ध" के रूप में देखा।[153] रूस ने अमेरिका और यूरोपीय संघ पर अपने प्रतिबंधों को जारी रखा। हालांकि, 2017 के पहले छह महीनों में यूरोपीय संघ-रूस व्यापार में €27 बिलियन की वृद्धि हुई।[154] ईरानी मुद्दे पररूस ने ईरान का समर्थन जारी रखा तथा उत्तर कोरिया पर अमेरिका के हमले पर अमेरिका को चेतावनी दी।[155] हालांकि रूस ने उत्तर की परमाणु बोली को स्वीकार नहीं किया, लेकिन अपने परमाणु कार्यक्रम को रोकने हेतु उत्तर कोरिया के साथ जबरदस्ती करने में रूस और चीन की बड़ी भूमिका चाहता था।[156] रूस राष्ट्रपति बशर अल-असद के नेतृत्व में सीरियाई सरकार का समर्थक बना रहा। दोनों देशों ने सीरिया के टारटस में रूसी नौसैनिक अड्डे के विकास और आधुनिकीकरण के साथ-साथ सीरिया में रूसी एयरोस्पेस फोर्स के विमान तैनाती के लिए शर्तों को पूरा करने वाले प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए।[157] क्रेमलिन ने कहा कि रूस सीरिया में एक नौसैनिक और एक हवाई अड्डा रखेगा।[158] सेना ने कहा कि पहली रूसी सेना 12 दिसंबर को सीरिया में अपनी तैनाती से घर लौटी थी।[159] रूस ने युद्धग्रस्त देश से सैनिकों को वापस लेने के आदेश के बावजूद सीरिया में रूस की नौसेना की उपस्थिति का विस्तार करने के लिए 50 साल के समझौते (2092 तक) पर हस्ताक्षर किए। रूस ने अतिरिक्त 50 वर्षों के लिए खमीमिम में अपने पश्चिमी सीरियाई एयरबेस पर पट्टे का नवीनीकरण किया।[160]

रूस ने आर्कटिक में सोवियत सेना, वायु और रडार बेस को फिर से खोला।[161] रूस ने आर्कटिक क आधा मिलियन वर्ग मील पर दावा किया है और 29 अप्रैल को पत्रकारों को सोवियत-युग के बेस, अलकुर्ती के आधार के नवीनीकरण हेतु आमंत्रित किया है। 11 मई को आर्कटिक काउंसिल की द्विवार्षिक मंत्रिस्तरीय बैठक में, अमेरिका, रूस और छह अन्य आर्कटिक राष्ट्रों ने सर्कुलेटर्स नॉर्थ में विज्ञान पर सहयोग करने का वादा किया, बाधाओं को दूर करने और सुदूर उत्तर में सीमाओं के पार काम करने के बीच आदान-प्रदान बढ़ाने हेतु बाध्यकारी समझौते पर हस्ताक्षर किए गए।[162]

153"Russia blasts US sanctions as'economicwar'", Timesof India,August 3,2017.

http://timesofindia.indiatimes.com/world/us/russia-blasts-us-sanctions-as-economic-war/articleshow/59897622.cms

154Francesco Giumelli, "EU-Russia trade bouncing back despite sanctions", EU Observer, October 17, 2017. https://euobserver.com/opinion/139485

155"'Negative consequences' if Trumpquits Irandeal: Russia",The Hindu,October 9,2017.http://www.thehindu.com/news/international/negative-consequences-if-trump-quits-iran-deal-russia/article19829143.ece.; "Russia warns US against 'Syria-style' actions in N. Korea", RT, April 17, 2017. https://www.rt.com/news/385039-russia-warns-us-north-korea/

156"Japan becoming ground zero for U.S. military buildup in Asia, Russia's Lavrov says", Japan Times, November 25, 2017. https://www.iapantimes.co.ip/news/2017/11/25/national/politics-diplomacv/russia-takes- tokyo-task-defense-alliance-washington/#.WhunOFWWbIU

157"Russia to Expand Capabilities of Naval Base in Syrian Tartus", Sputnik, January 20, 2017. https://sputniknews.com/militarv/201701201049836303 -base-naval-russia-svria/

158 Denis Pinchuk, “Russia will keep bases in Syria to strike at insurgents: Kremlin”, Reuters, December 12, 2017. https://www.reuters.com/article/us-mideast-crisis-svria-russia-withdrawa/russia-will-keep-bases-in-svria- to-strike-at-insurgents-kremlin-idUSKBN1E610F.

159“Russiabeginspartial withdrawalfrom Syria”,TheHindu,December12,2017.http://www.thehindu.com/news/international/russia-begins-partial-withdrawal-from-svria/article21543545.ece

160“Russia Rules Out Further Military Expansion”, The Moscow Times, December 25, 2017. https://themoscowtimes.com/news/russia-rules-out-further-militarv-expansion-60040

161“Russiamakesbigmilitary push inArctic”, The Hindu, January31,2017.http://www.thehindu.com/news/international/Russia-makes-big-militarv-push-in-Arctic/article17124634.ece

162Yereth Rosen, “Science cooperation promised in newly signed Arctic Council agreement”, Adn.com, Mav 12, 2017. https://www.adn.com/arctic/2017/05/11/science-cooperation-promised-in-newlv-signed-arctic-council- agreement/

रक्षा क्षेत्र में, रूसी सशस्त्र बलों को 59.5 प्रतिशत तक आधुनिक आयुध के साथ पुनः हथियारबंद किया गया है। सैनिकों को आयुध के 3,000 से अधिक नमूने दिए गए हैं। 2017 में सैन्य बुनियादी ढांचा विकसित किया गया है। कुल मिलाकर, 3,000 सुविधाएं बनाई, पुनर्निर्माण और पुनर्प्राप्त की गई हैं। पिछले साल की तुलना में कॉम्बैट ट्रेनिंग तेज हो गई है। कुल मिलाकर, छह अप्रत्याशित निरीक्षण तथा कुछ 15,000 कार्यक्रम युद्ध प्रशिक्षण कार्यक्रम हुए। झापड़2017 रूस- बेलारूस रणनीतिक अभ्यास युद्ध प्रशिक्षण का मुख्य कार्यक्रम था। दो सशस्त्र बलों ने अमेरिका रक्षा हेतु अपनी तत्परता की पुष्टि की।[163] रूस के 2017 के रक्षा खर्च 61.2 बिलियन डॉलर तक पहुंच गए और दुनिया भर के सबसे बड़े सैन्य खर्च करने वालों की सूची में मास्को को शीर्ष-15 में 4वां स्थान मिला।[164] इसके अलावा, रूस ने सीरिया में 162 प्रकार के समकालीन और आधुनिक हथियारों का परीक्षण किया, जिसमें उच्च स्तर की प्रभावशीलता दिखाई दी।[165]

भारत रूस द्विपक्षीय संबंध

दोनों देशों ने राजनयिक संबंध की स्थापना की अपनी 70वीं वर्षगांठ मनाई। इसे मनाने हेतु विदेश मंत्रालय ने विभिन्न थिंक-टैंक और अन्य संघों के साथ मिलकर इस अवसर पर ट्रैक 2, ट्रैक 1.5 संवाद, वीडियो कॉन्फ्रेंस, कार रैली और सांस्कृतिक कार्यक्रमों आदि जैसे कई कार्यक्रमों का आयोजन किया। 2017 में वार्षिक शिखर सम्मेलन सहित हर स्तर पर दौरे जारी रहे।

भारत और रूस के बीच 18वें वार्षिक शिखर सम्मेलन के दौरान, जो जून 2017 को हुआ था, दोनों देशों ने के.के.एन.पी.पी. इकाइयों 5 और 6 के लिए इस तरह के समझौते की विस्तृत श्रृंखला में सहयोग से संबंधित 12 दस्तावेजों पर निष्कर्ष निकाला।18वें शिखर सम्मेलन में "सेंट पीटर्सबर्ग घोषणा" को अपनाने पर भी भारत और रूस के बीच बहुआयामी सहयोग पर प्रकाश डाला गया।घोषणा-पत्र में भविष्य के सहयोग हेतु एक व्यापक मैट्रिक्स भी प्रदान किया गया।सेंट पीटर्सबर्ग की इस यात्रा के दौरान, भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोलह रूसी क्षेत्रों के गवर्नर के साथ एक

अलग बैठक की, जहां उन्होंने भारतीय और रूसी क्षेत्रों के बीच सहयोग बढ़ाने से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की। पीएम मोदी ने गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में सेंट पीटर्सबर्ग इंटरनेशनल इकोनॉमिक फोरम में भी हिस्सा लिया। इसके बाद पीएम मोदी और राष्ट्रपति पुतिन ने जून 2017 में अस्ताना एससीओ शिखर सम्मेलन और जुलाई 2017 में हैम्बर्ग में जी20 शिखर सम्मेलन में मुलाकात की।[166]

रूसी संघीय सीमा शुल्क सेवा के आंकड़ों के अनुसार, 2017 के दौरान द्विपक्षीय व्यापार 7.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर था।[167]

बहुपक्षीय मंचों में रूस और भारत के बीच सहयोग भी जारी रहा। जून 2017 में भारत शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) का सदस्य बना।

163"Russian Minister of Defence General of Army Sergei Shoigu holds teleconference with Armed Forces leadership", Ministry of Defence of the Russian Federation, December 26,2017.http://eng.mil.ru/en/newspage/country/more.htm?id=12156325@egNews

164"Russia the 4th in Top 15 military defense spending around the world", Army Recognition, March 31, 2018,http://www.armyrecognition.com/march_2018_global_defense_security_army_news_industry/russia_the_4th_in_top_15_military_defense_spending_around_the_world.html

165Lucian Kim, "Russian Defense Minister Says His Military Has Tested 162 Weapons In Syria", NPR, February 23,2017. http://www.npr.org/sections/parallels/2017/02/23/516895124/russian-defense-minister-says-his-military-has-tested-162-weapons-in-syria

166"India-Russia Relations",MinistryofExternalAffairs,August2017.

http://www.mea. gov.in/Portal/ForeignRelation/Russia_August_2017.pdf

167"India-Russia Relations",MinistryofExternalAffairs,August2017.

http ://www.mea. gov.in/Portal/ForeignRelation/Russia_August_2017.pdf

दोनों देश ब्रिक्स और रूस-भारत-चीन (आरआईसी) में साथ काम करते रहे। सितंबर को आयोजित 9वें ब्रिक्स बैठक का मुख्य आकर्षण सदस्यों द्वारा आतंकवाद के हर प्रारुप की निंदा था। उन्होंने यह भी पुष्टि की कि आतंकवादी कृत्यों को करने, संगठित करने या समर्थन करने के जिम्मेदार लोगों को जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए।[168]11 दिसंबर 2017 को नई दिल्ली में हुई आरआईसी के विदेश मंत्रियों की 15वीं त्रिपक्षीय बैठक के दौरान, तीन विदेश मंत्रियों ने चार व्यापक क्षेत्रों, यानि आर्थिक और विकासात्मक मुद्दे; आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई; वैश्विक अर्थव्यवस्था, आतंकवाद के खतरे, अंतरराष्ट्रीय संगठित अपराध, ड्रग्स की तस्करी, प्राकृतिक और मानव निर्मित आपदाओं, जलवायु परिवर्तन, और मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका में बदलते राजनीतिक परिदृश्य को कवर करते हुए वैश्विक / बहुपक्षीय मुद्दे; और, क्षेत्रीय मुद्दे पर चर्चा की।[169]

168 "BRICS Leaders Xiamen Declaration", BRICS Post, September 8, 2017.https://www.brics2017.org/English/Documents/Summit/201709/t20170908 2021 .html.

169 “15th Russia-India-China Trilateral Foreign Ministers’ Meeting New Delhi, 11th December 2017’, Embassy of India, December 11, 2017.http://indianembassy.ruindex.php/en/media-news/press-releases/2130-15th-mssia-india-chim-trilatsral-forsign-ministers-meeting

बहुपक्षीय और अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक विकास

10 बहुपक्षीय और अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक विकास

2017 में वैश्विक आर्थिक स्थिति

वर्ष 2017 में वैश्विक अर्थव्यवस्था में दो प्रकार के विकास द्वारा संशयवाद उत्पन्न हुआ।सबसे पहले, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के नए अमेरिकी प्रशासन ने जनवरी 2017 में अमेरिकी नौकरियों की रक्षा तथा 12-राष्ट्र ट्रांस-पैसिफिक पार्टनरशिप (टीपीपी) व्यापार समझौते से अपनी वापसी हेतु अपनी व्यापार रणनीति की घोषणा की।इसके बाद नाफ्टा व्यापार समझौते को फिर से शुरू करने का फैसले किया गया। दूसरा, आधिकारिक ब्रेक्सिट वार्ता 19 जून, 2017 को जनमत संग्रह के एक साल बाद शुरू हुई। फिर भी, वर्ष 2017 के अंत तक, वैश्विक अर्थव्यवस्था में सुधार देखा गया। संयुक्त राष्ट्र द्वारा 11 दिसंबर, 2017 को जारी की गई विश्व आर्थिक स्थिति तथा संभावनाएं (डब्ल्यूईएसपी) 2018 की रिपोर्ट के अनुसार, वैश्विक वित्तीय संकट से संबंधित कमजोर अर्थव्यवस्थाओं के रूप में विश्व अर्थव्यवस्था मजबूत हुई। 2017 में, वैश्विक आर्थिक विकास 3 प्रतिशत तक पहुंच गया, जो 2016 में 2.4 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में एक महत्वपूर्ण वृद्धि है - जो 2011 के बाद से उच्चतम विकास दर है। यह भी अनुमान लगाया गया कि आने वाले वर्ष में विकास स्थिर रहने की उम्मीद थी।

भारत का आर्थिक विकास

भारत के आर्थिक विकास हेतु इस वर्ष की शुरुआत अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) के साथ हुई थी, जिसमें वित्त वर्ष 2016-17 में भारत के विकास के पूर्वानुमान को 16 जनवरी, 2017 को इसके पहले के अनुमान 7.6% के मुकाबले 6.6 प्रतिशत तक सीमित कर दिया था, जो कि उच्च मूल्य वाली मुद्राओं के विमुद्रीकरणके सरकार के कदम के कारण था। हालांकि, संशोधित अनुमान 2016-17 में सांख्यिकी विभाग द्वारा 7.1% की वृद्धि के अनुमान के अनुरूप था, जो पिछले वर्ष 7.6 प्रतिशत था। यद्यपि 2016-17 में भारतीय अर्थव्यवस्था धीमी हो गई, सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में 2015-16 में 8 प्रतिशत से घटकर 7.1 प्रतिशत रही, यह वर्ष 2017 में दुनिया की दूसरी सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बनी रही।

व्यापार संतुलन

उत्पाद व्यापार के संदर्भ में, अप्रैल-दिसंबर 2017-18 के लिए निर्यात का संचयी मूल्य 226712.58 मिलियनडॉलर (1441419.91 करोड़ रुपये) था, जो पिछले वर्ष की समान अवधि में 199467.14 मिलियन डॉलर(1338341.51 करोड़ रुपये) था, जो डॉलर में 12.05 प्रतिशत की सकारात्मक वृद्धि और रुपए में 7.70 प्रतिशत की वृद्धि है।अप्रैल-दिसंबर 2017-18 में आयातों का संचयी मूल्य 277899.32 मिलियन डॉलर(1865151.87 करोड़ रुपये) केपिछले वर्ष की इसी अवधि के मुकाबले

338369.63 मिलियन अमेरिकी डॉलर (2182289.84 करोड़ रुपये) था, जो डॉलर के संदर्भ में 21.76 प्रतिशत की सकारात्मक वृद्धि और रुपये के संदर्भ में 17.00 प्रतिशत की वृद्धि थी।अप्रैल-दिसंबर 2017-18 में व्यापार और सेवाओं को एक साथ मिलाकर, अप्रैल-दिसंबर 2016-17 के दौरान35626.18 मिलियन डॉलरकी तुलना में अप्रैल, 2017-18 में कुल व्यापार घाटा70063.05 मिलियन डॉलरअनुमानित किया गया था।

एफडीआई और विदेशी मुद्रा

भारत में संचयी एफडीआई प्रवाह (अप्रैल, 2000 से सितंबर, 2017 तक), इक्विटी प्रवाह, 'पुनः निवेशित आय' और 'अन्य पूंजी'सहित 518,100 मिलियन डॉलर थी। 2017-18 (अप्रैल-सितंबर) में कुल एफडीआई (इक्विटी इनफ्लो) 25,354 मिलियन डॉलर था। 22 दिसंबर, 2017 को कुल विदेशी मुद्रा भंडार 404,921.8 मिलियन अमेरिकी डॉलर था।

बहुपक्षीय और क्षेत्रीय संस्थान

संयुक्त राष्ट्र महासभा का 72वां सत्र

संयुक्त राष्ट्र महासभा (यूएनजीए72) का 72वां सत्र 12 सितंबर, 2017 को संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में आयोजित किया गया था। सामान्य बहस 19 सितंबर, 2017 को 'लोगों पर ध्यान केंद्रित करना: शांति और सतत ग्रह पर सभी के लिए सभ्य जीवन के प्रयास'विषय पर केंद्रित थी। अन्य गणमान्य व्यक्तियों में, महासभा को भारतीय विदेश मंत्री, सुषमा स्वराज ने भी संबोधित किया। उन्होंने आतंकवाद, जलवायु परिवर्तन, सतत विकास और अन्य जैसे मुद्दों पर ध्यान केन्द्रित कराया।

11वां डब्ल्यूटीओ मंत्रिस्तरीय सम्मेलन

ग्यारहवां डब्ल्यूटीओ मंत्रिस्तरीय सम्मेलन (एमसी 11) 10-13 दिसंबर, 2017 को अर्जेंटीना के ब्यूनस आयर्स में आयोजित किया गया था। इसकी अध्यक्षता अर्जेंटीना की मंत्री सुसाना मालकोररा ने की थी। 11 अक्टूबर को मंत्रिस्तरीय घोषणा के बिना या आम सहमति के अभाव में कोई ठोस परिणाम के बिना समाप्त हो गया। सम्मेलन मत्स्य पालन सब्सिडी और ई-कॉमर्स शुल्कों और सभी क्षेत्रों में वार्ता जारी रखने की प्रतिबद्धता सहित कई मंत्रिस्तरीय फैसलों के साथ समाप्त हुआ। एमसी11 के दौरान, भारत विश्व व्यापार संगठन के मूल सिद्धांतों पर अपने रुख पर कायम रहा, जिसमें बहुपक्षवाद, नियम आधारित सहमति से निर्णय लेना, स्वतंत्र और विश्वसनीय विवाद समाधान और अपीलीय प्रक्रिया, विकास की केंद्रीयता, सभी विकासशील देशों के लिए अंतर उपचारजो डीडीए, और विशेष को रेखांकित करता है, शामिल है।

नाफ्टा की पुन: वार्ता

18 मई, 2017 को, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प ने नाफ्टा की पुनः वार्ता के निर्णय की घोषणा की और 17 जुलाई, 2017 को, यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव (यूएसटीआर) के कार्यालय ने यूएस नाफ्टा के उद्देश्यों को पुन: प्रकाशित किया। 2017 के अंत में, पांच दौर की वार्ता संपन्न हुई। 16 से 20 अगस्त, 2017 तक

वाशिंगटन, डीसी में पहले दौर की वार्ता हुई; 1 से 5 सितंबर, 2017 तक मेक्सिको सिटी में दूसरी; तीसरी 23-27 सितंबर, 2017 को ओटावा में; 11-17 अक्टूबर, 2017 को वाशिंगटन डी.सी. में चौथी; 17-21 नवंबर, 2017 को मैक्सिको सिटी, मैक्सिको में पांचवीं वार्ता हुई। नाफ्टाके पुन: वार्ता प्रक्रिया को पूरा करने की प्रारंभिक समय सीमा दिसंबर 2017 थी। पहले पांच दौरों के रूप में, समझौते पर पहुंचने के लिए संघर्ष किया गया, फिर से बातचीत की प्रक्रिया को 2018 की पहली तिमाही तक बढ़ाया गया था।

43वांजी7 शिखर सम्मेलन

जी7 देशों के नेता 26-27 मई, 2017 को आयोजित 43वें जी7 शिखर सम्मेलन के लिए इटली के टारमिना में एकत्रित हुए। जी7 देशों के नेताओं ने गंभीर वैश्विक चुनौतियों का सामना करते हुए, आर्थिक और राजनीतिक प्रकृति सहित कई मुद्दों पर चर्चा की। शिखर सम्मेलन के अंत में, जी7 देशों के नेताओं ने टोरामिना लीडर्स कम्युनिक्स को अपनाया। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राज्य अमेरिका और जी7 देशों के बाकी देशों के बीच मतभेद थे।

जी20 शिखर सम्मेलन

जी20 के नेता 7-8 जुलाई, 2017 से हैम्बर्ग में एकत्रित हुए। शिखर सम्मेलन का विषय "शेपिंग ए इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड" था, जिसमें तीन उद्देश्यों की खोज में शिखर सम्मेलन के परिणामों को रेखांकित करते हुए संयुक्त कम्युनिटी के साथ एकजुट होना, जो लचीलापन बना रहे, स्थिरता में सुधार और जिम्मेदारी संभालने वाली हो। बैठक के दौरान नेता व्यापार, वित्त, ऊर्जा और अफ्रीका पर प्रतिबद्धताओं के साथ संवाद पर आम सहमति पर पहुंचे। लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प और समूह के 19 अन्य सदस्यों के बीच जलवायु परिवर्तन पर मतभेद थे। व्यापार पर भी, शिखर सम्मेलन में 'समझौता' हो गया और जलवायु परिवर्तन पर20 में से 19 नेता सहमत स्थिति पर पहुंचे।

आई.ओ.आर.ए.समिट की बैठक

हिंद महासागर तटीय सहयोग संघ (आई.ओ.आर.ए.) ने 7 मार्च, 2017 को जकार्ता, इंडोनेशिया में नेताओं की पहली शिखर बैठक जकार्ता में आयोजित की। शिखर सम्मेलन का विषय "शांतिपूर्ण, स्थिर और समृद्ध हिंद महासागर के लिए समुद्री सहयोग को मजबूत करना" था। शिखर सम्मेलन के दौरान, आई.ओ.आर.ए.दूरदर्शी दस्तावेज, "शांतिपूर्ण, स्थिर और समृद्ध हिंद महासागर के लिए क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देने" पर जकार्ता कॉनकॉर्ड पर हस्ताक्षर किए गए थे, जिसमें छह प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर प्रकाश डाला गया था। इनमें समुद्री सुरक्षा और बचाव; व्यापार और निवेश सुविधा; मत्स्य प्रबंधन; आपदा जोखिम में कमी; शैक्षणिक और एस एंड टी सहयोग; और पर्यटन संवर्धन और सांस्कृतिक आदान-प्रदानशामिल हैं।

15वीं बिम्सटेक मंत्रिस्तरीय बैठक

15वींबिम्सटेक (बंगाल की खाड़ी बहु-क्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग उपक्रम) मंत्रिस्तरीय बैठक 10-11 अगस्त, 2017 को नेपाल, काठमांडू में आयोजित की गई। बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, भारत, म्यांमार, श्रीलंका और थाईलैंड के उप विदेश मंत्री ने बैठक में भाग लिया। बैठक बिम्सटेक की 20वीं वर्षगांठ की पृष्ठभूमि में हुई। मंत्रिस्तरीय बैठक में काठमांडू, नेपाल में 7 फरवरी और 10 अगस्त, 2017 को आयोजित क्रमशः बिम्सटेक के वरिष्ठ अधिकारियों की सत्रहवीं और अठारहवीं सत्रों की रिपोर्टों को मंजूरी दी गई। मंत्रीमंडल की बैठक में सहयोग के सोलह क्षेत्रों पर सहमति हुई।

एशिया-प्रशांत आर्थिक सहयोग (ए.पी.ई.सी.) शिखर सम्मेलन, 2017

एशिया-प्रशांत क्षेत्र के 21 देश 6-11 नवंबर, 2017 को एशिया-प्रशांत आर्थिक सहयोग (ए.पी.ई.सी.) शिखर सम्मेलन के लिए वियतनाम के दा नांग में एकत्र हुए। वियतनाम द्वारा आयोजित शिखर सम्मेलन, "नया गतिवाद बनाना, साझा भविष्य को बढ़ावा देना" पर केन्द्रित थी।शिखरसम्मेलनकेदौरानबैठकोंकीश्रृंखलाआयोजितकी गई, जिसमें 8 नवंबर को XXIX मंत्रिस्तरीय बैठक और 11 नवंबर को XXV ए.पी.ई.सी.आर्थिक नेताओं की बैठक शामिल है।21ए.पी.ई.सी.सदस्य अर्थव्यवस्थाओं के नेताओं ने ए.पी.ई.सी.आर्थिक नेताओं की बैठक के बाद दा नांग घोषणा जारी की।दा नांग घोषणा में सहयोग के चार क्षेत्रों की पहचान की गई: क) टिकाऊ, अभिनव और समावेशी विकास; ख) क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण और कनेक्टिविटी; ग) सूक्ष्म, लघु और मध्यम आकार के उद्यमों (एमएसएमई) के लिए गतिशीलता; और घ) खाद्य सुरक्षा एवं स्थायी कृषि प्राप्त करना।

17वां एससीओ शिखर सम्मेलन, अस्ताना, कजाखस्तान

शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) के 17वें शिखर सम्मेलनका आयोजन 9 जून, 2017 को कजाकिस्तान के अस्ताना में हुआ। इस शिखर सम्मेलन के अंत में, कुल 11 दस्तावेजों को अपनाया गया। शिखर सम्मेलन के दौरान, राष्ट्राध्यक्षों ने भारत गणराज्य तथा इस्लामिक गणराज्य पाकिस्तान को पूर्ण सदस्यता देने की ऐतिहासिक प्रकृति को रेखांकित किया।

9वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन, ज़ियामेन, चीन

ब्राजील के संघात्मक गणराज्य, रूसी संघ, भारत गणराज्य, पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना और दक्षिण अफ्रीका गणराज्य के नेताओं ने 4 सितंबर, 2017 को चीन के ज़ियामेन में नौवें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में "ब्रिक्स: मजबूत भविष्य के लिए मजबूत भागीदारी" विषय के तहत मुलाकात की। शिखर सम्मेलन के अंत में, ज़ियामेन घोषणा को अपनाया गया था। नौवें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के पूर्ण सत्र के दौरान भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आग्रह किया कि ब्रिक्स देश सौर ऊर्जा एजेंडा को मजबूत करने हेतु अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (आईएसए) के साथ मिलकर काम कर सकते हैं, क्योंकि पांच देशों के पास अक्षय और सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने का पूरक कौशल और क्षणता हैं।उन्होंने टिप्पणी की कि ब्रिक्स देश लाभ के परिणामों हेतु साझेदारी को गहरा कर सकते हैं। उन्होंने संयुक्त पहल में युवाओं को मुख्यधारा में लाने और कौशल विकास तथा सर्वोत्तम प्रथाओं के आदान-प्रदान में सहयोग बढ़ाने; इनोवेशन और डिजिटल इकोनॉमी पर मजबूत ब्रिक्स की साझेदारी से विकास में मदद,

पारदर्शिता को बढ़ावा देने और सतत विकास लक्ष्यों का समर्थन करने; और कौशल, स्वास्थ्य, बुनियादी ढांचे, विनिर्माण और कनेक्टिविटी के क्षेत्रों में ब्रिक्स और अफ्रीकी देशों के बीच अधिक केंद्रित क्षमता निर्माण कार्य की दिशा में काम करने पर जोर दिया।

शोध अध्येता जिन्होंने वार्षिक समीक्षा के लिए सामग्री में योगदान दिया 2017

क्षेत्रवार

क्षेत्र / देश	शोध अध्येता
दक्षिण एशिया	
अफ़ग़ानिस्तान	डॉ, स्मिता तिवारी, डॉ. अम्बरीन आगा और डॉ. धुबज्योति भट्टाचार्जी
बांग्लादेश	डॉ. आशीष शुक्ला
नेपाल	डॉ. राकेश कुमार मीणा
पाकिस्तान	डॉ. धुबज्योति भट्टाचार्जी
श्रीलंका और मालदीव	डॉ. समथा मल्लेम्पति
दक्षिण पूर्व / पूर्व एशिया / सुदूर पूर्व	
दक्षिण - पूर्व एशिया	डॉ. तम्जेनमेरेन एओ और डॉ. समथा मल्लेम्पति
उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया और जापान	डॉ. जोजिन जॉन
मध्य एशिया	डॉ. अतहर ज़फर
पश्चिम एशिया	
सऊदी अरब, फिलिस्तीन, कुतर, इज़राइल, ओमान और जॉर्डन	डॉ. जाकिर हुसैन, डॉ. एफ.आर. सिद्दीकी और डॉ. धुबज्योति भट्टाचार्जी

ईरान	डॉ. आसिफ शुजा
तुर्की	डॉ. उमेर अनस
अफ्रीका (उत्तरी, पूर्वी, पश्चिमी, दक्षिणी और उप-सहारा)	
उत्तरी	डॉ. फज़ूर सिद्दीकी
पूर्वी, पश्चिमी, दक्षिणी और उप-सहारा	डॉ. निवेदिता रे, डॉ. सौरभ मिश्रा और डॉ. चरणिका डेका
हिंद महासागर द्वीप राज्य	डॉ. अमित कुमार
लातिन अमेरिका और कैरेबियन	डॉ. स्तुति बनर्जी
उत्तरी अमेरिका	डॉ. स्तुति बनर्जी
	प्रमुख शक्तियाँ
चीन	डॉ. संजीव कुमार
अमेरीका	डॉ. स्तुति बनर्जी
रूस	डॉ. इंद्राणी तालुकदार
यूरोपीय संघ	डॉ. दीनोज उपाध्याय
बहुपक्षीय और अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक विकास	डॉ. अरुंधति शर्मा

संयुक्त रूप से

डॉ. निवेदिता रे, डीआईआर (आर) और डॉ.ध्रुबज्योति भट्टाचार्जी, आर.एफ., आई.सी.डब्ल्यू.ए.

द्वारा

संकलित और संपादित